साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
Phone : +91 731 2015827

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 11 अंक 32 प्रति सोमवार इंदौर, 20 से 26 मार्च 2017 पृष्ठ 12 मूल्य 2/- रुपए

सेवाकर, स्वच्छता शुल्क, सेट टॉप बॉक्स से लूट के बाद, ई-भुगतान के नाम से लूट

नगदीहीन व्यवस्था से जनता से हर वर्ष रुपए 200 लाख करोड़ लूटेंगे

भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिसने 25 से 35 वर्ष की उम्र में संघ कार्यालयों में झाड़ू लगाई और सेवा चाकरी की, बाद में चाय बैची, ठेले पर, दिन फिरे और पहले मुख्यमंत्री रहा फिर पूंजीपतियों और अमित शाह जैसे धूर्त की सहयोग और धूर्तता से प्रधानमंत्री बन गया, एम.कॉम की झूठी डिग्री का बखान अवश्य किया गया परंतु वह 8वीं, 10वीं पास नहीं, यदि होता तो सहपाठी कहीं से तो आवाज उठाते, स्वाभाविक है गंजे को नाखून मिल गए देश को नोंच मारा, फिर मंचों से घोषणा भी कि मैं तेली जाति का हूं, तो देश की जनता का पिछले ढाई वर्षों में ही हर तरह से तेल निचोड़ रहा है। जो भाजपा विपक्ष में रहकर कुछ सेवाओं पर 2.5 से 5 प्रतिशत का विरोध करती थी उसके सत्ता पिपासु दानव मोदी ने बिजली, पानी, फोन, यात्रा, रेलवे, विमान यात्रा, आदि सभी सेवाओं पर 5 से 15 प्रश तक का सेवाकर ठोककर महंगाई बढ़ा जनता को लूट का खुला तांडव किया। प्रधानमंत्री बनते ही उस चाय बेचने वाले, अपने आपको फकीर कहने वाले इस ढोंगी को अपारखेड़ी वाचाल ने जनता का रुपए 50 लाख करोड़ विदेश यात्राओं में लुटाया, खूब विदेशी प्रसार माध्यमों से छाये रहने और हजारों की संख्या भी इकट्ठा करने और तालियां ठुकवाने में हजारों करोड़ बर्बाद किया, रुपए 25 लाख के सूट पहने और नंगे-भूखों के तन से

कमाई पूंजीपतियों और बैंकों को कार्ड या ऑनलाइन लेन-देन से, न 24 घंटे बिजली न अंतरजाल की गति, न सुरक्षा, जो लूटे उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं, दुनिया में रुपए 26000 अरब की डकैती नेट और कार्ड बैंकिंग पर, हैकर्स के मकड़जाल में दुनिया

रोटी कपड़ा छीन अय्याशी और मौज-मस्ती की। विदेश यात्राओं का जब चारों तरफ विरोध होने लगा, आलोचनाओं का अंबार छपने लगा तो जनता से लेकर रुपए 1.50 से 2.00 लाख का वेतन पाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में झाड़ू थमाकर सफाई की नौटंकी कर जनता के दिलो दिमाग से अपनी लूट-डकैती और मौज-मस्ती की सफाई में लगा दिया। दूसरी तरफ सफाई के नाम पर 80 प्रश रकम नगर निगम के आयुक्तों, महापौरों, पार्षदों से लेकर गावों के पंचों, सरपंचों, सचिवों द्वारा डकारे जाने के भ्रष्टाचार को दूर करने की अपेक्षा उल्टे ही जनता पर स्वच्छता कर थोपकर, लाखों करोड़ की बर्बादी और भ्रष्टाचार के नए रास्ते खोले गए, पूरे देश के नगर निगमों, पालिकाओं में सफाई की मशीनों वाहनों को 10 से 20 प्रश मोटे कमीशन पर खरीद एक तरफ अपने धूर्त मित्र रतन टाटा की कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया तो दूसरी तरफ हजारों करोड़ के कमीशन नगर निगमों,पालिकाओं, जनपदों से लेकर पंचायतों के नेताओं अधिकारी कर्मचारियों को सांड बनाकर डकारने, पेट्रोल-डीजल में सीधा 25 से 50 प्रश चोरी का झूठे बिलों से हजम करने के नए रास्ते खोले गए, मीडिया चिलाए नहीं इसलिए उसे भी हजारों करोड़ के विज्ञापन लगातार बांटे गए। शौचालयों के निर्माण में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत देश की 62000 पंचायतों से लेकर मु. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास मंत्री तक हजारों करोड़ हजम कर लिए गए, बात यहीं तक नहीं थमी एक तरफ सफाई के नाम हर सेवा और **(शेष पेज 5 पर)**

आखिर दो महत्वपूर्ण बजट एक साथ पेश क्यों हुए

न जालसाजियां समझ आए, न विपक्ष धज्जियां बिखेरे

56 इंच सीना अपनी जालसाजियों, चालबाजियों, नाकामियों से सिकुड़ा, कहां गया सीमा पर आतंकवाद खत्म करने का मुद्दा, नोटबंदी से बेरोजगारी आदि पर विपक्ष के सामने करने से भयभीत, बजट में किसानों को कर्ज अनुदान समाप्त की तैयारी। नगदीहीन लेन-देन रुपए 200 लाख से रुपए 300 लाख करोड़ तक की लूट की व्यवस्था

नई दिल्ली की सत्ता संभालते ही अपने बाप की जागीर समझ जनता के धन से 40 से ज्यादा देशों में गुलछर्रे उड़ाने, अय्याशी करने और अपने आकाओं के लिए जन धन का रुपए 50 लाख करोड़ से ज्यादा बर्बाद कर अंबानी, अडानी, टाटा व अन्य पूंजीपतियों के लिए ये गुजराती दल्लों की भूमिका निभाने गया था, जब देश में चारों

तरफ इसकी धज्जियां उड़ाई जाने लगी, और सब थू-थू करने लगे तो बंदे ने सबका मुंह बंद करने सबको हाथ में झाड़ू थमा दी ताकि जनता से लेकर सभी नेताओं, पार्टियों और प्रधान, मुख्य, सचिवों, जिलाधीशों जिन्हें जन-धन से जो जनता से करों में, पेट्रोल डीजल के दुगुनी तिगुनी कीमत पर बेंच 80 प्रतिशत तक विभिन्न कर वसूल कर लूटा जाता है। दी जाने वाली प्रतिमाह लाखों का वेतन दिया जाता है। से सारे प्रशासनिक व अन्य महत्वपूर्ण कार्य छुड़वाकर झाड़ू लगवाई जा रही है। जब इसकी ये नौटंकी चल रही थी अचानक रुपए 500 व 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की लाइन में मौत हुई तो वहीं 100 से ज्यादा बैंककर्मी नोट बंदी बदलवाने के बोझ के चलते हुए मौत हो गई, इन सब पर जब संसद में बहस का मौका आया तो कभी किसी कारण कभी किसी कारण संसद के सत्र बाधित हुए और टाले गए, **(शेष पेज 5 पर)**

राष्ट्रपति ट्रंप बहुराष्ट्रीय कंपनी का दुनिया को नोचो का खेल बिगाड़ो

क्षेत्रीय विकास वाद का ट्रंप, विश्व के गरीबों को लाभप्रद

बहुराष्ट्रीय कं. का षड़यंत्र-ट्रंप का विरोध, शोषणकारी षड़यंत्र का जाल नष्ट होना ही चाहिए

अमेरिकी में चुने गए नए राष्ट्रपति ट्रंप के रूसी संबंधों को लेकर आम अमेरिकी जनता में संशय की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, दूसरी तरफ गैर अमेरिकी नागरिकों और अप्रवासी अमेरिकी नागरिकों में भी नौकरी, धंधे, व्यवसाय को लेकर भी भारी संशय और स्थायित्व को लेकर आसन्न संकट नजर आने लगा है। इसके विपरीत सच यह भी है कि अनेकों भारतीय व एशियन ट्रंप की टीम में शामिल हैं। ट्रंप ने अपने चुनावपूर्व भाषणों में, वैश्विक व्यापार संगठन जो कि बहुराष्ट्रीय कं. का गिरोह है, जिसका मूल उद्देश्य है

कि विश्व के अन्य राष्ट्रों के प्राकृतिक व मानव निर्मित संसाधनों को कब्जाकर अपने मोटे लाभ के लिए प्रयोग में लाने के लिए विश्व व्यापार संगठन का नाटक तैयार कर सभी बड़ी जनसंख्या, प्राकृतिक साधनों यथा जलवायु, खनिज, नदियां, कृषि, मिट्टी की उर्वरता, मौसम आदि पर अपने एकाधिकार के लिए वहाँ की सरकारों, मंत्रियों, नेताओं को खरीदकर दबाव डाल, ऋण, रिश्वत आदि के दम पर अपने मनचाहे कानून बनवाकर डकैती डालना था। जैसा कि भारत में 1992 में इन्हीं धूर्त कं. अमेरिकी व युरोपियन कं. यथा वालमार्ट, मेकडॉनल्ड व अन्य के इशारे पर तात्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंहराव की कनपट्टी पर बंदूक रखकर विश्व व्यापार संगठन के कानूनों पर हस्ताक्षर करवाए गए, क्योंकि भारत जनसंख्या के हिसाब से एक बड़ा व लालची पढ़े लिखे मूर्खों का 100 करोड़ की आबादी का बाजार होने के साथ ही यहां का निश्चित मौसम उर्वरा मिट्टी, भरपूर कृषि फसलें, बिजली पानी की अपार संभावनाओं वाला राष्ट्र था, वहीं हाल चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि का था, साथ ही ब्रितानी हुकुमत के वे सभी देश जिन पर ब्रिटेन ने राज्य किया था।

(शेष पेज 6 पर)

मप्र बजट 17-18, कमाई वालों को ज्यादा, कम कमाई वालों को कम आवंटन

आंकड़ों की बाजीगरी में, जनता से लूट, भ्रष्टाचार में धन हजम करने की पूरी छूट

मप्र का बजट 28 फरवरी 17 को 12वीं बार भ्रष्ट व जालसाज व आपराधिक प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री शिवराज में वित्तमंत्री जयंत मलैया ने प्रस्तुत किया। स्पष्ट था कि जनता से लूटे गए बेइंतिहा करों से कमाई वाले विभागों को ज्यादा धन आवंटित किया गया। अधो संरचना व्यय में, जल संसाधन को 16-17 में रुपए 6784 करोड़ था, 17-18 में रुपए 7943 करोड़ आवंटित, नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्रा. को 16-17 में रुपए 2065 करोड़ रुपए 7314 करोड़, 17-18 में आवंटित, 40 प्रश हजम कर लिया जाएगा। ग्रामीण विकास प्र.ग्रा.स.यो. 16-17 में रुपए 2831 करोड़ से बढ़ाकर 17-18 में रुपए 3707 करोड़ नगरीय प्रशासन व पर्यावरण में 16-17 में रुपए

जन-धन लुटाकर मीडिया का मुंह बंद किया, लूटतंत्र में सत्ता में रहने लूट ले अब काहे पछतायेगा, प्राण जाएंगे छूट, अगले चुनाव की तैयारी को ध्यान में रख बस सीधी गैस की कीमत बढ़ाई, बिजली की लूट में कीमतें भी बढ़ाई, बजट भी बढ़ाया, फिर भी कर्ज की तैयारी

364 करोड़ से बढ़कर 842 करोड़, 17-18 में आवंटित लो.स्वा.यां. में पेयजल आपूर्ति में रुपए 2832 करोड़ से बढ़कर 17-18 में रुपए 3796 करोड़ ऊर्जा में 16-17 में रुपए 2347 करोड़ से बढ़कर 17-18 में रुपए 2901 करोड़ ये पूरा धन हजम करेगा। जनस्वास्थ्य क्षेत्र व्यय लो. स्वा. व परिवार कल्याण में 16-17 में रुपए 4887 करोड़ से 17-18 में रुपए 5673 करोड़ आवंटित 50 प्रश सीधा हजम 30 प्रश डॉक्टर हजम करेंगे, 10प्रश जनता स्वास्थ्य में खर्च होगा, चिकित्सा शिक्षा में 16-17 में रुपए 846 करोड़ से बढ़ाकर 17-18 में रुपए 1367 करोड़, जबकि प्रदेश में रुपए 5200 डॉक्टर अर्थात रुपए 25 लाख में भी एक डॉक्टर नहीं मिलता, 50 प्रश पैसा हजम, व्यापमं का सबसे बड़ा अपराधी जिसके संरक्षण में 2006 से कांड चल रहा था, महिला बाल विकास में 16-17 में रुपए 4046 करोड़ बढ़ाकर 17-18 में रुपए 4315 करोड़ आवंटित 80 प्रश भ्रष्टाचार में हजम। **(शेष पेज 7 पर)**

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

घुटन से होगा विस्फोट

वर्तमान मोदी सरकार जिस तरह से पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन जनता को निचोड़ने, बांधने और लूटने में लगे, पहले नोटबंदी फिर केशलेस में पहले करोड़ों को बेरोजगार किया, फिर केशलेस बनाकर 90 लाख से 300 लाख करोड़ की लूट की योजना बनाकर जिस 100 करोड़ आम आदमी का दम घोंटा जा रहा है। ये घुटन पूंजीवादी शोषण, जालसाजियों से चुनाव जीतकर पूंजीपतियों की शरण गच्छामी हो आम 100 करोड़ का गला घोंट कंकाल बनाने की तैयारी की जा रही है। सोवियत रूस की तरह देश को खंड-खंड बांटने, परमाणु युद्ध की विभीषिका झेलने की और या फिर प्राकृतिक आपदाओं में नष्ट करने की कामना करने लगे आम आदमी और फिर दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों का बर्बादी का कहर झेलना पड़ जाए। नोटबंदी से उपजे आक्रोश का भले ही इस गुजराती दानव ने मीडिया को हजारों करोड़ के जनधन की करों से लूटी रकम से भले ही प्रदर्शन न होने दिया हो पर देश का 90 प्रश मोदी अंबानी और जेटली की अकाल मृत्यु की कामना कर रहा था, क्योंकि आम आदमी जो खुली मजदूरी छोटे-मोटे धंधे से कमाई कर रहा था, इन जैसे तो 40 करोड़ लोगों को सारा धंधा पानी बंद कर नोट बदलने की लाइन में खड़ा था और पूछ रहा था कि ये मोदी राक्षस और जेटली कब मरेंगे, दूसरी ओर मोदी ने स्वयं स्वीकारा कि मुझे लोग मार डालेंगे, मेरी हत्या कर देंगे, आखिर क्यों इतना भयभीत होना पड़ा? फिर मोदी की किस्मत ने साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड 120 डॉलर से गिरकर 30 डॉलर हो गया पर इस डकैत ने अपने बापों को पूरा पेट्रोलियम मंत्रालय गिरवी कर दिया, जिस पेट्रोल को रुपए 20 प्रति लीटर बिकना चाहिए था उसने रुपए 65 से कम नहीं होने दिया। अभी जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50-55 डॉलर की कीमत के क्रूड की कीमत जिसमें 160 ली. क्रूड आता है। रुपए 80 वसूल रहे हैं, ये भुखेरा जनहितभक्षी पार्टी का मु.मं. और प्र.मं. इन दुष्टों की लूट कारवां अब जबकि यूपी जैसा बड़ा प्रदेश जालसाजी से जीत लिया है तेजी से बढ़ेगा, अब हर लेन-देन में 3 प्रश की वसूली करने के साथ हर खरीद बिक्री व लेन-देन पर भी नजर रख सके, घोंटिये 100 करोड़ लोगों को गला। नीच कसाइयों उनका रक्त पीकर और काया का मांस नोंचकर उन्हें नर कंकाल, लगाइये जीएसटी अपने गुजराती अंबानी, अडानी आकाओं के साथ चंदा देने वाले टाटा बिरला जैसे चंद अरबपतियों को खरब पति वसूलिए चंदा, हजम नहीं हो रही आम आदमी की समृद्धि, बैंकों से लुटवाइये, फिर भी बच जाए तो नेट बैंकिंग से हैकरों से डाके डलवाइये, फिर भी बच जाए तो घर पर आयकर वालों को भेजिए, खड़ाकर दीजिए नंगा भूखा बनाकर 40 करोड़ की सड़क पर, नीच गिद्धों रोजगार देना तो तुम्हारी फितरत नहीं, पर रोजगार छीनिये, नोटबंदी से चमड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य उद्योग में परिवहन व्यवसाय के 40 लाख ट्रकों को तरलता की कमी से, ऑटो व्यवसाय के आदि में दो माह तक कारोबार ठप्प रहा। 10 करोड़ से ज्यादा सीधी, 40 करोड़ तक अप्रत्यक्ष रूप से 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज रहे, फिर भी मीडिया प्रशंसा की धन लेकर बांसुरी बजाता रहा, छापे की खबरों सुनाता रहा और ये गुजराती 4 दूष्ट जनता के कष्टों पर मुस्कुराते रहे, वैसे ही जैसे बंटवारे के समय मोहन दास करमचंद गांधी हिंदूओं का कत्लेआम देखकर भी हिंदूओं की चीख-पुकार सुनकर भी भाग रहे थे, फिर मेक इन इंडिया के नाम सारे विमान, निर्माण हथियार बनाने के सारे ठेके अंबानी फर्मों का ही दिए जा रहे, 40 से ज्यादा विदेश यात्राओं में ये हरामखोर यथार्थ में अपने इन बापों अंबानी, अडानी, टाटा आदि के लिए बड़े-बड़े सौदे करके लाया जिसमें अडानी के लिए स्टेट बैंक से कर्ज दिलाकर आस्ट्रेलिया की समुद्र किनारे की कोयला खदानों का ठेका लेकर आया जिसका वहां की जनता भारी विरोध कर रहर है। जिससे वहां की मूंगे की समुद्री चट्टानों को खतरा पैदा हो गया, यथार्थ में हर सेवा यथा रेलवे, बिजली, पेट्रोल, डीजल गैस आदि की जनता से लूटे रुपए 50 लाख करोड़ बर्बाद कर अपने पूंजीपति आकाओं का शासकीय प्रतिनिधि होने के बाद भी व्यावसायिक दूत का काम कर रहा था, चुनावी वादों को भी मोदी और उसका शार्गिक अमित गंजा गिरगिट की तरह रंग बदल पलटी मार बोलता है कि हमने कोई वादा नहीं किया था, क्या हुआ आतंकवाद खत्म हो गया, महंगाई कम हो गई शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और निजी कं. की लूट बंद हो गई, उल्टे ही आतंकवाद, महंगाई, भ्रष्टाचार और जालसाजियां बढ़ने के साथ सरकारी लूट और बेरोजगारी बढ़ गई, लाख मीडिया के टूकड़खोर श्वान भांडो की तरह तारीफ करें, पर गरीब मध्यमवर्गीय का जो दम घोंट रहा है उसका विस्फोट होगा, जनता की इसी घुंटन का परिणाम थी हमारी हजारों साल की गुलामी, तब भी सजे राजवाड़े अपनी मौज-मस्ती में मस्त रहते थे, जनता घुंटकर उनकी बरबादी की कामना करती थी। जिससे आक्रांताओं को आसानी से राज्यों पर न केवल विजय मिल जाती थी वरन घुटती हुई जनता उन आक्रांताओं का स्वागत भी करती थी। स्व. इंदिरा गांधी व राजीव गांधी इतने बड़े इन जैसे पूंजीपतियों के पिछे लग्गू नहीं थे फिर भी कुछ नीतियों ने जनता का गला घोंटा परिणाम स्वरूप उनकी हत्या कर दी गई। पर ये धूर्त सुधरने को तैयार नहीं ये जनता को घुटने दे। खुद भी शहीदों की सूची में शामिल होने को बेताब है।

24×7 दिन बिजली नहीं, इंटरनेट स्पीड नहीं, जालसाजियों पर लगाम नहीं, सुरक्षा नहीं, अपना कुछ भी नहीं, विदेशी सायबर गुलामी की जिद, कमाई के लिए

केवल पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कं. के लाभ के लिए, आधार कार्ड, पेन कार्ड की अनिवार्यता

भाजपा बनाम भुखेरा जन पार्टी, सत्ता में आते ही देश और देश की जनता को लूटने नोंचने और बर्बाद करने पर तुल गए क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं, कल सत्ता रहे या न रहे, इसलिए सत्ता संभालते ही लाखों रुपए के सूट, जो चाय की कमाई से पहनने की तो दूर देखे भी नहीं थे, पहनकर विश्व भ्रमण पर निकल गए। रुपए 50 लाख करोड़ की बर्बादी पर हल्ला मचा तो स्वच्छ भारत की झाड़ू थमा दी। फिर सर्जिकल स्ट्राइक का शिगूफा छोड़ा वो भी फुस्सी बम साबित हुआ, थू-थू होने लगी तो नोटबंदी कर नगदीहीन अर्थव्यवस्था का शिगूफा छोड़ा, यहां पर भी बिना आधार भूत तैयारी ने करोड़ों को बेरोजगार करने के साथ यह भी गले की फांस बन गया

विश्व में भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में मोदी जैसे का प्रधानमंत्री बनना शायद आंधुनिक विश्व की सबसे बड़ी दुर्घटना सिद्ध होगी। जिस व्यक्ति ने 35-40 की उम्र तक किसी संगठन के कार्यालयों में झाड़ू लगाई और चाय बेची हो, उसका मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना बेशक अनहोनी तो है ही, पर इसके बाद जो हो रहा है, उसये देश की जनता झेलने और 130 करोड़ जनता का भविष्य गर्त में धकेलने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होती। होगी भी क्यों जो पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह छिपाकर केवल अपनी मौज मस्ती और ऐशो-आराम, घूमना फिरना ही जिंदगी समझता हो, जिसे अपनी तीन तेरह और नौ अठारह करने से ही फुर्सत न मिली हो, जिसने स्कूल-कॉलेज का मुंह न देखा हो, स्वाभाविक है जैसा उसे हांका और नचाया, समझाया जाएगा, वह वैसा ही करेगा, फिर गुजराती मानुष महाजालसाज, ठगोरा, सब्जबाग दिखाकर वसूली करना उनके रक्त का गुण है। मोदी जिसका साक्षात जाली प्रमाण है। उसके क्या मतलब कि देश कें अनेकों राज्यों में 24 घंटे इंटरनेट तो दूर बिजली घर को प्रकाशित करने के लिए नहीं मिलती, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तो ठीक मप्र में जहां कुल उपयोग 10 हजार मेवा की अपेक्षा 20000 मेंवा का उत्पादन होने के बाद भी इंदौर जैसे शहर में दिन में 3-4 बार आधा से 1-2 घंटे तक चली जाती है तो फिर सारे देश की जनता के लिए हर शासकीय कार्य आधार कार्ड से, पेन कार्ड से जोड़ना, जबकि न तो पूरा सायबर संचालन का स्वयं की संरचना व साधन, हर जानकारी भारत के चापे की पूरी दुनिया जिसमें पाकिस्तान, चीन जैसे शत्रु राष्ट्रों के साथ नाइजीरिया जैसे जालसाज लोगों के हाथ में पहुंचाकर आखिर मोदी सरकार क्यों आम नागरिकों को पूर्णतः असुरक्षित बनाना चाहती है। पर धूर्त मक्कार को इन सबसे कोई मतलब नहीं उसे तो जबकि हर दिन देश की विविध 55000 से ज्यादा बैंक शाखाओं से रुपए 1000 करोड़ से ज्यादा की डकैती डाली जाती है। 90 प्रश बैंक शिकायतें सुनने और लेने को ही तैयार नहीं होते उल्टे ही ग्राहकों को ही डरा-धमकाने के साथ मारापीटी तक करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा और घोर बत्तमीज होते हैं। स्टेट व इनके सहयोगी बैंकों के कर्मचारी अधिकारी जो स्वयं भी सैकड़ों प्रकार की जालसाजियों लूट और हेरा-फेरी में स्वयं ही शामिल भी होते हैं। इसके विपरीत रिजर्व बैंक जो बैंकरों का बैंक होने के साथ जालसाजों का महाजालसाज सरकारी गिरोह है का लोकपाल की साइट पर स्पष्ट लिखा होता है। बैंकों के कर्मचारियों को मारपीट की शिकायतें नहीं ली जाएगी।

अब धूर्त प्रधानमंत्री की इच्छा है कि आधार कार्ड से आपका फोन, मोबाइल नं., बैंक खाता, गाड़ी नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस आदि सब जोड़ दिए जाये अर्थात किसी भी व्यक्ति जो ठग है जालसाज है उसे गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, मोबाइल नं., ड्राइविंग कुछ भी मिला तो तत्काल सारी जानकारी घर या कहीं भी बैठकर आसानी से निकालकर, आधार कार्ड की प्रति निकाल सारे बैंकों के खाते खालीकर देते है। फिर यह कार्य देश में ही नहीं विदेशों में बैठकर भी आसानी से अंजाम दिये जा रहे हैं। पर हमारी सरकार के मुखिया मोदी से लेकर नीचे थानों तक किसी को भी कोई चिंता तो दूर वरन सायबर अपराध की तो बहुत दूर थानों में अपराधिक प्रकरणों की 90 प्रश शिकायतों की एफआईआर तो दूर आवेदन लेकर कचरे की टोकरी में डाल दिये जाते हैं। इंदौर जैसे शहर में ही दम-खम वाले पीड़ितों की सायबर डकैती 5000 से ज्यादा शिकायतें लंबित पड़ी हुई है। अरबों रुपए खर्च करके जो जन-धन के थे सायबर थानों के भवन, कम्प्यूटर्स व अन्य साधनों की व्यवस्था के बाद भी कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंजिनियर्स, सायबर व दूरसंचार व वेव विशेषज्ञ इंजिनियरों के स्टॉफ की तो दूर, पुराने कला, वाणिज्य व अन्य विषयों के उत्तीर्ण स्नातकों को जो भारतीय व राज्य पुलिस सेवा से चुनकर आए हैं। उन्हीं को इन थानों की कमान सौंप दी जाती है यदि इंजीनियर छात्र हर्षिल जैन पिता रा.न. जैन जो हैकिंग आदि में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। पुलिस की निगाह में आ जाते हैं। तो पुलिस अधिकारी उनका बड़े-बड़े कामों यथा उच्च श्रेणी के मंत्रियों, अधिकारियों, व्यवसायियों के स्विस बैंकों के खातों की जानकारी निकलवाकर उनसे वसूली करते हैं। जब ऐसे युवा प्रतिभाशाली छात्रों से इन पुलिस अधिकारियों का मतलब निकल जाता है तो उन्हें छोटे-मोटे मामलों में उलझाकर सालों जेलों में सड़ाकर भविष्य बर्बाद कर देते हैं। ऐसे अपराधियों के मामले में हर कदम पुलिस अपनी बत्तमीजियों का परिचय देते हुए मामले को अटकाकर सालों जमानत तक नहीं होने देते। ऐसी घटनायें बताती हैं। सरकारी लूटतंत्र की जनता को सायबर अपराधों से सुरक्षा दिलाने मंशा, जो केवल कागजी घोषणाओं के दम पर आबंटित धन को हजम करने और जनता के साथ देश भर में हर दिन होती रुपए 1000 करोड़ से ज्यादा की लूट का यथार्थ, हाल ही पकड़े गए जासूसी कांड जिसमें आईएसआई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के जाल में धन इकट्ठा करने और खुफिया सेना की जानकारी भेजने वालों के पास 3000 से ज्यादा सिम पकड़ी गई। स्वाभाविक है कि इन 3000 के बैंक खातों से जिनके नामों की सिम होगी पैसे भी साफ किए गए होंगे।

मोदी की नोटबंदी ने करोड़ों को बेरोजगार बना दिया, स्वाभाविक है युवा पीढ़ी जो घंटों इंटरनेट पर बैठती है, आसानी से किसी का मोबाइल नंबर या घर के पते से कोई भी सेवा केन्द्र पर बैठकर आधार कार्ड का नंबर निकालेगी या निकालती है, मोबाइल नंबर निकालती है, आधार कार्ड नंबर लेकर जाती है, मोबाइल गुमने की शिकायत देकर नई सिम निकालती है या सिम की दूसरी प्रति की कॉपी तैयार करती है, पहली 20-25 मिनिट के लिए ब्लॉक करती है। खाते में पड़ा पैसा साफ करती है और बैंक से आया संदेश देखती है। बाद में क्लोन सिम निकाल, नष्ट करती है और पुरानी पुनः चालू कर देती है। संबंधित जब पैसा ग्राहक की सिम से ही निकाला गया है, ई वॉलेट, ई पेमेंट या मोबाइल से आधार कार्ड और बैंक खाते को जोड़ने का खतरा केशलेस में जिस कार्ड से भुगतान जहां-जहां किया है, हर विक्रेता के खाते में आप केवल लाखों के नंबर संग्रहित हो गए हैं। अब उस कार्ड के नं. का भी क्लोन बनाकर ठगी हुई है और होती रहेगी, और ये ठगी जब चीन, पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों से होती है तो सरकार भी ऐसे शत्रु राष्ट्रों से ऐसे सायबर अपराधियों को पकड़ने या पैसा वसूल करने के लिए कुछ नहीं कर पाती, जबकि ऐसी ठगी विश्व के किसी भी कोने से की जा रही है। क्योंकि इंटरनेट का मूल केन्द्र तो अमेरिका के पास है। भारत में की गई ठगी तो दूर प्रत्यक्ष लूट, मारापीटी ठगी व अन्य गंभीर किस्म के अपराधों तक में उसकी कोशिश रहती है कि फरियादी को चलता कर दिया जाए तो फिर आईटी एक्ट में जालसाजी, ठगी, खाते, खाली होने की शिकायत जिसमें 95 प्रश तक पुलिस के मुंशी, उपनिरीक्षक, सहा. निरीक्षक से लेकर थानेदार, सहा. नागरी, उप अधीक्षक तक को अब सद नहीं समझता तो आवेदन भी लेने को तैयार भी कैसे होंगे।

जासूसी कांड में पकड़े गए 11 जासूसों के पास 3000 सिम वह भी चालू दूसरों की नामों की अब हर किसी सिम पर आधार कार्ड, वोटर कार्ड भी लगे होंगे वो सब निर्दोष भी लपेटे में आएंगे कितनों के बैंक फर्जी खातों में जो लेन-देन हुआ होगा, कितनों पर ऋण ले लिए गए होंगे, कौन भुगतना अमेरिका से आप का चुनाव प्रसार कर सीधे ही दिल्ली में भाजपा को हराने के लिए सामाजिक साइटों पर संदेश भेजे गए, और भाजपा की सत्ता, धन, बल और सत्ता का रसूख लेकर भी कुछ नहीं कर पाई, तो ये आखिर आधार कार्ड का आधार हीन बनाने का ही कमाल ही तो था।

प्रधान मंत्री कार्यालय को सूचना के अधिकार में एक पत्र यह जानने के लिए दिया गया कि आखिर आधार कार्ड के चालू होने से लेकर अभी तक आधार कार्ड की बाध्यता के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय ने कितने फैसले दिए, दूसरा आपके केबिनेट मंत्रियों के आधार कार्ड के नं. क्या है। नोटबंदी के बाद प्र.का. से कितने आदेश और परिपत्र जारी किए गए, आदि बदले में प्र के सूचना अधिकारी ने पत्र को तीन अलग-अलग विभागों में पत्र अंतरित कर के पीछो छुड़ाने की कोशिश की गई, आखिर क्या जरूरत है सच को छुपाने की। ऐसा भी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के हर फैसले न केवल सर्वोच्च न्यायालय की साइट पर हर फैसले की जानकारी होने के साथ ही हर फैसले की प्रति प्र.मं. कार्यालय को जाने के साथ ही भारत के लाखों समाचार पत्रों में छपती हैं। फिर जनता पर दबाव डालकर आधार कार्ड बनवाने के लिए हर षड़यंत्र रचा जा रहा है। राशन कार्ड, ईंधन गैस, बैंक खाते, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि सभी उसी से जोड़े जाएंगे। ठीक है, सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार को काले धन को बिना आयकर भुगतान के लेन-देन पर कड़ी चौकसी लगाकर दोनों हाथ हर कदम पर वसूली की जाए, इसके विपरीत स्वयं मोदी उसका धूर्त सहयोगी अमित शाह व अन्य भाजपाई नेता स्वयं गिरेबां में झांके और देखें, कि स्वयं कितने ईमानदार हैं। चुनाव आयोग की संसद के चुनाव खर्च की सीमा रुपए 70 लाख है, स्वयं और पूरे भाजपाई सांसदों ने रुपए 100 से 1000 करोड़ तक खर्च किए और हिसाब दिए मात्र रुपए 70 लाख तो फिर शूकरों की ये फौज पूरे देश को कैसे ईमानदार बनाने की या निष्कर्ष में लूटने और मेहनत के पैसे की छीनने के लिए कदम-कदम षड़यंत्र क्यों और कैसे रच रही है। दो नंबर का पैसा कमाने के लिए भी मेहनत करना पड़ती है, आसमान से नहीं टपकता, खेतों में पैसा कमाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। आसमान से नहीं टपकता, खेतों में नहीं ऊगता कोई घर बैठे मुफ्त में नहीं दे जाता, मात्र आयकर न देने पर कालाधन कह देने अपने बाप की जागीर नहीं।

दूसरी और हालात ये है कि चीनी सरकार व कं. आप की बाप है। वो साधारण से क्रियाकलापों पर न केवल बारीकी से हर इंटरनेट पर काम करने या उपयोग पर नजर रख रही है। हालात ये है कि इस देश में भी चीनी चुरकटों में माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर पर पूरी सेंध लगा रखी है। वह साइट खोलते ही चीनी भाषा के साथ इंग्लिश में भी खोलता है। गूगल, रिडिफ व अन्य अनेकों खोजी व ईमेल की साइटों को नहीं खोलने देता, जबकि भारत के विश्व की जानी मानी सॉफ्टवेयर कं. में कार्य करने भारतीयों की अच्छी खासी संख्यात्मक स्थिति होने के साथ ही भारत की सॉफ्टवेयर कं. भी विश्व में अच्छा खासा स्थान रखती हैं। पर भारतीयों का भारत में न केवल अपना कोई सर्च इंजन नहीं, वरन आम सामान्य दैनिक समाचार पत्रों को दैनिक उपयोग के लिए तत्काल के इतिहास में छापा चित्रों तक का गूगल से निकालकर चिपकाते हैं और सरकार की सारी एजेंसियों तक की अधिकांश जानकारियों, आधार कार्ड, किसी स्थान, मार्ग यहां तक कि अब तो गूगल मेप से कार्य विभागों की सड़कें, नालियां, बांध, टीपो शीट तक ली जा रही है। अर्थात सारी सूक्ष्मतम गोपनीय, स्तर की जानकारियां तक विदेशी सर्च इंजन गूगल, याहू आदि से खोजकर निकाली व ली जाती है। तो फिर क्यों भारत की सूचना प्रोद्योगिकी विभाग बिना पुख्ता सुरक्षा के, मात्र रुपए 1 लाख करोड़ से ज्यादा जिसमें 50 से 70 प्रतिशत पैसा भ्रष्टाचार और बंदरबांट में जन-धन का बर्बाद किया जाकर हर आम आदमी को असुरक्षा की गर्त में ढकेलकर आधार कार्ड बनाने के लिए मजबूर कर उसे आर्थिक, सामाजिक तौर पर आधारहीन बनाने में तुली है। रक्त पिपासु दानव मोदी की जिद।

कानून धूर्तों के बनाए शब्दों के जाल, जो अपनों के पोषण व निरीहों के शोषण के काम आते है

भारतीय न्याया., सत्ताधीशों और पूंजीपतियों की रखैल, जुए के अड्डों से बदत्तर

भारत की वर्तमान न्याय प्रणाली यथार्थ में अंग्रेज धूर्तों की भारतीय गुलामों को हांकने, जोतने और अपनी तरह से शोषण करने की व्यवस्था थी, जो वर्तमान में भी 99 वर्ष के पट्टे पर हस्तांतरित सत्ता, जो विशुद्ध रूप से 70 वर्ष बाद भी यथा स्थिति में आम भारतीयों के लिए लागू हो संचालित की जा रही है। निंसदेह हर मनुष्य पहले एक आम मनुष्य है, जो भय, काम, क्रोध, मद, मोह, माया, लोभ की मानसिकता लिए हुए मंत्री, सर्वोच्च, उच्च न्यायालयों से लेकर जिला एवं सत्र न्यायालयों तक के न्यायाधीश हों, या अन्य किसी राजकार्यों में बैठे शिखर से शिला पर बैठे हर अधिकारी कर्मचारी सभी उन दुर्गणों से ग्रसित हो अपनी आजीविका संचालित करते हैं। यह सर्वकालिक कालजयी सिद्धांत है, जो मनुष्य योनि के प्रारंभ से अंत तक समान रूप से विद्यमान रहेगा, शास्त्रों में वर्णित देवों और दानवों में भी यह दुर्गण काम ज्यादा आवश्यक थे तो फिर मानव कैसे अछूता रह सकता है। यथार्थ में कानून जो मनुष्यों की सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए शासकों द्वारा बनाए गए थे व बनाए जाते हैं वे सभी शासक, उनके सलाहकार, मंत्री, कानूनविद सभी महाधूर्त, चालाक होने के साथ ही जनता को कैसे निचोड़ना, नियंत्रित करना और अपने और अपनों को कैसा, फायदा पहुंचाना है, इसके ध्यान में रखकर, ही बनाए जाते हैं। या संक्षिप्त में कानून धूर्तों के बनाए शब्दों के मायावी सत्ता तंत्र हैं,जो अपने के पोषण और निरीहों के शोषण के काम आते हैं। जिसका अनुभव विधिवत्ताओं, सत्ताधीशों और बुद्धिजीवियों से लेकर आमजन भी करने लगा है। फिर 15 वर्ष पूर्व, भूतपूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने राष्ट्रीय मंच से स्वीकार किया था कि न्यायालय न्याय के मंदिर जुये के अड्डे, जो जितना धन खर्च करेगा उतना न्याय धारित करेगा, जिसके उदाहरण हर वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के सैकड़ों प्रकरणों में निर्णयों सिद्ध होता है। जैसा कि हाल ही में व्यापमं घोटाले में आया निर्णय सिद्ध करता है कि सबसे कमजोर कड़ी छात्रों को जो 634 थे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से बाहर निकाल दिया गया, परंतु इस जालसाजी, भ्रष्टाचार लूट और दलाली के प्रकरण में प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, धर्मपत्नी साधना सिंग, सभी शासकीय अधिकारी जिसमें अनेकों इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के इंडियन (क्राइम) प्रोटेक्शन सर्विस के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाता, बड़े मंत्री, नेता जिनका एसटीएफ की सूची में था, निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के मालिकों यथा विनोद भंडारी, जो कि भोपाल कारागृह में वर्षों गुजार चुके थे, कैसे और क्यों बच गए इसके विपरीत सैकड़ों विद्यार्थियों के साथ उनके माता-पिता व संरक्षकों को आर्थिक मानसिक, सामाजिक प्रताड़ना के साथ कईयों की मौत, हत्या और आत्महत्या से तबाही हुई उनके सारे जिम्मेदार

भू.पू. राष्ट्रपति के आर नारायणन-न्यायालय न्याय के मंदिर नहीं जुए के अड्डे

मोटा धन खर्च करके बचा लिए गए, वह सारा धन आखिर भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज ने जन-धन का ही खर्च किया, सर्वोच्च न्यायालय ने मात्र दोषी विद्यार्थियों को ही मान सजा दे दी जबकि अधिकांश दलाल, व्यापमं के अधिकारियों से लेकर परीक्षा केन्द्रों के संचालनककर्ता, गिरोह के सदस्यों, संचालकों आदि अनेकों के बारे में चुप्पी साध ली।

दूसरी तरफ पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय 1997 से अब तक अनेकों फैसलों को दे चुका है। फिर एक देश, एक सर्वोच्च न्यायालय, एक कानून, एक संविधान होने के बाद भी उन्हीं फैसलों के विरुद्ध वहां के पंजीयक अनेकों याचिकाएं स्वीकार की जाती है और उनकी सुनवाई भी अनेकों तारीखों पर तारीखें विभिन्न कारणों को लेकर बढ़ाई जाती है। जबकि उन्हीं निर्णयों के आधार पर दूसरे राज्यों में कार्यवाही भी हो चुकी है। परंतु मप्र सरकार जन-धन के करोड़ों रुपए वकीलों की फीस पर कार्यवाही में कुछ ऊपर से कुछ नीचे खर्च कर तरीखें बढ़वाने में सफल हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ लाखों कर्मचारियों अधिकारियों 30-35 वर्ष में एक भी पदोन्नति मिले बिना सेवानिवृत्त हुए जा रहे हैं। उनका ख्याल किसी को नहीं आता। यह देखकर कि जो हाल उसके माता-पिताओं का हुआ है, सरकारी धन जो कि जनधन से अनाप-शनाप करों में वसूला गया था से पढ़ लिखकर विदेशों में प्रतिभायें पलायान कर उन राष्ट्रों की समृद्ध और सिंचित कर रही हैं। 2017-18 में मप्र शासन के हर विभाग में 80-90 के दशक में भर्ती किए 60 प्रश कर्मचारी-अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 80-90 प्रतिशत आरक्षित वर्ग के अधिकारी रह जाएंगे क्या मप्र सरकार को सर्वोच्च न्यायालय निर्देशित करेगा कि सामान्य वर्ग के 50 प्रश की सीमा को पूरा करने के लिए उनकी भी भर्ती बेकलाग पद्धति से करें। जैसा कि बेकलॉग से आरक्षित वर्ग की भर्ती क़ी गई। यदि बारीकी से न्यायालयों की घोंघा चाल से चलने वाली प्रक्रिया को नीचे से लेकर ऊपर तक देखा जाए तो ये अपराधियों के संरक्षण का भी हिस्सा बन चुकी है, जबकि न्याय सैद्धांतिक किताबी भाषा में जो विधि के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है कि एक निर्दोष को बचाने 100 अपराधी बच जाए, परंतु निर्दोष को सजा न मिले, परंतु भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में वास्तविकता में एक अपराधी को बचाने में 100 निर्दोषों की जान जा रही है। हजारों बेगुनाह जेलों में सड़ रहे हैं। पर पुलिस प्रशासन न्यायालयों को इसकी चिंता के विपरीत संवेदनाहीन हो अपनी गुलामों को अपनी पद्धति से हांकते और चलाने के लिए सत्ताधीशों और पूंजीपतियों के इशारे पर चलने को मजबूर है। सत्ताधीश, पूंजीपति कितना ही बड़ा अपराधी हो, उसके हितों का संरक्षण कानून की अंधी गलियों में किया ही जाएगा जिसका सबसे बड़ा उदाहरण सलमान खान है। जिसे निचली अदालतों ने, उच्च न्यायालय ने दोषी करार दिया पर सर्वोच्च न्यायालय के बरी करने के फैसले ने भूतपूर्व राष्ट्रपति और भारत के प्रथम नागरिक स्व. के.आर. नारायण के कथन न्यायालय न्याय के मंदिर नहीं जुए के अड्डे हैं, पर यहां तो हालात जुए के अड्डों से भी बदत्तर सिद्ध कर दिये।

अधिकांश विधि वेत्ताओं, अधिवक्ताओं के बीच बैठ, या निकट बैठ उनके समूह के आपसी वार्तालाप को निचले न्यायालयों के परिसरों से चलकर उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के परिसरों तक सुनिये। 90 प्रतिशत अधिवक्ताओं के बीच आपसी चर्चा का एक ही मुद्दा होता है किस फैसले में कितना लेन-देन भ्रष्टाचार और दलाली की गई, क्या अन्याय हुआ, यह तथ्य न्यायालय परिसरों से लेकर जिला दंडाधिकारी अर्थात जिलाधीश, उप जिलाधीश, सहा. जिलाधीश और तहसीलदारों के राजस्व न्यायालयीन प्रकरणों में भी खूब गूंजता है। अंतर इतना सा है कि उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता कम व धीरे और सटीक बोलकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं।

फिर न्यायाधीश की कुर्सी पर आरुढ़ होने से पहले और बाद में वे सब भी हैं, तो आम साधारण मनुष्य जिन्हें सरकार नियुक्त करती है, जनधन से वेतन देती है, सुविधायें पदस्थापना, पदोन्नति, स्थानांतरण विधि मंत्रालय के अधीन ही होते हैं। विधि मंत्री कोई बहुत बड़ा कानूनविद नहीं वरन वही नेता होता हैं, जिनमें 90 प्रश का कोई पुराना अपराधिक इतिहास होता है, जैसे वर्तमान में गोपाल भार्गव फिर नेतागिरी करने के लिए गिरोह पालना होता है। स्वाभाविक है गिरोह के मुखिया को धन की आवश्यकता होती है तो जब विधि मंत्री का ही ये चाल चरित्र होगा तो कैसे विधि और विधायी साफ-सुथरी होगी स्वाभाविक है कि जुये के अड्डों से बदत्तर होगी। अब राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए स्व. आर.के. नारायणन इससे नीचे शब्द तो प्रयोग में नही ला सकते थे, फिर भारत में वो इतिहास गवाह रहा है कि सभी प्रधानमंत्रियों ने राजधर्म, राष्ट्रधर्म नहीं केवल वोट धर्म निभाया है, तो मोदी और शिवराज जिन श्रेष्ठियों का पैसा खाकर पले-बड़े, वोट धर्म निभाने के लिए स्वयं उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय अपनी ही सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के संवैधानिक समानता के हितों का बलात्कार कर पेशियां बढ़वाने में जन-धन बर्बाद कर अधिकांश कर्मचायिों-अधिकारियों की सेवानिवृत्ति का इंतजार कर रहे है।

नोटबंदी से मौत और परेशानी, मीडिया सपने दिखाने में मस्त रहा

मीडिया के टुकड़खोर श्वानों को विज्ञापन, जनता यथार्थ से वंचित

जनता के लूटे धन से हजारों करोड़ के 2 से 10 पेज तक के विज्ञापन बांट, जनता की परेशानी को छुपाया, आपराधिक भांडों ने अपराधियों और डकैतों के महानायक बनाने का ठेका ले रखा है

भाजपा उर्फ मुखेरा जन पार्टी जनता से पेट्रोल, डीजल गैस आदि में 32 प्रश एक्साइज के साथ 2 प्रश शिक्षा सेस, 2 प्रश स्वास्थ्य सेस, 2 प्रश सड़क, 2 प्रश इंफ्रा, 0.5 प्रश स्वच्छता के नाम और रुपए 10 प्रति घन लीटर की गैस जनता के रुपए 75 प्रली का पेट्रोल, 65 का प्रली डीजल और रुपए 35 प्रति घन लीटर की शासकीय स्तर पर बिक्री कर रही है। इसके बाद पेट्रोल डीजल में 25 से 50 प्रश की मिलावट और 10 से 30 प्रश तक तौल में मारकर जनता को रुपए 20 से 40 प्रति लीटर की चोट पेट्रोल पंपों पर पहुंचाई जा रही है। इस चोट से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के मंत्री से लेकर खाद्य नियंत्रक, खाद्य अधिकारी, निरीक्षक नाप तौल निरीक्षकों आदि सभी को महीना बांटा जाता है। इस पर दृष्य और श्रव्य व मुद्रित प्रसार माध्यम तो चुप्पी मारे ही है। जबकि जनता लूट रही हैं। कुछ भारत पेट्रोलियम के पंपों नोजल के पास जरूर कांच लगाया गया है। जिसमें पेट्रोल के रंग से गुणवत्ता और वाहनों की टंकी में पेट्रोल जाता हुआ आदि दिखता है। परन्तु दूसरे हिंदुस्तान व इंडियन ऑइल के पंपों पर अभी तक ऐसी व्यवस्था भी नहीं की गई पर मीडिया के टुकड़खोर श्वानों को जनता से लूटे धन से हजारों करोड़ के विज्ञापन बांट न केवल कराघानों और शासकीय ऊंची लूट के साथ पेट्रोल पंपों पर कम नाप और मिलावट से होने वाली लूट से रुपए 75 का पेट्रोल रुपए 100, 125 तक प्रति लीटर पड़ने के साथ प्रति किमी औसत मिलने की तो दूर देशी-विदेशी कं. की गाड़ियां के इंजन भी 10-20000 किमी चलने के बाद ही बिगड़ने लगते हैं। इस यथार्थ को भी दृष्य, श्रव्य व मुद्रित प्रसार माध्यमों से प्रस्तुत न कर न तो जनता को जागृत करने के लिए व प्रशासन व सरकार को मिलावट व कम नापतोल को रोकने के लिए जागृत किया, जो देश 80-90 प्रश पेट्रोल पंपों पर पिछले 50 वर्षों से चल रही है। मान लें कि 130 करोड़ की आबादी 130 करोड़ लीटर प्रतिदिन पेट्रोल खरीदती है, रुपए 20 की लूट से रुपए 2600 करोड़ की लूट प्रतिदिन देशभर में पेट्रोल पंपों पर हो रही है। प्रशासनिक अधिकारियों, खाद्य व नागरिक आपूर्ति कार्यालय जिला सहायक अधिकारियों, निरीक्षकों को प्रति माह रुपए 7.80 लाख करोड़ का मात्र रुपए 1 लाख करोड़ बांटकर, सब शांति से चल रहा है। ऐसे ही मोबाइल फोनों में रुपए 3 हजार करोड़ की लूट हर दिन होती है जनता से, पर मीडिया यहां भी चुप है। 50 वर्षों से ।

महाधूर्त, पूंजीपतियों के रखैल मोदी ने जिस तरह मीडिया को टुकड़े डाले अपने स्वपनिल वादों को प्रसारित कर जनता का और प्रशासन को झांसे में लेकर सत्ता हथियाई, फिर सत्ता में बैठेते ही 40 से ज्यादा विदेश यात्राओं में रुपए 50 लाख करोड़ से ज्यादा बर्बाद कर विदेशों में रुपए 25 लाख के जनधन से एक गरीब देश की जनता से नोचा गया था, कोट पहनकर अरबों रुपए के विज्ञापन वहां के मीडिया में बांटकर छपवाकर अपनी झूठी वाहवाही करवा तालियां पिटवाने में बर्बाद करने के कारण जो देश-विदेशों में हला मचा, और बदनामी होने लगी, तो देश की जनता को स्वच्छता के नाम झाड़ू पकड़ाकर और लाखों रुपए प्रति माह की जनधन से वेतन लेने वाले आ. प्रताड़ना सेवा बनाम आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस को झाड़ू लगवाई और जान बचाई, पर मीडिया के भांडों ने कभी यह नहीं पूछा कि रुपए डेढ़ लाख से ज्यादा का जनधन से वेतन लेने वालों को क्यों इस नौटंकी में घसीट क्यों प्रथम व उच्च श्रेणी के अधिकारिया, इंजीनियरों, डॉक्टरों को उनके मूल कार्य से विमुख कर झाड़ू लगवाने और सफाई करवाने की नौटंकी दिखाकर क्या सिद्ध करना चाहते है। मोदी के पहले पूरा देश गंदगी में ही जीवन यापन कर रहा था। मीडिया के मुखेरे भांडों ने नोटबंदी विरोध में देश के अनेकों क्षेत्रों में हुए हजारों लोगों, किसानों, मजदूरों के अलग-अलग प्रदर्शनों को भी नहीं दिखाया। नोटबंदी में सबसे ज्यादा बत्तमीजियां कालेधन को सफेद करने, करोड़ों की नेताओं, अधिकारियों की नगदी के बिना जनता में विनिमय किए सीधे ही बदला पर जनता को लगातार खदेड़ा जाता रहा, जिस मोदी ने केशलेस का शिगूफा छोड़ा, जिससे जनता के साथ प्रतिदिन रुपए 75000 करोड़ से लेकर रुपए 1 लाख करोड़ तक की लूट संभावित है। एक तरफ ये हरामखोर जालसाज मोदी जनता को निःशुल्क केशलेस सेवा देने की बात करता है दूसरी तरफ हर बैंक जिसमें स्टेट बैंक व अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के एक तरफ निजीकरण करने की जालसाजियां कर रहा है, तो दूसरी तरफ बैंकों में जमा और नगदी की निकासी या कार्ड से लेन-देन पर लगातार शुल्क बढ़ाने लगाने की छूट दे रहा है जबकि अभी तक जमा और निकासी मुफ्त थी, यही 99 प्रश बैंकर्स महाजालसाज होते हैं जो मोटा कमीशन और सुरासुंदरी भोग आंखभींच कर ऋण बांटते है। बदले में वर्तमान बैंकिंग परिस्थितियों का 40 प्रश अशोध्य ऋणों में परिवर्तित हो चुका है। बेशक यह बात भी सही है कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों जिनमें अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जेपी एसोसिएट्स, बड़े कॉलोनाइजर्स कुल बैंकिंग ऋणों का रुपए 50 लाख करोड़ से ज्यादा के ऋण है। जिसे ये धूर्त गुजराती मोदी माफ करने औश्र बदले में चुनावों के लिए लाखों करोड़ रुपए जो लिए गये थे उनको चुकाने और बैंकों को लाखों करोड़ रुपए का लाभ दिलाने के लिए जनता को लुटवाने के लिए कांड केशलेस पर 3 प्रश कमीशन, जमा निकासी पर रुपए 150 को न्यूनतम शुल्क वसूलने खाते में जमा राशि कम होने पर धन वसूलने का षड़यंत्र रच रहा है।

पर मीडिया के धूर्त इस जनता को लूटने वाले यथार्थ को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि 90 प्रश मीडियाकर्मी सड़कछाप और ब्लेकमेलिंग से पैसा कमाने वालों की फौज है, जो गले तक सुरा सुंदरी को शौकीन और मुफ्त के धन को हजम करने का आदि है। उसे जनता के भूत, वर्तमान और भविष्य से बिलकुल मतलब नहीं है। इसलिए उसे जो भी धन देगा वो इसके इशारों पर नाचेगा। इसके लिए वो विदेशों से धन मिलने पर जनहित तो दूर राष्ट्रहितों को भी बलाए ताक रख, जो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री जो अभी भी दाउद के इशारे पर पाकिस्तान से चलाई जा रही है फिर भी उन राष्ट्रद्रोही भांडों, नौटंकीबाजों, वैश्याओं जो दाउद और उसकी माफिया गैंग के इशारे पर नाचती है फिर भी मीडिया के बत्तमीज हमारी युवा पीढ़ी को 24 घंटों सातों दिन उनकी हर बत्तमीजी पूर्ण हरकतों और नौटंकियों को ऐसे परोसता है, जैसे वो नीच शूकरों की फौज देवी-देवता हो, इस दृष्य, श्रव्य मीडिया को जनता के साथ शासन-प्रशासन की लूट, विश्व में सबसे ज्यादा करारोपण कर वसूली, फिर उस पैसे को मनचाहे तरीके से अपनी कमाई के लिए दुरुपयोग कभी ये समाचार श्रृंखला में कमी नहीं दिखाती। पूरे प्रदेश और देश में नगर निगम और पालिकाएं बिना पूर्व उचित नियोजन के क्रांकीट सड़के बनाती है, फिर नालियों के लिए सड़कें फोड़ती हैं। फिर नालीयां बनाने के बाद फिर सड़के बनाती हैं। फिर तोड़ती है। फिर फुटपाथ बनाती है। फिर तोड़ती है बनाती है। इस प्रकार पूरे देश में नगर पालिकाओं और निगमों में बैठे पार्षदों से लेकर, कर्मचारी अधिकारी हर वर्ष लाखों करोड़ हजम कर जाते हैं। पूरे देश में बिजली कं. हर वर्ष लाखों करोड़ का खेल कर रही है। तेज मीटर लगाने अनाप-शनाप बिलिंग से जनता आत्महत्या कर रही है।

पर मीडिया के धूर्तों को इस सत्य को दिखाने की फुर्सत नहीं। उसे जनता से मतलब नहीं। उसे अपनी कमाई से मतलब है। मुद्रित समाचार पत्रों का भी यही हाल है। वे 5-10 पेज के विज्ञापन पाकर निहाल हो जाते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के जनता के साथ छल-कपट से लूट के यथार्थ बताने की अपेक्षा उनकी प्रशंसा ही परोसते हैं। जनता को भ्रमित करते हैं। बदले में मोटा धन वसूलते हैं। बेशक मीडिया भी पूंजीपतियों का गिरोह है।

साप्ताहिक समय माया

द्वितीय अपीलें सुनने की अपेक्षा आयुक्त डाँट फटकार रहे थे अपीलार्थीयों को मू.सू. आयुक्त, सूचना आयोग-आय-योगीयों का अड्डा

सभी सरकारी विभाग मजाक उड़ा रहे हैं, सूचना अधिकार का

जो सूचना देने का जिम्मेदार उन्हें ही अपीलीय अधिकारी बनाया जा रहा, सूचना आयुक्त कानून की निगरानी तो दूर धारा 4 का पालन नहीं करवा पाये, 12 वर्ष बाद भी, अरबों रुपए हजम कर गई सरकारें

केन्द्र सरकार में बैठी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने, भ्रष्टाचार नियंत्रण और पारदर्शिता के सूचना अधिकार अधि. 05 को 12 अप्रैल 2005 से लागू कर 6 माह के समय में कानून के पालन और प्रबंधन के लिए पूरे देश की राज्य सरकारों को हजारों करोड़ का बजट बनाके आवंटन दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, सभी उच्च न्यायालयों से लेकर जिला न्यायालयों तक केन्द्र व राज्य सरकार के सभी विभागों के आमजन के सरकारी कार्यों की जानकारी देने और जनधन का उपयोग संबंधी दस्तावेज देने की व्यवस्था की गई। हर विभाग में धारा 2 व 4 के अंतर्गत अलग से कक्ष बनाए गये। सभी विभागों को अरबों रुपए खर्च कर प्रशिक्षण दिया गया, जब कानून लगा तो सभी विभागों में भारी दहशत थी कि अब काला-पीला और मनमानी नहीं चलेगी, पर कानून बनने, लागू करने और 12 अक्टूबर 05 से जनता को जानकारी पाने का अधिकार देने के साथ, उसे भोथरा बनाने, बच निकलने जानकारी न देने के रास्ते स्वयं केन्द्र सरकार के जन कष्ट निवारण और पेंशन मंत्रालय शूकरों की फौज ने ही नए-नए परिपत्र जारी कर ऊपर से लेकर नीचे अंतिम छोर पर बैठे पंचायत कार्यालयों तक दिये जाते रहे हैं, इसके बलात्कार में न केवल सूचना आयुक्तों वरन उच्च व सर्वोच्च न्यायालय में बैठे न्यायाधीशों ने अपने व शासकीय विभागों की जानकारी और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए खुलकर उल्टे सीधे निर्णय दिये, जो भ्रष्ट और जालसाज अधिकारियों को अपने कुकर्मों और डकैती को छुपाने और जानकारी न देने के लिए मील के पत्थर बन गए। इसके साथ ही अधि. 05 में स्पष्ट व्याख्या और लिखे होने के बाद भी सरकार में बैठे मूर्ख टूकड़खोर मंत्रियों और धूर्त, शातिर इंडियन एव्यूसिंग सर्विस या भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों ने अपने आपको बचाने और लूट का पैसा पचाने के लिए ग्रामीण विकास वाणिज्यकर कृषि व अन्य विभागों में जिला लोक सूचना अधिकारियों व अन्य अधिकारियों के कार्यालयों में वरिष्ठों तक मामला न पहुंचे उनके सहायक बाबुओं, छोटे अधिकारियों को लोक सूचना और उन्हें स्वयं को अपीलीय अधिकारी बना दिया। अर्थात भ्रष्टाचार करो और बचने के लिए कां. यंत्री को, कृषि में उपसंचालक को, वाणिज्यकर में उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त को ही लोक सूचना अधिकारी से अपीलीय अधिकारी बना दिया, वही हाल जिलाधीश कार्यालयों में, जिलाधीश को, मुख्य अभियंता कार्यालयों अधीक्षण यंत्रियों कार्यालयों में, मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों में उनको स्वयं को ही अपीलीय अधिकारी घोषित कर अधिसूचना जारी कर दी गई। ताकि उनके कुकर्मों, भ्रष्टाचार, लूटपाट के बाद भी उनकी स्वयं की अपीलें वरिष्ठ न सुने, यही हाल केन्द्र सरकार के कार्यालयों में भी हुआ, हालात ये है कि ये शासकीय डकैतों की फौज खुलकर लूटपाट करती है। सूचना के अधिकार में पहले 5 वर्ष तक ही जानकारियां मिल जाती थी। पर अब जानकारियां देने की तो दूर अपीलों को लगाने पर स्वयं ही अपीलीय अधिकारी बन जाने के बाद वन विभाग, जिला पंचायत, कृषि जिलाधीश कार्यालयों, संभागीय कार्यालयों में आवेदन लेने में भी हरामखोर जालसाजों ने अपने आपको बचाने आधार कार्ड मांगना, कारध पूछना आवेदन लेने में अभी बाबू नहीं है, अभी साहब नहीं है। बिना पूछे नहीं लेंगे, जैसे इन सब हरामखोरों का बाप की जागीर हो जनधन और विभाग, और डाक से आवेदन भेजने पर न केवल जवाब नहीं देना, वरन् पंजीकृत डाक से भेजने या कोरियर जालसाज से अधिकारी साफ पलट जाते हैं। मिला ही नहीं आवेदन तो अपील किस बात की फिर शूकरों की फौज अपीलीय अधिकारी स्वयं ही न्यायाधीश और स्वयं लोक सूचना अधिकारी उल्टे ही अपने अधीनस्थों की तकालत भी करने लगते हैं और कमजोर आवेदक को डांटने, डपटने, धमकी देने मारने और हाथ-पैर तोड़ने तक की धमकी देते हैं। यह हाल 90 प्रश शासकीय विभागों में अधिकारियों का है। भोपाल स्थित या संभागों में स्थित मुख्यालयों में तो बैठे आयुक्तों, संचालकों को प्रमुख अभियंता कार्यालयों में आवेदनों के जवाब देना सीखा ही नहीं या फिर श्वानों की फौज एकमुश्त जवाब देती है कि पत्र हमारे कार्यालय से संबंधित नहीं बत्तमीज निकम्मों की फौज धारा 6 (3) में अंतरण भी नहीं करती। प्रथम अपीलीय चूंकि विभागीय होता है और अपने अधीनस्थों से महीना वसूलकर तो अपील की सुनवाई में वाणिज्यकर में तो प्रथा है कि वो प्रतिप्रार्थी को बुलाते ही नहीं, निर्णय भी सबकुछ गैर काननी होने पर भी स्वयं ही प्रतिप्रार्थी की तरफ से वकालत करते हुए अपीलें खारिज कर देते हैं।

कानून में स्पष्ट लिखा है कि ससम्मान आवेदनकर्ता को जानकारी प्रदान की जाये पर आवेदक को देखते ही हर विभाग के कर्मचारी अधिकारी घूरते और गुर्राते हुए देखते है। जैसे गिद्धों के घोंसले में कोई उनका उनसे बड़ा शत्रु आ गया हो, कैसे उस पर झपट कर बाधा दूर करें ताकि अपनी जनधन की नोंच खसोंट को देख जान व समझ लें। वरना अपना निवाला छीन ले जायेगा, बेशक देश में सूचना आवेदकों पर हमले हुए है हत्यायें कर दी गई है, फिर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मु.मं. शिवराज और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, वहां के अधिकारी तक सभी चाहते हैं कि वो जनता का खून पीते रहे खून पसीने की कमाई को करों, दरों से लूटते रहें। आधार कार्ड, बैंक खातों पर उसकी पूरी निगरानी हो कि आम आदमी एक पैसा भी इधर से उधर न रख सके न बीमारी के लिए न पढ़ाई के लिए न अपनी सुरक्षा, घर की जरूरतों के लिए, और ये गिद्धों की फौज लाखों करोड़ रुपए खर्च करके विदेशों में अय्याशी करें। मौज मनायें लाखों के सूट जनधन से पहनकर अपनी सेल्फियां लेते हुए अपने फोटो समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर चलाए इसीलिए ये भी इसे समाप्त करने की तैयारी में होने के साथ सूचना आयोगों में चापलूस दल्लों की फौज बैठाते हैं। जो घोर भ्रष्ट और सुविधाभोगी होने के साथ सरकार के इशारो पर नाचे चाहे वो केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्यों के सूचना आयोग में नियुक्तियों के लिए निर्देशित करें, फिर आयोग कोई सा भी हो, अपराधों को अत्याधिक विलंब से अपनी प्रक्रिया पूरी करें ताकि दोषियों को अधिकतम राहत मिले और जिसमें केडी खान पूर्व शासकीय अधिकारी हीरालाल त्रिवेदी भी पूर्व के अधिकारी रह चुके हैं। सू.आ. आत्मदीप और सुखराज सिंह भी मु.मं. के चहेते रहे हैं। इसलिए मात्र इन 4 को बैठाया गया है, जबकि वैधानिक तौर पर हर संभाग में एक अर्थात 10 सू.आ. और एक मुख्य सू.आ. होना चाहिए, ताकि द्वितीय व अंतिम अपीलों का निराकरण शीघ्र हो सके परंतु मु.म. धूर्त शिवराज कैसे चाहेगा कि उसके कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार का यथार्थ सामने आये, इसलिए जिन अपीलों का निराकरण तीन माह में होना चाहिए तो तीन-तीन वर्ष तक नहीं होती और सरकार की हार्दिक इच्छायें भी यहीं होती है।

इसलिए मात्र 4 आयुक्तों की नियुक्ति भर की गई। दूसरी ओर आवेदकों पर बड़ा अहसान करते हुए इंदौर में 28 जनवरी 17को इंदौर संभाग की अपीलों की सुनवाई रेसीडेंसी में की गई थी। मालूम पड़ा कि 90 प्रश अपीलार्थी को ये चाटूकार आयुक्तों की फौज डांट-फटकार कर भगा रही थी। पूछ रही थी कि तुम्हें क्यों चाहिए जानकारी। बार-बार जानकारी मांगते ही शासकीय लोगों का वक्त बर्बाद करते हों, जैसे इन हरामखोंर शूकरों की बैंक खाते की जानकारी देनी पड़ रही हो, या अपने ससुराल के रिश्तेदारों की जानकारी मांगी जा रही हो ऐसे बौखलाहटभरी बत्तमीजी पूर्ण तरीके से अपीलार्थी को बेइज्जत किया जा रहा है। इन जालसाजों ने शासन से कभी ये भी पूछ लिया होता कि पेट्रोल डीजल पर 31 प्रश पर कर के बाद भी रुपए 4 प्रति लीटर अधिक होकर देश में सबसे ज्यादा वूसली करने के बाद भी जनता के सिर रुपए 4500 करोड़ का कर्ज लेकर क्या किया। करों में लूट से पहले जनता से पूछा था कि हम कर, बिजली की दर बढ़ायें की नहीं, तो फिर हिसाब देने में क्यों जान निकल रही है। अमर फल खाकर धरती पर पैदा नहीं हुआ मोदी शिवराज या ये सूचना आयुक्त।

मु.मं. एक तरफ वन भूमि पर पट्टे बांटता है दूसरी तरफ अतिक्रमण हटाने को कहता है

वन विभाग में चारों तरफ भ्रष्टाचार का तांडव, हर स्तर पर

सू.अ. में अपीलों की कभी सुनवाई नहीं होती, किसी भी स्तर पर सब एक-दूसरे को बचाते हैं और जानकारी देने से टरकाते है

मप्र वन विभाग में निचले स्तर पर स्टॉफ की भारी कमी भी भ्रष्टाचार, अवैध कटाई,वन भूमि पर अतिक्रमण, वन प्राणियों का शिकार, अवैध उत्खनन, वनोपज का अवैध दोहन आदि अपराधों के बढ़ने का मूल कारण है जिसके वनापराध भी ढंग से पंजीबद्ध नहीं होते हैं। दूसरी तरफ अग्नि सुरक्षा, घास कटाई व अन्य वनोपज की बाले-बाले बिक्री, वनीकरण में 90 प्रश वृक्षारोपण का पैसा, जल व भूमि संरक्षण का आवंटन रात्रि निगरानी, मजदूरी, वन विकास, वन ग्राम विकास, नर्सरी में वृक्षों के बीजों से रोपणी विकास का धन, कागजों पर ही पूरा कर दिया जाता है। वन विकास व संरक्षण के नाम भक्षण होकर कर्मचारियों, अधिकारियों का विकास, सूचना अधिकार में जानकारी मांगने पर चक्कर कटवाये जाते हैं।

मप्र वन विभाग का मूल उद्देश्य वनों का विकास व संरक्षण है। इसके विपरीत वहां बैठे कर्मचारी व अधिकारी न तो कागजों और दस्तावेजों में दिखाए जा रहे फर्जी विकास के आंकड़ों का 50 प्रश भी ढंग से कार्य कर देते हैं और आत्मियता से पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ संरक्षण का कार्य संपन्न करते हैं। निंसदेह इसके पीछे प्रदेश के मुखिया चौहान की दो मुहीं नीतियां, घोर भ्रष्टाचार, लूट और जालसाजियों की नीतियों में मंत्री से लेकर नीचे तक गाहे-बगाहे कभी स्वयं के लिए तो कभी ऊपर वालों को खुश करने के लिए नीचे तक की श्रृंखला के बीट गई तक शामिल हो खुलकर भ्रष्टाचार का तांडव कर अवैध कटाई, वन भूमि पर अतिक्रमण अवैध उत्खनन, वन प्राणियों के शिकार, वनोपज की अवैध बिक्री को संरक्षण और शामिल होकर अपनी व वरिष्ठ अधिकारियों की तन, मन, धन से सेवा करते हैं। स्वाभाविक है, कर कदम-कदम हर कार्य में जिसको जैसा मौका मिलता है, अपने कौशल का पूर्ण सदुपयोग करता है, तो फिर निश्चित ही सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर हर कर्मचारी, रेंजर, उपसंभागीय, अधिकारी, वनमंडलाधिकारी अर्थात वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, प्रधान वन संरक्षक चाहे वो नियमित के हो, उत्पादन, वन्य प्राणी, सामाजिक वानिकी आदि किसी भी शाखा के हो से लेकर सचिव प्रधान सचिव मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सबको भयभीत करेगा, वो फिर क्यों जानकारी दी जाए, क्यो ये हरामखोरों की फौज अपीलों की सुनवाई करेगी और क्यों निराकरण करेगी।

इस विभाग में सन् 1984 तक एक महत्वपूर्ण पद वन भूमि के सर्वेयर का होता था, जो वन भूमि के नक्शे,अतिक्रमण, वन मार्गों के विकास आदि की निगरानी सूचना एकत्र करना, वरिष्ठ अधिकारियों को देना व अतिक्रमण आदि के विरूद्ध कार्रवाई करने की लिखा-पढ़ी करना आदि कार्यों को संपन्न करता था। वह इसीलिए ही समाप्त किया गया ताकि न केवल वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी वरन स्वयं राजस्व शासन भी स्वयं आसानी से वनभूमियों पर अतिक्रमण कर सके। अवैध उत्खनन कर सके, वन भूमि पर खेती करवाकर वनपाल से लेकर रेंजर तक सभी महीना वसूले और कागजों पर उस भूमि पर पौधारोपण, वृक्षारोपण दिखाकर हर वर्ष अरबों रुपए की प्रदेशभर में धन राशि हड़पी जाए। दूसरी तरफ ऐसी वनभूमियों पर अतिक्रमण करवाकर भूमियों के निवास व कृषि के पट्टे बांटकर अपना वोट बैंक मजबूत कर सके। इसमें बाद में राजस्व पटवारी, तहसीलदार, सहायक, उप व जिलाधीश तक भी ऐसी हजारों एकड़ जमीन की खरीदी बिक्री और कालोनी काटने में मोटी कमाई कर सकें इसके बाद भी वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी पूर्ण बेहोशी में रहे, क्योंकि उन्हें स्वयं ही ठोस व पक्की जानकारी नहीं कि कौन सी भूमि उनकी है और कौन सी राजस्व, नजूल, पंचायत व तहसील की है। इसके विपरीत सड़कों, तालाबों, नहरों व अन्य विकास कार्यो में वन भूमि प्राप्त करने के बदले, संबंधित विभागों से वन भूमि क्षतिपूर्ति बाजार दर से बदले में जमीन और उस पर वन विकास की पूर्ण राशि वसूली जाती है। चाहे वहां वन विकास की 90 प्रश राशि केवल दस्तावेजों पर विकास दिखाकर हजम कर ली जाती है। जैसा कि नर्मदा पर बने बरगी, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, मंडलेश्वर, सरदार सरोवर वृहत बांधों और उसकी नहरों के निर्माण में हुआ, हालात ये हैं कि कई बांधों और नहरों के निर्माण को ही वर्षों गुजर चुके हैं। जबकि क्षतिपूर्ति वनों का 25प्रश भी विकास नहीं हुआ है, यह हाल जबलपुर उसके आसपास के जिलों, इंदौर संभाग और उसके जिलों में इस तथ्य का सत्यापन किया जा सकता है। इन जालसाजियों में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का वन व पर्यावरण सदस्य जो कि वन विभाग का ही मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी से लेकर वन मंडलों के वनमंडलाधिकारी का ही मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी से लेकर वनमंडलों के वनमंडलाधिकारी से नीचे तक सारे कर्मचारी है। स्वाभाविक है पिछले 32 वर्षों में क्षतिपूर्ति वनों के नाम पर हजारों करोड़ रुपए की राशि कागजों पर ही वानों का विकास कर हड़प ली गई, जिसकी वास्तविकता का भौतिक सत्यापन यदि वन व पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली के माध्यम से करवाया जाए तो पिछले 30 वर्षों में हजारों भारतीय वन हड़पों के अधिकारियों से लेकर नीचे तक कर्मचारी इस भ्रष्टाचार के लपेटे में आ जाएंगे।

वन्य प्राणियों के मामले में भी स्थिति भयावह है। वन विभाग की 1991 में प्रकाशित बड़े वन प्राणियों यथा शेर व तेंदुओं की संख्या 1851 तेंदुंये और 927 शेर की बहानी यथावत 2016 में भी चल रही है। जिसकी वास्तविकता के बारे में समय माया ने 1979, 2003, 2006 में प्रकाशित कर दी थी जिससे इस विभाग के भेड़ियों को अमेरिकी डॉलर 2000 करोड़ जो विश्व वन्य प्राणी निधि से इन जानवरों के भोजन, पानी, संरक्षण आदि के लिए मिलता था मिलना बंद हो गया था, जो भारतीय रुपए में 1 लाख 20 हजार करोड़, एक लाख 40 हजार करोड़ तक होती थी केवल कागजों पर ही जो प्रधान वन संरक्षक, मंत्री और उसके स्टॉफ पूर्णतः फर्जी खर्च और रखरखाव दिखाकर हजम कर ली जाती है। जबकि वर्तमान में भी 250 से 300 शेर अधिकतम और 400 से 450 तेंदुयें से ज्यादा नहीं है। क्योंकि इन हरामखोंरों के भ्रष्टाचार के साथ ही स्वयं धूर्त पाखंडी मुख्यमंत्री की नीतियों के कारण इन 25 प्रश वर्षों में 40 प्रश तक वनों की धरा पर सफाया हो चुका है जिसमें सबसे ज्यादा जमीन,इंदौर संभाग में बने इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, सरदार सरोवर, मानजोबट आदि बांधों में ही डेढ़ लाख है। जमीन पर बसे जंगल डुबो दिए गए। स्वाभाविक था इस वन भूमि पर निवासरत प्राणियों का निवास खत्म होने के साथ भी सैकड़ों की संख्या शेर-तेंदुयें भी नष्ट हुऐ जब रहने को वन ही नहीं तो इनके सारे शेर तेंदुयें शायद मल्टीस्टोरी सरकारी कागजों की स्मार्ट बिल्डिंग में निवासकर विश्व वन प्राणी निधि से रोज हिरण, नीलगाय, सुअर, बंदरों आदि की चाइनीज डिशेज खाकर अपना परिवार बढ़ा रहे हैं। जिस दम भा.व.स. के भेड़ियें, 1827 तेंदुयें और 927 शेर दिखा पा रहे है। इसलिए कभी-कभी पिकनिक के इरादे से इंदौर के सांवेर रोड की फैक्ट्री में भोपाल, शिवपुरी व अन्य शहरों की बस्तियों सें घुसे ये तेंदुये जनता को अपने अस्तित्व का बोध करा रहे है। उतना सबकुछ पूरे प्रदेश में हर महीने में दो चार-बार घट रहा है। इसके विपरीत वन तो वन भूमि न वृक्षों व वन संपदा का अवैध दोहन अपनी कमाई के लिए मुख्य मंत्री चौहान, वनमंत्री से लेकर निचले स्तर तक बीट गार्ड तक सब अपने-अपने स्तर पर अपनी कमाई की व्यवस्था में हर कदम लगे हैं।

तानाशाहों को यथार्थ सुनने और पढ़ने से भारी डर लगता है, इसलिए

मोबाइलों की रिकार्डिंग, संदेश उड़ाना, झूठी प्रशंसा फैलाना

वाट्सएप, फेसबुक, ट्वीटर, मोबाइल से वार्तालाप करना, सिग्नल बंद करना भी करवा रही मोदी सरकार जनता के हजारों करोड़ खर्च करके

भारत की धरती ज्ञानियों, ध्यानियों, ऋषियों, मुनियों, देवताओं की उर्वरा रही हैं तो दानवों, धूर्तों, घोर स्वार्थी, मक्कारों, वाचालों और लफ्फाजों की भी उर्वरा रही है। स्पष्ट है कि इतिहास और वर्तमान इनसे भरा रहा है, तो स्वाभाविक है कि भविष्य भी इन्हीं से भरा रहेगा, उदाहरणों का आंकलन पाठक स्वयं कर सकते हैं। वर्तमान लोकतंत्र यथार्थ में भीड़तंत्र को साधकर सत्ता हथियाने और उसे अपने स्वार्थों के हित साधने, जनता को भ्रमित कर जनहित साधने का लालच देकर साधन बन चुके है।

स्वाभाविक है, छल, कपट, जालसाजियों से सत्ता हथियाकर जो भी सत्ता सुंदरी का वरण करेगा, उसके चारित्रिक गुणों में धूर्तता, मक्कारी चालाकी भरी होगी, उसे चाटूकारों की फौज ही पसंद आएगी, चाटूकारों को जो उसकी छल-कपटपूर्ण भाषा से मूर्खों की भीड़ को लुभा सके उन्हीं को पालेगा-पोसेगा। बेशक इस राष्ट्र के अज्ञानी, अनपढ़ों की वो ठीक यहां वैसे के पृथ्वी पर मानव आबादी के अन्य हिस्सों की अपेक्षा घोर, धूर्त, स्वार्थी लोगों की फौज होने के साथ 80 प्रश आबादी घोर ज्ञानी होने का भ्रम पालने के साथ घोर लालची और तात्कालिक लाभ के लिए सबकुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहती है। यही कारण इसकी सहस्त्रों वर्षों की गुलामी का कारण भी रही है। स्वाभाविक है कि सहस्त्रों वर्षों के गुलामों की मानसिकता 25-30 वर्षों में तो बदल नहीं सकती, न ही इन घोर ज्ञानी ध्यानियों को इतिहास से कोई सबक लेकर कुछ सीखने, समझने और भविष्य के दीर्घगामीं परिणामों को देखने की आवश्यकता है। सहस्त्रों वर्षों से विश्व के अन्य भूभागों में बसी मानव आबादियों को प्रकाश स्तंभ की भांति ज्ञान से प्रकाशित कर, मानव सभ्यताओं को गणित, भौतिकी, रसायन, आयुक्तों से इस श्रेष्ठ युग तक पहुंचाने वाले देश की जनता कितनी अज्ञानी है अंधी सोंच और लालची है, इसका अंदाजा यहां पर पिछले 67 वर्ष के लोकतंत्र में चुने गए नेताओं जो घोर धूर्त, मक्कार, अय्याश, लालची होने के साथ ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे है उनका सत्ता संभालकर 125 करोड़ लोगों को सुख समृद्धि और विकास की अपेक्षा बेरोजगारी और अवसाद देकर आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं।

सत्ता संभालने के पूर्व ही इस महाधूर्त, जालसाज नरेन्द्र मोदी अपने आकाओं से रुपए लाखों करोड़ इकट्ठे कर सारे दृष्य-श्रव्य व मुद्रित प्रसार माध्यमों पर रुपए लाखों करोड़ खर्च कर जिस तरह से अपने आपको महान जन, और राष्ट्रभक्त सिद्ध कर, भ्रष्टाचार मिटाने, विदेशों से काला धन लाने, महंगाई कम करने, आंतकवाद मिटाने, चीन और पाक की सीमाओं पर खदेड़ने, सबको रोजगार आदि जनमानस को उद्देलित करने वाले मुद्दों को सुलझाने वाला महानायक सिद्ध करने के लिए वर्तमान युग की संचार क्रांति पर चलने वाली फेसबुक, टवीटर,वाट्सएप को खरीदकर अपनी गुजरात के मुख्यमंत्री काल में किए गए भ्रष्टाचारों, जालसाजियों को छुपाकर लाखों करोड़ खर्चकर अपनी प्रशंसा के चर्चे करवाये तब ही सिद्ध हो चुका था कि अंहकारी सत्ता, संभालते ही अपनी दानवी प्रवृत्ति का तो घोर तांडव करे कि जनता त्राहि-त्राहि कर उठेगी। उसके बाद जो हो रहा है उसे न केवल देश की जनता भोग रही है। वरन न केवल देश में वरन पूरे विश्व में इस जाहिल दानव की आलोचना होने लगी है। सत्ता संभालते ही इसने कालेधन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, सीमाओं पर आतंकवाद समाप्त करने की तो दूर, जन-धन से मौज-मस्ती और विदेश यात्राओं में जुट गया, 40 से ज्यादा देशों की यात्राओं में प्रसार माध्यमों पर हर देश में अपनी झूठी प्रशंसा करवाने में हजारों करोड़, सभी सभाओं में भीड़ खरीदकर लाने में हजारों करोड़ और विदेशी वहां से समयबाधित हथियारों का कबाड़ा खरीदा गया। जबकि दूसरी और मोदी भारत सरकार का जालसाजीपूर्ण तरीके से जीता प्रधानमंत्री बन अपनी हर विदेश यात्रा में अपने आकाओं यथा अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, मित्तल व अन्य के लिए व्यावसायिक प्रतिनिधि व उनका व्यस्थ अधिकारी की भूमिका अदाकर इन सबके उन देशों की सरकारों और व्यवसायिक फर्मों से राजनीतिक व व्यवसायिक सौदेबाजी करता रहा, 40देशों की यात्रा में हर देश में यही किया। इंग्लैंड, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन आदि से लेकर बांग्लादेश तक में, जब इन सबकी आलोचनाएं चारों तरफ फेसबुक, ट्वीटर, वाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डन आदि पर होने लगी तो सार्वजनिक दृष्य व श्रव्य व मुद्रित प्रचार माध्यमों को जिने हर माह 10 पेज के विज्ञापन देकर खरीदकर मुंह और कलम बंद करता है। को भी इसकी आलोचना करना पड़ीत तो बदले में इस हरामखोर जाहिल ने फेसबुक ट्वीटर, वाट्सएप ने अपने विरुद्ध चलने वाली खबरों और विचार विनिमय को भी रोकना उड़ाना शुरू कर दिया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनवरी 14 में फेसबुक पर मोदी के विरुद्ध लिखी गई कोई भी टिप्पणी, समाचारों को फेसबुक स्वीकार ही नहीं करता था, जबकि आपके पृष्ठ पर मोदी की प्रशंसा में लिखी टिप्पणीयां कहीं से भी लाकर भर दी जाती थी। इसलिए फर 14 से फेसबुक चलाना ही बंद कर दी, अभी भी मात्र वाट्सएप पर मोदी के विरुद्ध लिखी सच्चाई पूर्ण टिप्पणियां, समाचार, वीडियो, कार्टून आदि को कई बार लिखते ही उड़ा दिए गए। बेशक जिसमें नोटबंदी, बैंकों, डाकघरों की जालसाजियां आदि का चित्रण, वर्णन था। भेजे जाने पर भी 15-20 दिन तक मोबाइल में ही पड़े रहे। जबकि दूसरे संदेशों का विनिमय होता रहा। एक बार 15 नवम्बर 16 से 5 दिसम्बर 16 तक के संदेश, वीडियो, ध्वनि चित्रावलियां, कार्टून पूरे उड़ा दिए गए, जबकि मोदी की प्रशंसा के सारे संदेश यथा स्थिति पड़े रहे और आते-जाते भी रहे, ये है व्यक्तिगत स्तर पर सरकारी हस्तक्षेप। अपने विरुद्ध चलने वाली सच्चाईयों को छिपाने, नियंत्रण करने, साफ करने में लगने वाले साधनों का खर्च जिसमें अधिकारियों,कर्मचारियों को वेतन, सुविधाएं उपकरणों के साथ अरबों रुपए खर्च करने और संबंधित कंपनियों को अरबों रुपए भी जन-धन से ही बांटे गए। आखिर ये धन भी तो जनता से ही लूटा गये करो का ही है। इससे इन हरामखोरों, जाहिल, तानाशाहों को क्या फर्क पड़ता है। उन्हें तो अपनी हर बत्तमीजी चाहे उससे देश की जनता भूखे ही क्यों न मर जाए, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए जैसा कि नोटबंदी में हुआ। 15-20 करोड़ बेरोजगार हो गए उनसे जुड़े परिवार, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, तो दूर लगभग राष्ट्र की 70 करोड़ जनता को इस दानव ने बैंकों की लाइन में खड़ा करवाकर नोट बदलने के लिए मजबूर कर दिया क्योंकि जो धन उनके हाथों में था, उससे रोजमर्रा की दूध, तेल, अनाज, सब्जी नही खरीदी जा सकती थी, चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची थी, सड़के सूनी, बाजार सूने, सबलाइन में खड़े थे और बिका हुआ भांड मीडिया यथार्थ के प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा उसकी जापान यात्रा, गंगा दर्शन व आरती दिखा रहा था। फेसबुक, ट्वीटर, वाटसएप पर इसके यथार्थ को छुपाकर सरकारी मशीनरी उस नोटबंदी की तारीफों के, उसके चलचित्रों के, टिप्पणियों को प्रचारित प्रसारित कर रही थी। तो सच का प्रस्तुतीकरण कर रहे थे, ये राष्ट्र भंक्षी दैत्यों का झूंड उन्हें राष्ट्रद्रोही करार दे रहे थे। दूसरी ओर सत्ता में बैठे इन सब को जानकर आंखें मूंदे अपने दो. नं. के भ्रष्टाचारर से कमाए गए धन को नए नोटों में बदलने के लिए बैंकों में साम, दाम, दंड, भेद के साथ अपने सत्ता के दंड का उपयोग कर पुरानेके बदले नए नोट बटोरने में लगे थे। ये हाल दिल्ली देश की राजधानी से लेकर राज्यों की राजधानियों, महानगरों से लेकर गावों तक था। एक तरफ कालेधन की आड़ में अपने आकाओं को रुपए 12.50 लाख करोड़ के कर्जे माफ कर चुका था, जो जनता का सफेद धन हजम कर चुके थे। दूसरी तरफ मात्र 6 प्रश लोगों के कालेधन की आड़ में 125 करोड़ को भूखा मारने पर न केवल तुला था वरन जनता से हर कदम वसूले गए हर दिन अपने विरुद्ध प्रसार-माध्यम आग न उगले धन से हजारों करोड़ के देश भर के मुद्रित व दृष्य श्रव्य माध्यमों को विज्ञापन लुटा रहे है।

नगदीहीन व्यवस्था से जनता से हर वर्ष रुपए 200 लाख करोड़ लूटेंगे

पेज 1 का शेष

पेट्रोल-डीजल पर 0.5 प्रतिशत सेस थोपकर रुपए 3 से 5 लाख क़रोड़ जनता से अप्रत्यक्ष रूप से वसूली तो घर-घर कचरा उठाने के नाम हर दिन रुपए 2 से 5 रु. प्रतिदिन के हिसाब से रुपए 60 से 200 की सीधी वसूली भी जनता से करने के नाम से, मोहल्ले के पार्षदों, सफाईकर्मियों को अकेले इंदौर में ही रुपए 30 से 50 करोड़ की अतिरिक्त वसूली हो जाने की शुरूआत हो चुकी है। अर्थात ये चाल भी लूट और डकैती ही सिद्ध हुई। जबकि इस सफाई के नाम सारे दिन कचरे की गाड़ियां मोहल्ले में घूम-घूम कर सफाई के गीत के नाम भारी ध्वनि प्रदूषण फैलाने के साथ बदबू और कचरा भी जो पहले दिन में एक दो बार फैलता था अब सारे दिन का स्थाई रोग बन गया। यही हाल टीवी चैनलों का जो केवल ऑपरेटर्स चलाते थे उन्हें डीटीएच के माध्यम से जोड़ने के लिए प्रति टीवी रुपए 5 से 6 हजार अर्थात रुपए 30 करोड़ टीवी के लिए रुपए 5000×30 करोड़ अर्थात रुपए डेढ़ लाख करोड़ की लूट के साथ सीधे ही अंबानी, टाटा, एयरटेल, वोडाफोन, वीडियोकोन आदि को रुपए 300×30 करोड़ अर्थात 900 करोड़ प्रति माह और वर्षभर में रुपए 10800 करोड़ की लूट और कमाई की व्यवस्था पूंजीपतियों के इशारे पर जनता को लूटने के लिए की गई। रक्त पिपासु, दानव मोदी ने नोटबंदी से जो कि कालेधन के नाम पर की गई, उसमें भी राहुल के शब्दों में, पप्पू बोलना, पढ़कर सीख गया। गरीबों को नोंचा और अमीरों को सींचा, का यथार्थ में मूल उद्देश्य था। एक तरफ हरामखोर जालसाज ने नोटबंदी कर रुपए 500-1000 के नोट चलन से बाहर कर दिए, दूसरी तरफ 50 दिन में सब सामान्य हो जाएगा कि झूठी शिगुफे बाजीकर रहा है जबकि रुपए 16 लाख करोड़ के नोटों के बदले ये मात्र रुपए 5 से 8 लाख करोड़ ही बाजार में चलन में डालेगा ताकि आमजन को ऑनलाइन डेबिट, क्रेडिट कार्ड के सौदे संपन्न करना मजबूरी बन जाए। जिसमें न्यूनतम 0.5 प्रश कहने भर के है जबकि 3 प्रश से 10 प्रश तक ऑनलाइन में वसूली की जा रही है। आईसीआईसीआई के गोल्ड क्रेडिट कार्ड व अन्य कार्डों में 3.80 प्रश का दंड, 40.82 प्रश का ब्याज, हर कार्ड के हर भुगतान पर वो चाहे रुपए 100 का हो रुपए 10000 का रुपए 151 न्यूनतम शुल्क है। फिर गैस अनुदान ऑनलाइन भुगतान के नाम रुपए 70-80 के अनुदान खाते में अंतरण के नाम हर अंतरण पर रुपए 50 का न्यूनतम शुल्क जो कि मात्र गैस अनुदान के अंतरण में रुपए 6000 करोड़ की वसूली बैंक कमीशन में ही जनता से लूट की जाती है। 125 करोड़ के देश में यह मान लिया जाए कि 100 करोड़ कार्ड से हर दिन औसतन 5 भुगतान करेंगे, औसतन रुपए 100 प्रतिदिन का कमीशन ऑनलाइन में जनता को देना पड़ा तो भी प्रतिदिन रुपए 75000 करोड़ जनता के जेब से जाएगा, वर्ष भर में यह राशि रुपए 182 लाख 50 हजार करोड़ जनता से ऑनलाइन के नाम पर डकैती डाली जाएगी, यह सामने से होगी यह लूट ही प्रतिदिन रुपए 75,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक की हो सकती है जिसे रोकने में पुलिस गृह मंत्रालय, सूचना तकनीकी मंत्रालय के पास न तो साधन न स्टॉफ, आने वाले समय में अगर कम्प्यूटर साईंस के स्नातक 5 प्रश या कुल जनसंख्या का 0.1 प्रतिशत भी बेरोजगारी के चलते इस आसान से कारोबार में जुड़ गए और मात्र रोज 0.1 प्रतिशत से ठगी का तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या हाल होगा। इस नगदीहीन व्यवस्था का इस संबंध में रिजर्व बैंक ने रुपए 5000 क्षतिपूर्ति देने की बात कही, जबकि ठगी का शिकार होने वाला रुपए लाखों गंवा चुका होगा। इसके साथ ही हर राष्ट्रीयकृत बैंकों से लेकर, निजी बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी भी घोर, मक्कार, चालाक और बत्तमीज होते हैं। जो स्वयं ही सैकड़ों जालसाजीयों को अंजाम देते हैं। जो चेक, ड्रॉफ्ट संग्रहण के लिए अलग-अलग बॉक्स में डलवा दिए जाते हैं। उन तक को तो वो हरामखोर, जालसाजों का स्टॉफ दूसरे के खातों में जमाकर अपना हिस्सा डकार जाते हैं। जिसकी शिकायत रिजर्व बैंक का लोकपाल भी नहीं लिखता, बैंक में शिकायत करने पर वहां के श्वानों की फौज मारापीटी पर उतारू हो जाती है। अरुण वित्त मंत्री बैंकों की उन जालसाजियों पर, ग्राहकों की मारपीट की शिकायतों पर तो कार्रवाई कर पाएगा, ये मुखेरा जनहित भक्षी पार्टी जो पूंजीपतियों की रखैल बन जनता का हर तरह से खून पी रही है और इलेक्ट्रॉनिक वोट क्रॉफ्टिंग मशीन की जालसाजियों से जीत कर खुश हो रही है।

न जालसाजियां समझ आए, न विपक्ष धज्जियां बिखेरे

पेज 1 का शेष

शीत सत्र में अधिकांश समय 56 इंच का सीना सिकुड़ कर 26 का हो गया और अधिकांश सत्र दिवसों में किसी न किसी बहाने गायब रहा अंत में आया ताकि विपक्षी सदस्यों को ज्यादा न झेलना पड़े और उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य न होना पड़े।इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए रेल बजट और राष्ट्रीय बजट को एक साथ संसद में प्रस्तुत किया गया ताकि रेलवे में चल रहे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, दुर्घटनाएं, बढ़ते किराए, घटती सुरक्षा, निजीकरण, सेवाओं का अपने भाई भतीजों को ठेके से लूट, नई परियोजनाओं की धीमी गति, नई ट्रेनों आदि पर खुलकर बात नहीं की गई, यथार्थ में विपक्षी सदस्यों को मौका ही नहीं दिया गया, ताकि बहस की जा सके या हो सके।

वही हाल राष्ट्रीय बजट का भी हुआ उसमें भी एक तरफ तो नोटबंदी से करोड़ों लोगों की बेरोजगारी नए पुराने उद्योगधंधों का बंद होना, नए में नगद लेन-देन पर रोक, आयकर की सीमा को रुपए 5 लाख न किया जाना ताकि जनता अधिक खर्च कर सके, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोक्रूड की आधी कीमत पर भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि, गैस पर अनुदान जो मोदी के आका अंबानी, अडानी देते है। 80 प्रतिशत कर वसूलने के बाद भी अनुदान कम करने के बहाने कीमतें बढ़ाना, नोटबंदी से कृषि पर विपरीत असर पड़ने पर भी किसानों को ऋण देने के लिए रुपए 10 लाख करोड़ की व्यवस्था की अर्थात खाद, बीज, कीटनाशकों, विद्युतभार बढ़ने और कर्जभार व ब्याज से यथार्थ में कृषि विकास का भ्रम पैदा किया, परंतु इससे कृषि उत्पादकों की लागत बढ़ने से आम आदमी की कमर ही टूटेगी।

दूसरी तरफ नगदीहीन व्यवस्था को बढ़ावा देने के बदले में सौदों पर 3 से 5 प्रश अधिभार नहीं हटाया गया। इससे जनता से रुपए 200 लाख से 300 लाख करोड़ की जनता सीधी लूट का लाभ अंबानी, पेटीएम, एयरटेल के मित्तल के साथ बैंकिंग कं. को जाएगा। जीएसटी जिसमें तीन प्रकार के जीएसटी होंगे। राष्ट्र, राज्य और अंतर्राजीय इससे भी वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि होगी, अर्थात इन सब पर बहस का मौका ही न मिले इसलिए दोनों बजट एक साथ पेशकर 56 इंच ने अपने सीने की 26 इंच करने से बचाने और 36 इंच रखने के लिए दोनों बजट पेश कर अपनी धज्जियां सदन में न बिखरें और इसका सीधा असर 5 राज्यों के चुनाव पर न पड़े और अपनी कहीं सत्ता पर ताजपोशी का मौका मिले न मिले। पर हार भी चौथे-पांचवे नं. की स्थिति में लाकर न खड़ा कर दे। संसद में विपक्षी बहस करते, स्वाभाविक है पक्ष में बैठे लोग उत्तर प्रतिउत्तर में कुछ कहते। वही वाक्य विपक्षी के लिए हथियार बनते जो इनके वादों, भाषणों की धज्जियां बिखेर देते। फिर अब तो संसद में जो भी कुछ बहस आरोप-प्रत्यारोप लगते-लगाते है। जनता भले ही क्रिया-प्रतिक्रिया दे न दे, परंतु मस्तिष्क में जरूर रखती है और वोटिंग के समय अपने अधिकार का उपयोग करती है। इन सबके के साथ ही दोनों बजट अलग-अलग पेश करने से न केवल मोदी, अरुण चीटली के साथ सभी विधानसभाओं के 5 राज्यों के सांसदों को भी चुनाव प्रचार-प्रसार का भी मौका नहीं मिल पाया। इसीलिए भी विपक्ष शांति से भाजपा की चाल पर चुप रहा। इस महत्वपूर्ण पर दृष्य, श्रव्य और मुद्रित प्रसार माध्यमों ने कोई विशेष टिप्पणियां और आलोचनायें नहीं की। वैसे भी 99प्रश प्रसार माध्यम यथार्थ में धनार्जन और पक्षपातपूर्ण, सत्ताधीशोंके तलुवे चाटकर जनता को भ्रमित करते रहने के कारण अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। यही कारण है कि अब न केवल सरकारी दूरदर्शनी समाचार है। श्रृंखलाओं को वरन सभी निजी समाचार श्रृंखलाओं से विमुख हो जनता का युवा और बुद्धिजीवियों के साथ सक्षम लोग अब वाट्सएप, मोबाइल संदेशों, फेसबुक, ट्वीटर आदि पर न अन्य की वरन स्वयं की भावनाओं को ज्यादा वैविध्यपूर्ण तरीके से विशिष्ट वर्ग के सामने प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं।

साप्ताहिक समय माया

नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण 3 वर्ष और तांडव

3 दशकों की उ.सि.परि. असफल-लूट के लिए बना रहे, लग रहे हजारों करोड़

सू.अ. आवेदन देख डर जाते हैं। उपयंत्री से उपाध्यक्ष मंत्री मु.मं./अंदाज लगा सकते हैं कि हजारों करोड़ की लूट का आलम। क्षिप्रा में लाखों मछलियां मौत के कगार पर, जलाभाव, फिर जनधन से हजारों करोड़ की परियोजनायें क्यों?

म.प्र. की जीवनदायिनी नर्मदा नदी ही प्रदेश की 50% जनता को अन्न, जल, बिजली के साथ सुख और समृद्धि की कारक और कारण है। परन्तु घोर लोभी डकैतों ने उसे अपनी डकैती का साधन बना। इस प्राणदायिनी पुण्य पावन सलिला को हर तरह से बर्बाद करने की कसम खा रखी है। स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज नाममि देवी नर्मदा यात्रा के 144 दिन में, बड़ी-बड़ी हस्तियों को बुलाकर अपनी वाहवाही करवाता है और जनता पर थोपे गये 31% वेट रु. 4/- प्रति ली. अतिरिक्त करों से वसूल कर हजारों करोड़ बर्बाद कर स्वयं नर्मदा तटों का सर्वे करता है, कि कहां से उसके रिश्तेदारों के 700 से ज्यादा चल रहे डंपर रेत निकाल नर्मदा के तटों को खोखला कर अपना व्यवसाय करेंगे तो दूसरी तरफ नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माध्यम से जनधन का हजारों करोड़ बर्बाद कर उद्वहन सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से अपना मोटा कमीशन जीमता है। ओंकारेश्वर की टर्न की नहर निर्माण जो दो वर्ष में जो 2 नव.08 को पूरा होना था 17-17 समय विस्तार देकर करोड़ों का महंगाई का भुगतान कर कमीशन हड़पता है। वही रा.अं. सागर बांध की दायीं बाईं तट नहरों का हैं, जो आज भी न केवल अधूरी व कच्ची हैं। जिनकी सीमेंट लाइनिंग का पैसा 867 करोड़ 1997 में स्वीकृत हुआ था हजम कर लिया गया। अभी भी बारगी बांध की दायीं बाईं तट नहरों, इंदिरा सागर नहर, ओंकारेश्वर की दांई बाई तट नहरों की वितरणीयों के निर्माण के कार्य के नाम पर हजारों करो रु. हर वर्ष लगाया जा रहा है। साथ ही सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के नाम पर भी लगभग रु. 40,000 करोड़ का नया खेल शुरु हो चुका है। जिसमें अकेले नर्मदा परियोजना के मुख्य अभियंता कार्यालय को ही रु. 15,166 करोड़ मिला। पिछले अंकों में लगभग रु. 30,000 करोड़ की उद्वहन परियोजना के संबंध में प्रकाशित किया गया था। जबकि नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना में भी सिंहस्थ और 2016 की वर्षा समातिक 170 दिनों में से 17 दिन भी 24 घंटे पंप नहीं चलाये गये। ग्रामीणों ने धरने-प्रदर्शन किये तो मु.अ. अजनारे का कहना था कि पानी ही नहीं है बांध में तो पंप कैसे चलाये। तो जनधन के हजारों करोड़ की होली क्यों? नई परियोजनाओं पर पैसा खर्च दिखाकर हजम करने की तैयारी में लगे है। जब 5 एमसीएम पानी क्षिप्रा में डालने के लिये नहीं है। जिससे न केवल कृषकों वरन् त्रिवेणी से होकर चंबल तक जल में पल रही मछलियों के मरने का खतरा भी है। तो फिर 15 एम.सी.एम. पानी नर्मदा गंभीर में कैसे आपूर्ति होगी। पर सावनी सूरदासों को इससे मतलब नहीं ये तो रु. 1900 करोड़ बर्बाद करेंगे। मु.मं. चौहान, महाधूर्त पूर्व मु.स.आर. के साहनी अध्यक्ष जो 10 वर्ष पूर्व शा.से.सं. सेवानिवृत्त हो चुका है। घोर लालची सरकार के कुकर्मों के कारण ब्लेकमेल कर पद हथिया बैठा है। उपाध्यक्ष रजनीश वैश्य जो एक ही पद पर पिछले 15 वर्षों से अजगर की तरह लिपटा है और अब अपर आयुक्त व सदस्य पुनर्वास का भी पद संभाल मोटा धन जीम रहा है। साथ ही सदस्य अभियांत्रिकीय शिवहरे 3 री संविदा पर, शूकर सलाहकार परिहार जो से.नि. के बाद भी 7 वर्ष से ज्यादा समय से कुंडली मारे बैठे गिद्धों की ये फौज सूचना के अधिकार में जानकारी देने के नाम पर ये हरामखोर परिहार अपीलों और आवेदनों को निरस्त करने के सूत्र से.नि. संविदा पर बैठे सदस्य मु.अ.अ.यं. व अन्य को बताकर विभिन्न कारणों की आड़ में देने से बचते हैं। क्योंकि ये अमर फल खाकर धरती पर लूटने के लिये पैदा हुए हैं। इसलिये मु.मं. शिवराज चौहान, अ.स. रजनीश शिवहरे, परिहार के बाप की जागीर है। इसलिये ये निकम्मे बेशर्म अपील की सूचना सुनवाई, सुनवाई की तारीख निकल जाने के बाद भेजते हैं। ताकि अपीलार्थी आकर इन जालसाजों की सच्चाई न बता सके, वैसे तो शिवपुत्री नर्मदा स्वयं ही ऐसे सभी जालसाज धूर्तों को अकाल मृत्यु और पर्याप्त दंड देती हैं। जिसके उदाहरण हैं पूर्व का धूर्त जालसाज स.अं. इंजी. इंगले, अ.यं. राठौर, अ.यं. आरघ जिन्होंने जालसाजियों से धन तो कमा लिया न.घा.वि.प्रा. में भ्रष्टाचार करके परन्तु परिणाम सामने हैं। ठेकेदार करण सिंग बीसी बिहानी की बरबादी की व्याख्या करना उचित नहीं समझता जिन्होंने खूब समय विस्तार लेकर महंगाई का अरबों रु. का लाभ उठाया। उनके व अन्य ठेकेदारों के हालात किसी से छुपे नहीं है। अजगर की तरह कुंडली मारे बैठे सभी अधिकारी से.नि. के बाद भी मोटा धन हड़पने कुंडली मारे बैठे हैं। धन भले ही इकट्ठा कर लें। परन्तु सुख भोगने की अपेक्षा घोर कष्टों में ही अंतिम विदाई लेंगे। इस सबकी व्याख्या के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये भी है कि ये जितने बांध नर्मदा पर बनाये गये आखिर इन सबका कितना जीवन है, 50 वर्ष अधिक से अधिक 100 वर्ष भी मान लें। यदि युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं ने तांडव नहीं बरपाया तो भी कितने वर्ष चलेंगे, पुनः प्राकृतिक अवस्थाओं में बहेगी नर्मदा, तब क्या होगा इंदिरा सागर बांध में डुबोई गई हजारों बस्तियों, हजारों हेक्टेयर जंगल व कृषि भूमि जिसका कुल 90,000 हे. का 20 % अर्थात लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाद में मरुस्थल बन जायेगा, वही हाल बारगी, ओंकारेश्वर, सरदार सरोवर के साथ देश व दुनिया के बांधों का होगा। जिसके लिये जिम्मेदार ही केवल सत्ताधीशों का घोर लालच। लूटो जितना लूट सको, अंत काल पछतायेगा प्राण जायेंगे छूट, चाहे मु.मं. शिवराज, अ.स. रजनीश, स.अ. शिवहरे, अ.यं. तोमर, परिहार या अन्य कोई।

खनन से खनका रहे, मु.मं., मंत्री, प्र.स., स.संचालक, जिलाधीश, स.जि. अधि. निरीक्षक व ठेकेदार

नोंच मारो नदियां, पहाड़, मैदान, वन, खेत

कुछ न बचे अगली पीढ़ी को, धूर्तों की फौज सू.अ. में आवेदन देखते ही बिफरती, अपीलें हजम कर जाते है। जिलाधीश, सू.आयोग, सब बर्बाद कर दो अभी

वर्तमान में म.प्र. में भाजपा का मु.मं. शिवराज कांग्रेसी दिग्गी दानव से बड़ा धूर्त महादानव सिद्ध हो रहा है। ये मुखेरा जनहित भक्षी पार्टी का प्र. म.मुं.यं. जैसा कहते हैं। 60 साल कांग्रेस ने लूटा, तो ये कांग्रेस की 60 साल की लूट से बड़ी लूट प्रदेश के प्राकृतिक और मानव निर्मित स्त्रोंतों से कर लेने के लिये बेताब ये अजर-अमर बने राक्षसों की फौज कर रही है। सारे नियम कानून, इनके कानूनी रुप से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनते ही इनके बाद जो बेचारे मजदूरी और किसानी कर इन दानवों को पाल पोसकर बड़ा बना गये, जिससे ये यहां पहुंचे, इनके बाप की जागीर बन गये, प्रदेश में शिवराज के 11 वर्ष के मुख्यमंत्री काल में हीरे से लेकर रेत, गिट्टी, पत्थर तक लगभग रु. 5 लाख करोड़ के खनन में से रु. 4 लाख करोड़ का अवैध उत्खनन किया गया, जिसमें से अकेले रु. 1 लाख करोड़ की रेती ही प्रदेश 10 से ज्यादा बड़ी नदियों के तटों से और 30 से ज्यादा छोटी नदियों के तटों से, इन नेताओं और उनके माफिया ठेकेदारों ने निकाल न केवल प्रदेश वरन् सटे हुए प्रदेशों यथा महाराष्ट्र, उ.प्र., राजस्थान, गुजरात आदि में भी बेची। जिसे जिलों के कलेक्टर, सहा. व उपजिलाधीशों के साथ जिला खनन अधिकारियों व निरीक्षकों का मोटे धन के बदले संरक्षण मिला। जबकि हीरा खनन के मामले में जो कि विदेशी उपग्रहों के 1986 के सर्वे के अनुसार जिसकी रिपोर्ट एक 1988 में एक कम्प्यूटर पर तैयार किये जाते समय देखी थी। हीरा छतरपुर-पन्ना से लेकर सतना-रीवा तक के वनीय व ग्रामीण क्षेत्रों में हे. को विदेशी कं. को उत्खनन के लिये विदेशी कं. को हजारों करोड़ का कमीशन डकार सौंप दी गई, वहां से चलकर झाबुआ की मैग्नीज खदानों, बालाघाट की मलाज खंड की तांबा अयस्क खदानें, कजी, सतना, रीवा की चूना खदानें, गोरेगांव की संगमरमर खदानें, छिंदवाड़ा सारणी शहडोल की कोयला खदानों के साथ पूरे प्रदेश के पक्के काले, लाल पत्थर की खदानों में, प्रदेश की नदियों के तटबंधों पर निकाली जा रही 15000 से 20,000 टन भी रेत भी 90% अवैध रुप से निकाली जाकर मात्र वैधानिक रुप 10% की ही रायल्टी सरकार के खाते में आती है। बाकी सब में मु.मं. चौहान, खनिज माफिया मंत्री राजेन्द्र शुक्ल से लेकर सारे जिलाधीश संबंधित क्षेत्रों के थानों से लेकर जिला स्तर पर बैठे खनिज अधिकारी, निरीक्षकों व बाबुओं की बंदरबांट होती है। इसके साथ शासकीय स्तर पर मिलने निर्माण विभागों, यथा लोक निर्माण विभाग इसका व्यावसायिक संगठन म.प्र. सड़क डकैती विकास निगम जिसके हर टर्न की बीओटी ठकों में भी 90% रायल्टी हजम कर गये मु.मं. चौहान की अध्यक्षता में, यहां तक हर बड़ा ठेका भी, अब लोक निर्माण विभाग के इस सड़क डकैती निगम को ही दिया जा रहा है। क्योंकि वहां पर चुन-चुन कर सारे न केवल भ्रष्ट वरन् घोर मूढ़ इंजीनियरी लोक निर्माण के विभाग के ही एक स्थान पर बैठाये गये हैं। जैसे इंदौर में बैठा का.यं. बी.पी. बोरासी, जिसके पास एक साथ तीन पदों पर पिछले 5 वर्षों से इसीलिये बैठा रखा है चौहान क्योंकि वह इंदौर-उज्जैन संभाग के 15 जिलों में चल रहे कार्यों में कार्य मु.मं. का पसंदीदा ठेकेदारों को दिलवाकर उसे लूट की पूरी छूट देकर कार्य करवाता है और बिना किसी न नुकूर के, बिना मीन मेख निकाले, बिना रायल्टी काटे भी कई बिलों का भुगतान कर शेयर हिस्सा सभी को यथा योग्य समय पर पहुंचा देता है। इसलिए डीपीआर भी दोगुनी बनाई जाती है। सामग्री यथा पत्थर, गिट्टी, चूरी, बंजरी, रेती की दुगुनी कीमत व उपयोग दिखाकर रायल्टी की राशि 20-40% ही काटी जाती है। यही हाल परि. क्रिया, इकाई, सेतु व लोक निर्माण विभाग का है। इसके साथ ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा, लो.स्वा.यां., विद्युत कं., जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण सारे नगर निगम, पालिकायें, पंचायतें, प्रदेश के सारे विकास प्राधिकरण, सारे गृह निर्माण व आवास मंडल यथा म.प्र. गृह निर्माण मंडल, पुलिस हाऊसिंग आदि शासकीय विभागों के कार्यों के निर्माण की प्राक्कलन के अनुसार उपयोग की गई सामग्री की रायल्टी भी ईमानदारी से जमा की जाये तो अरबों रु. प्रति माह शासन को अतिरिक्त मिल सकते हैं। पर 90% जिलों में ये राशि वहां बैठे लेखाधिकारी, ब्लाक व ठेकेदार हजम कर जाते हैं। जिसका अंकेक्षण स्वयं खनिज विभाग को केन्द्र व राज्य शासन के सभी विभागों और क्षेत्रीय निगमों, पालिकाओं, प्राधिकरणों से लेकर पंचायतों तक हो रहे हर निर्माण कार्य की सामग्री के उपयोग पर दी गई रायल्टी से सत्यापित करना चाहिये, इसके विपरीत खनिज विभाग में अधिकारियों, निरीक्षकों, बाबुओं का पर्याप्त स्टॉफ नहीं है। फिर सब भ्रष्ट और जालसाज स्वयं ही अवैध खनन और ढुलाई को बढ़ावा देकर वसूली कर अपने आकाओं की सेवा चाकरी कर पद और शिकायतों के साथ वैध-अवैध खनन माफियाओं से अपनी जान बचाने में ही लगे रहते हैं। यही कारण है कि सूचना के अधिकार में यह विभाग जानकारी नहीं देना चाहता और जिलाधीश को अपील करने पर अधिकांश अपने मातहतों को बचाने के लिये बहाने से खारिज कर देते हैं। बेशक इंदौर जिलाधीश ने पहली बार ईमानदारी और दिलेरी दिखाते हुए निःशुल्क जानकारी देने के आदेश दिस.16 में जारी किये थे। जिसकी थोड़ी सी जानकारी बड़ी मुश्किल से फर. 17 में दी गई और बाकी अभी तक नहीं मिली, जबकि उज्जैन, देवास में, देवास जिलाधीश कार्यालय की सुनवाई का पत्र, सुनवाई की तारीख के बाद मिला, शिकायत की गई, तो पत्र खनिज विभाग की अपील की सुनवाई को भेजा और अपील आदिम जाति की सुनवाई की गई। इंदौर में पत्र देने के बाद सुनवाई कर निःशुल्क जानकारी देने के बाद, कुछ बड़े भू और खनिज माफिया जो वर्षों से पत्थर, गिट्टी, रेत का अवैध व्यापार कर सबको बांट और धन देकर साध, दिन दुनी रात चौगुनी कमाई कर रहे थे, छापे डाले गये, जिनके 40 घन मी. के थे 4000 घन मी. खोद चुके थे, मु.मं. के रिश्तेदारों के नाम के 35 डंपर पकड़े गये। अर्थात के.के. मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता के लगाये 600 डंपरों जो जेपी एसोसियेट्स के पास सतना-कटनी में काम रहे थे। हटाकर होशंगाबाद, बुधनी में लगा दिये इसलिये सांसद सिंधिया ने नर्मदा यात्रा को सर्वे यात्रा बताकर सच ही बोला। ऐसा नहीं है, कि भ्रष्ट, जालसाज मु.मं.चौहान ने नर्मदा घाटी क्षिप्रा में केवल रजनीश बैश को 25 वर्ष से ज्यादा समय से बैठाकर 3-3 पद देकर अपनी कमाई और उसकी गोपनीयता को सुनिश्चित किया हैं, ऐसे कई इंजीनियर जिसमें सं.क्र. 25 व 27 संभाग में 15 वर्ष से ज्यादा समय से बैठा फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहा संसाधन मीना भी हैं, जो नर्मदापुरम और इंदिरा सागर की कालोनियों का अरबों रु. हजम कर रहा है। एक एसडीओ कटारिया हैं। जो दिल्ली के नर्मदा रेस्ट हाउस में हर वर्ष लाखों के फर्जी बिल हजम करते हैं, तो नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना धामनोद में भी हर बिल में 10% तक कमीशन हजम कर वर्षों से 23 नं. संभाग भोपाल में अजगर की तरह चिपकाये रखा है। ये है धूर्त दानव की भ्रष्टाचार पूर्ण कार्य पद्धति, मुरैना, भिंड, शिवपुरी व अन्य सभी जिलों में इन भू और खनिज माफियाओं के वर्चस्व का अंदाजा इसी से लग जाता है कि वे पुलिस और शासकीय अधिकारी जो दमदार, मजबूत शिकायतों के कारण मजबूरी में ऐसा खनन और अवैध परिवहन पकड़ने जाते हैं, तो इन पर हमला कर दिया जाता है।

क्षेत्रीय विकास वाद का ट्रंप विश्व के गरीबों को लाभप्रद

पेज 1 का शेष

भारत में विश्व व्यापार संगठन के इशारों पर नाचकर हमारे यहां के महाधूर्त भ्रष्ट व घोर जालसाज, भारतीय प्रशासनिक सेवा बनाम भा. प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों ने ही विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से विकास के नाम पर अरबों करोड़ रुपए का ऋण लिया जिसका, मात्र 50 से 60 प्रश कार्य हुआ और सारा धन मंत्रियों व इन धूर्तों ने देश पर कर्जलादकर हजम कर लिया बदलें में देश के संसाधनों को गिरवी कर दिया, ट्रंप ने इस संगठन के इन इरादों और चालबाजियों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था और स्पष्ट कर दिया था कि पहले देश इसके विकास के लिए आम अमेरिकियों को रोजगार व विकसित होना आवश्यक है जबकि ये बहुराष्ट्रीय कं. जिसमें हथियार उत्पादकों, अनुसंधान, संचार व कम्प्यूटर, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर, विमानन, इलेक्ट्रानिक्स आदि कं. ने आम अमेरिकियों की उपेक्षाकर, ज्यादा मेहनती, कम वेतन पर काम करने के लिए एशियाई नागरिकों यथा भारत, चीन, पाकिस्तान व अन्य राष्ट्रों के नागरिकों को नौकरी पर रख मोटा लाभ कमाना शुरू कर दिया, इससे आम अमेरिकी जो कई पीढ़ियों से अमेरिका में बस गए थे बेरोजगार हो गए या उन्हें निम्न स्तर के कार्यों से जीविकोपार्जन करना पड़ रहा था। ट्रंप के पूर्व राष्ट्रपति यथा बराक, बिल, रीगन व अन्य सभी ने चूंकि इन बहुराष्ट्रीय कं. के गिरोह से मोटा चुनावी चंदा लिया था, इसलिए उनकी मजबूरी थी कि उनके हितों के लिए कानून बनाएं विदेशी मजदूरों जो कम मजूदरी और अधिक कार्य के घंटों में कार्य करने के लिए तैयार हो, अमेरिका में आने की इजाजत दे व उन्हें नागरिकता प्रदान करें, चूंकि ट्रंप स्वयं अरबों डॉलर के अनेकों व्यवसायों का कारोबारी है इसलिए उसने अपने धन से चुनाव लड़ा तो आखिर क्यों वो इन धूर्त बहुराष्ट्रीय कं. की सुनेगा और नाचेगा, स्वाभाविक है अमेरिकी, युरोपियन हथियार व युद्धक सामान बनाने वाली कं. द्वारा अपने हथियारों को बेचने, उनके प्रदर्शन के लिए युद्ध का खेल और आतंकवादियों को पालने पोसने पाकिस्तान को सहायता देकर आतंकवादी गतिविधियां चलवाने पूरी दुनिया में डर व दहशत फैलाकर अपने कारोबार को चमकाने के खेल पर भी विराम लगेगा।अमेरिकी इतिहास के 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से हुए हर क्षेत्र में चाहे वह स्वास्थ्य हो, वैज्ञानिक उन्नति, वैज्ञानिकी युद्ध हथियारों के विकास आदि में डर, दहशत फैलाकर अपना माल बैचने का अमेरिकी व युरोपियन कं. के गिरोह का बोलबाला रहा है जिसे समयमाया के पूर्व के संस्करणों में छापा है। ऐसी ही कं. ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में चंदा देकर अपना माल बेचने के षड़यंत्रों में दुनिया के अन्य देशों पर बनाकर उन्हें नचाया गया है। पर ट्रम्प के मामले में इन अमेरिकी व अन्य युरोपियन कं. से चुनावी चंदा न बटोरने के कारण इस बार वह दांव उल्टा पड़ गया और यही कारण था, कि ट्रंप ने वैश्विकता के षड़यंत्रों से अलग होकर क्षेत्रवाद के विकास को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। यथार्थ में ट्रंप के व्यावसायिक और चारित्रिक दुर्गणों को नजरअंदाज कर देखा जाए तो यह विश्व के गरीब और मध्यम स्तर के प्राकृतिक साधनों वाले राष्ट्रों की जनता के लिए अत्याधिक लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि इस वैश्वविकता की आड़ में इन कं. ने अनेकों राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को खरीदकर खाद्य सुरक्षा व मानक अधि. 06 जैसे अनेकों कानून पास करवाकर हमारे देश के प्राकृतिक साधनों यथा जन, जमीन, जलवायु का भरपूर दोहन क हमारी ही मनी, मशीन में न पॉवर न माल मैनेजमेंट से हमारे ही देश के मार्केट पर कब्जा जमाकर हमारी ही जनता से 5 से 5000 गुना तक लूट कर लाभांश देश से बाहर भेजा जा रहा है जैसे कोकोकोला, पेप्सी आदि पेय पदार्थों, पिज्जा, बर्गर व अन्य सैकड़ों सामग्री हमारा ही पानी जो 5 पै. लीटर का होता है हमारी ही जनता को 20 रुपए ली. बेचकर लूटा जा रहा है और महंगाई बढ़ाकर आम आदमी के मुंह से दाना पानी न केवल ये कं. के दबाव के चलते वह पानी स्टेशनों और ट्रेनों में रुपए 20 प्रति ली. में लेना पड़ता है। जिससे गरीब यात्रियों को प्यासा रहना पड़ता है। इसी कारण मेक्सिकों की जनता जब त्रस्त हो गई तो वहां 5 वर्ष पूर्व भारी बगावत हुई और इन बहु राष्ट्रीय कं. को वहां से खदेड़ा गया। बेशक़ हमारे धूर्त दानवों की फौज जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, मानव निर्मित संसाधनों यथा बिजली, पानी, सड़के खदाने, जर, जमीन, कृषि आदि सब गिरवी करने, बैचने पर तुली हो चाहे वह कांग्रेस हो या भुखेरा जनहित भक्षी पार्टी, बस उसका कमीशन भर दीजिये और तोलिये क्या लीजिए क्या चाहिए है, स्वाभाविक है यह हर लोकतांत्रिक राष्ट्र की कहानी है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का यह गिरोह अपनी जालसाजियों को ज्यादा अंजाम नहीं दे पायेगा क्योंकि ट्रंप का क्षेत्रीय विकासवाद वैविश्कता के लूट खसौट कर देगा। जिससे विश्व में इन बहुराष्ट्रीय कं. का भ्रष्टाचार बढ़ाओ।

लूट के लिये नये-नये तरीके बंद करो विद्युत कं., मंडल को पुर्नजीवित कर, स्थायी भर्तीयां करो व ठेकेदारी प्रथा बंद करो

विद्युत-सत्ताधीश झटकों से कमाई के लिये जनता को लूट के झटके

मंडल के स्थापित 13000 मेवाके प्लांट बंद करने का षड्यंत्र रु.1/- प्रति यूनिट की खरीद रु.5.70पै. फिर रु. 2.43 की बिक्री, म.प्र. की जनता को रु. 10.40 पै. यूनिट में

मध्यप्रदेश में यथार्थ में 8-9 हजार मे.वा. की मांग के विरुद्ध 30 हजार मे.वा. बिजली ताप, जल पनचक्की, सौर ऊर्जा से प्राप्त हो रही है, यही कारण है कि ये शिव दानव मोटे कमाई और जनता से लूट के लिये म.प्र. विद्युत मंडल द्वारा स्थापित सारणी व अन्य स्थानों के ताप विद्युत गृह जो 13000 मे.वा. बिजली बनाते हैं। कभी कोयले की कमी, कभी पुराने होने का बहाना बनाकर बंद करने पर तुले हैं। जबकि दूसरी ओर मंडला जिले में परमाणु बिजलीघर बनाकर मोटा कमीशन परिष्कृत यूरेनियम खरीदने के बहाने, समय बाधित भट्टियां बनाई जा रही है। उन भट्टियों से जो रुस, फ्रांस, आस्ट्रेलिया में अपनी आयु पूरी कर आई परमाणुवीय घातक अल्फा, बीटा गामा किरणें जो रेडियोधर्मी हैं और मानव के लिये घातक हैं उगल रही हैं। वो इन भट्टियों को सुरक्षित नष्ट करने के लिये परेशान हैं। ये शूकरों की फौज मोटे कमीशन के चलते उन्हें लगाने के लिये बेताब है। इसके साथ ही रिलायंस, टाटा पावर से वही ताप विद्युत मोटे कमीशन पर खरीदी जा रही है और अपने हिस्से कि 49% विद्युत की जो लगभग 70 पै. युनिट की इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर से नहीं खरीदी जा रही है। जबकि रु. 5.70पै. प्रति यूनिट की बिजली, वायु सेा चलने वाली पवन चक्की जो निजी क्षेत्र में हैं। म.प्र. के अधिकांश पहाड़ों पर स्थापित कर उनसे जिसकी लागत पूंजीगत ब्याज जोड़कर भी 30पै. यूनिट से ज्यादा नहीं हो तो करीब 300 मे.वा. प्रतिदिन रु. 5.70 से खरीदी कर रु. 3/- प्रति यूनिट का कमीशन डकारा जा रहा है। वही हाल पूरे प्रदेश में लगे 200 मे.वा. के सौर ऊर्जा का भी हैं, जबकि शासन ने निजी क्षेत्र में न केवल जमीन वरन् जनधन से अनुदान भी दिया गया है। फिर भी रु. 5.50 पै. यूनिट की खरीद की जा रही है। इस प्रकार हर महीने रु. 5345 करो का अतिरिक्त बोझ उस पर भी कमीशन हजम कर, जनता से 10 से हजार गुना बिल देकर रु. 175/- का न्यूनतम बिल, ऊर्जा शुल्क, सेवा कर, ऊर्जा ड्यूटी, दो बल्ब वालों को भी रु. 15-15 हजार से रु. लाखों तक के बिल देकर मानसिक, आर्थिक, सामाजिक प्रताड़ना दी जा रही है। शिकायत करने जाओ तो वहां बैठे डकैतों की फौज कुछ नहीं सुनती, उल्टे ही किश्ते बनाने, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद जब्त करने गुंडों से ठेके में बिल वसूली करवाने का तांडव करती है। जब से एलईडी बल्ब आए हैं बिजली खपत प्रकाश के लिए सीधी 10 से 20 प्रश रह गई है। 50 यूनिट की खपत वास्तविकता में 5 यूनिट हो गई है। परंतु बिल मन से 500 यूनिट तब के भेजे जा रहे है। रखरखाव के नाम पर ठेकेदारी में दिया गया कार्य मात्र 25 से 35 प्रश होता है फिर भी करोड़ों के बिलों का भुगतान मोटे कमीशन पर किया जा रहा है। यहां तक कि उच्च व निम्न दाब के खंभों की पुताई पिछले 12-15 वर्षों से नहीं हुई, पुताई के स्थान पर मोटी कमाई के लिए ठेका देकर ऐसे स्तरहीन खंभे लगाये गये जो लाइनों का भार झेलने से पहले ही मुड़ गए, और पुराने खंभों का हजारों टन लोहा बाले-बाले ही बेंचकर हजम कर गए।

जब से विद्युत मंडल की कंपनियां बनाकर धूर्त गिद्ध भा. प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों को बैठाया गया तब से इन जाहिलों ने हर वर्ष 5 कंपनियों में हजारों करोड़ डकार इन कंपनियों में घाटा दिखा, वर्ष में 2 से 3 बार तक जनता को कीमतें बढ़ाकर लूटा जाता रहा है, जबकि ये गैर तकनीकी, गैर विशेषज्ञ, भा.प्र.से. के अधिकारियों की लूट, वसूली और जालसाजियों बत्तमीजियों ने अच्छे खासे लाभ में चलते हुए हर सरकारी उपक्रमों मप्र सड़क परिवहन निगम, इलेक्ट्रानिक निगम, विपणन संघ, मप्र वित्त निगम आदि अनेकों को डुबो दिया, वही हाल केन्द्र में एयर इंडिया भारतीय इस्पात निगम भारत एल्यूमिनियम जैसे सैकड़ों शासकीय निगमों में लूटपाट, जालसाजियों से घाटे में लाकर डुबो दिया, ये हरामखोरों की फौज जनता से भी अनाप-शनाप लूटती है, कर्ज भी हजम कर जाती है और सरकार के भ्रष्ट शूकर मंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, सरकारी बजट आवंटन में भी हजारों करोड़ का प्रबंध करती है, ताकि आसानी से वह जनधन भी हजम किया जा सके जैसा कि वर्तमान में इन विद्युत कं. में भी पिछले 15 वर्षों से ये लूट का तांडव चल रहा है। पिछले वर्ष भी बजट में ऊर्जा के नाम पर रुपए 21183.36 करोड़ के व्यय की व्यवस्था की थी और इस बार भी रुपए 16801.62 करोड़ की, इतनी चारों तरफ से जनता से लूट के बाद बिजली बेचने और खरीद में 50 से 70 प्रश कमीशन जो हजारों करोड़ प्रतिदिन में होता है। हजम करने के बाद भी इंदौर जैसे शहरों में विद्युत कटौती पूरे वर्षभर रखरखाव के नाम से चलती रहती है। 50 प्रश लाइन स्टॉफ यथा लाइन मेन, मीटर रीडर, उपकेन्द्रों, निम्न दाब और उच्च दाब परिवर्तन या सब स्टेशनों पर कार्यरतकर्मी आदि न्यूनतम मजदूरी से कम पर ठेके में कार्य लेकर मोटा कमीशन करोड़ों में हजम किया जा रहा है, जो सब नियमित होने चाहिए थे। बस भगवान भरोसे ये तीनों वितरण और उत्पादन, प्रेषण कं., जुआखोर जालसाज पॉवर ट्रेडिंग कं. की दया पर चलाई जा रही है। अब जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सिरे से विश्व व्यापारिक लूट संगठन को खारिज कर दिया है। स्वाभाविक है बहुराष्ट्रीय कं. दूसरे देशों के अच्छे लाभ देने वाले संसाधनों को वहां की सरकारों के मंत्रियों और अधिकारियों को मोटी घूस देकर वहां के प्राकृतिक और मानव निर्मित संस्थानों और स्त्रोतों को कब्जाने के षड़यंत्र की मुहिम धीमी कर पावन लोकतंत्र आत्मा को जीवित क्यों नहीं किया जा रहा, शूकर मंत्रियों, डकैत अधिकारियों, पूंजी दानवों, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला व अन्य पूंजीपतियों के गिद्धों, खानदानों, मोदी और उसके मुखेरा जनहित भक्षी पार्टी के श्वानों मंत्रियों, नेताओं क्या तुम अमर फल खाकर आए हो, जो 200-500 वर्ष धरती पर रहना है, जो जनता का रक्त चूस-चूस कर हर कदम परेशान करना, लूटना मनमानी मीटर रीडिंग लिखना, अंट-शंट बिल भेज, आम गरीब और निम्न मध्यमवर्गीय को अकाल मृत्यु, आत्महत्या की तरफ ढकेल रहें है।

बेशक इसे बर्बाद करने में उपयंत्री से सहायक यंत्री बने जीके वैष्णव ने मोटा धन खाकर अभियंता, संघ का अध्यक्ष बन सरकार से इस शूकर जालसाज, भ्रष्ट ने सौदेबाजी कर कं. बनाने में अहम भूमिका अदा की और कर रहा है। अभी भी वक्त है सारे प्रदेश के विद्युत कं. के और देश इंजीनियर्स, इकट्ठे होकर एकमुश्त सरकार को चेतावनी देकर सारी कं. खत्म कर देश के सारे मंडलों को जीवित कर तरीके से विद्युत उत्पादन और वितरण करें, मंत्री और नेता घोर लालची मूर्ख होता है, जिसे भारतीय प्रताड़ना सेवा में अधिकारी हांकते चलाते और टुकड़खोरों को टुकड़े डालकर सारी फाइलें चलाते और फैसले करते करवाते है। इसलिए आवश्यक है देशभर की सारी कं. जो विद्युत मंडलों को तोड़कर बनाकर इनकी लूट का अड्डा बनाई गई है। सबसे पहले इन शूकरों को खदेड़ कर बाहर करो और इंजिनियर्स को ही मंडलों का प्र.स. व अध्यक्ष बनाओ। निजीकरण और ठेकेदारी प्रथा का हर स्तर पर बंद कर, दीर्घकालिक नीतियों पर स्थाई नियुक्तियों से अपने कर्मियों की सुरक्षा और विश्वास देकर ईमानदारी से जनता का विश्वास जीतो। अन्यथा जनता की आह से हर कदम पर पूंजीवादी व्यवस्था और कंपनियां हो जाएगी तबाह। निसंदेह डकैत भा.प्र.से. के अधिकारियों जिन्हें बिजली की अब कमी नहीं आती उन्हें प्र.सं. और अध्यक्ष बनने और बनाने के बाद से ही लूट का हर कदम तांडव मचा हुआ है हर कं. में जिन्होंने अच्छे इंजिनियर्स को या तो भ्रष्ट बनने पर मजबूर कर दिया या उन्हें गर्त में ढकेल दिया है। भ्रष्ट इंजिनियर्स एसके राय जो पूर्व में सहा. यंत्री रहते निलंबित किए गया था। पुनः इंदौर में पदस्थ कर दिया है। जो सूचना के अधिकार में जानकारी ही नहीं देते। से.नि. भ्रष्ट इंजिनियर्स को पुनः संविदा पर नियुक्तियां देकर उनसे उल्टे सीधे कार्य करवाये जाते हैं। उप महाप्रबंधक पदों पर रा.प्र. शूकरों को बैठा लूट का खुला तांडव करवा जनता से मनचाही वसूली को हो रही है।

आंकड़ों की बाजीगरी में, जनता से लूट...

पेज 1 का शेष

व्यय-शिक्षा-शालेय शिक्षा 16-17 में 17094 करोड़ बढ़ाकर 17-18 में रुपए 19783 करोड़ उच्च शिक्षा में रुपए 1998 करोड़ से बढ़ाकर 17-18 में रुपए 2294 करोड़, यहां देखें चिकित्सा रुपए 846 करोड़ से बढ़ाकर 17-18 में रुपए 1367 करोड़, अर्थात एक ही मदस्वास्थ्य में भी और शिक्षा में दोनों स्थानों पर आवंटित, तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास में रुपए 780 करोड़ से बढ़ाकर रुपए 1693 करोड़ 17-18 में, अनु. जाति जनजाति में रुपए 6059 करोड़ से बढ़कर रुपए 7678 करोड़, 17-18 में कृषि बजट में रुपए 33564 करोड़, पशु पालन में 16-17 में रुपए 894 करोड़ से बढ़ाकर रुपए 1000 करोड़, 17-18, उद्यानिकी में रुपए 613 करोड़ से बढ़ाकर 17-18 में रुपए 766 करोड़, इसका 80 प्रश कागजों पर ही समाप्त, मत्स्य पालन में रुपए 81 करोड़ से बढ़ाकर 17-18 में रुपए 91 करोड़, जबकि जीतने की व्यवस्था यह कुल केन्द्रीय सहायता जो अधोसंरचना जिसमें लोक निर्माण, लो.स्वा.या., जल संसाधन और ग्रामीण विकास में मिलती है का मात्र 30 प्रश है।

2017-18 की राजस्व प्राप्तियां रुपए 1,39,115.67 करोड़, जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि रुपए 50295.21 करोड़, 2017-18 का राजकोषीय घाटा रुपए 20688.97 करोड़ होना संभावित है। इसी प्रेस नोट में यह भी लिखा गया है कि सरकार द्वारा लिए गए कर्ज पर कुल राजस्व प्राप्तियों का 8.3प्रश ब्याज भुगतान में जाएगा, अर्थात ब्याज पर रुपए 12,500 करोड़ जाएगा जबकि लिए गए ऋण चुकाने के बारे में कहीं कुछ नहीं है।

वानिकी- नर्मदा नदी के तट संरक्षण के लिए फुलदार व अन्य वृक्षारोपण के लिए रुपए 100 करोड़ का प्रावधान, जो भी लगायेगा कागजों पर लगायेगा, जो बरसात में कागज पर ही बह जाएंगे, वन विभाग में कागजों पर वृक्षारोपण के लिए रुपए 2704 करोड़, गृह विभाग में 17-18 में रुपए 5055.21 करोड़ बढ़ाकर रुपए 6304.32 करोड़ आवंटित, वेतन के रुपए 1300 करोड़ छोड़कर रुपए 5000 करोड़ हजम, वाणिज्य उद्योग एवं व्यापार में 16-17 में रुपए 3749.23 करोड़ आवंटित, वेतन के रुपए 1300 करोड़ छोड़कर रुपए 5000 करोड़ हजम, वाणिज्य उद्योग एवं व्यापार में 16-17 में रुपए 3749.23 करोड़ को घटाकर रुपए 929.17 करोड़ किए, खनिज साधन में रुपए 609.78 करोड़ के 16-17 में बढ़ाकर 17-18 में रुपए 720.51 करोड़ किए, जबकि इस विभाग से राजस्व प्राप्ति के आंकड़े और राशि सरकार अपने राजस्व प्राप्तियों में नहीं दिखाती जबकि केवल शासन के सरकारी विभाग ही हर वर्ष 60-70 प्रश की बेईमानी करने के बाद भी मजबूरन हजारों करोड़ रॉयल्टी के चुकाते हैं।

जनसंपर्क में 16-17 में 369.11 करोड़ को घटाकर 17-18 में रुपए 300.00 करोड़ किया गया। जबकि यहां बटने वाले भांडो को अकेले 2016-17 में मुद्रित व श्रृव्य-दृष्य पर अकेले रुपए 3000 करोड़ से ज्यादा व्यय किया गया जिसमें सिंहस्थ की देश-विदेश में ब्रांडिंग करने के लिए ही रुपए 2000 करोड़ से ज्यादा के विज्ञापन दिए गए थे पूरे मार्च, अप्रेल, मई-2016 में एक दैनिक को सामान्य दिवसों में 2 से 5 पेज और शाही स्नान वाले दिनों में 5-11 पेज तक के विज्ञापन देकर जनधन से लूटे धन को लुटाया गया और बजट में दिखाया गया मात्र रुपए 365 करोड़, ये बजट केवल जनता को भ्रमित करने के आंकड़ों की बाजीगरी का हिस्सा है। बुंदेलखंडी बानिये जयंत मलैया के वित्त मंत्री बनने के बाद से मु.मं. शिवराज ज्यादा वित्तीय अनियमितताओं के शिकार हुए, हर तीन माह में अनुपूरक बजट मांगे पारित की जाती के बाद अधोसंरचना, स्वास्थ्य कृषि व अन्य के खर्चों में वास्तविक कार्य हो न हो पर भ्रष्टाचार बढ़ने के कारण अवश्य बढ़ोत्तरी हुई, साथ ही खर्चों और भ्रष्टाचार रोकने की अपेक्षा कर्ज लेकर, खुले बाजार से, सत्ताधीशों के घी स्नान की आदतों में भारी वृद्धि आंकी गई साथ ही ये बजट अनुमान जब पूरे वित्तीय वर्ष के लिए होते हैं। तो क्यों जुलाई से ही अनुपूरक बजट के साथ ही 6 माह भी पूरे नहीं होते कि सरकार को खर्च चलाने खुले मार्केट बाजार में कटोरा लेकर 4500 करोड़ जनता के नाम कर्ज की भीख मांगनी पड़ती है। दूसरी ओर यदि शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन भत्तों को अलग कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार के कारण यथार्थ में जनधन से लूटा गया धन कुछ योजनाओं व विभागों में यथा लोक.निर्माण विभाग में 30 प्रश से 40 प्रश, लो.स्वा. यां. में 50 प्रश, कृषि 70 प्रश, स्वास्थ्य में 70 से 80 प्रश भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, यही कारण है कि कृषि और स्वास्थ्य में बैठे शूकरों की फौज सूचना के अधिकार में जानकारी देने के नाम पर जानकारी न देने के लिए हर हथकंडें अपनाती है जिसमें आवेदक को डराने-धमकाने से लेकर मारने-पीटने तक, ग्रामीण विकास और पंचायतों में चलने वाली लगभग 80 से ज्यादा योजनाओं का पैसा 90 प्रश तक कागजों पर ही खर्च हो जाता है, जो कि पिछली बार रुपए 13479.77 करोड़ था, 17-18 में बढ़ाकर 14387.50 करोड़ कर दिया गया यह मु.मं. चौहान से लेकर ग्रा. पंचायतों के सरपंचों, सचिवों तक की जेब में पहुंचता है, जितना प्रदेश सरकार ने आवंटित किया है उसका दुगुना अर्थात 67 प्रश पैसा विभिन्न योजनाओं से केन्द्र शासन से भी मिलता है जिसकी सब से चर्चित और भ्रष्ट योजना है मनरेगा, इसके साथ ही स्वच्छता मिशन, शौचालय मिशन, इंदिरा आवास योजना, रा.गा. जल ग्रहण मिशन, साक्षरता मिशन, स्व. जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, मध्याह्न भोजन, गर्भवती महिला पोषण आहार आदि के साथ अनेकों योजनाओं का पैसा 90 प्रश कागजों पर ही मु.का.अ. जनपद, जिला पंचायत के साथ मिलकर हजम कर लिया जाता है। इस प्रकार जनधन की जनहितों के नाम बर्बादी कर अब गावों तक भ्रष्टाचार की जड़े चुनाव जीतने के लिए गहरीकर दी गई है। जिस पर सरकार की कोई सूक्ष्म निगरानी व नियंत्रण नहीं है। उस पर कागजी आंकड़ों की फसलों से गांवों में समृद्धि का ढोल पीटा जाता है। दूसरी ओर सूचना के अधिकार में स्वयं सूचना आयोग, जो कार्यप्रणाली को सुधारने और पारदर्शिता लाने के लिए आवेदकों को प्रोत्साहित करने की अपेक्षा द्वितीय व अंतिम अपील की 90 दिन में अपील का निराकरण 3-3 वर्ष तक नहीं कर पाता फिर आवेदकों को डांट-डपट करते हैं आयुक्त, आखिर जनता से मनचाही लूट पेट्रोल-डीजल में 31 प्रश कर के बाद रुपए 4 प्रति लीटर अलग से वसूलीकर, सत्ताधीश अपने बाप की जागीर समझ हजारों करोड़ प्रसार माध्यमों में अपनी फोटो लगाकर अपनी प्रशंसा करवाने दृष्य-श्रव्य व मुद्रित प्रसार माध्यमों में बर्बाद कहां से करते हैं जबकि बजट में मात्र रुपए 300 करोड़ ही आवंटन दिखाते हैं।वही हाल कृषि बजट में किया फसल बीमा के लिए रुपए 2000 करोड़ आवंटन किया और फसल बीमा का पैसा किसानों से लेकर निजी कं. को सौंपा गया तो फिर बीमा कैसा? जबकि प्रदेश के 2 करोड़ किसानों से 2 प्रश मंडी शुल्क से भी 0.5 प्रतिशत में किसानों की फसलों का बीमा स्वयं सरकार कर सकती थी दूसरी ओर फसल ऋण देने वाली राष्ट्रीयकृत बैंक भी पिछले 40 वर्षों से फसल बीमे की किश्ते काटता है, अर्थात किसान दोनों तरफ लूटा और फसल बर्बाद होने पर मुआवजा मांगने पर शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से पिटा भी, मुआवजा भी नहीं मिला। लोकसभा, विधानसभाओं में कमजोर, अशिक्षित, विपक्ष का न होना यथार्थ में जनता व लोक तंत्र के के लिए अभिषाप है। दूसरी ओर वर्ष के 365 दिन में से मात्र 60 दिन का सदन की कार्रवाई दूसरा कड़ा अभिषाप है। उसमें भी चालबाज और धूर्त सत्ताधीश नेता किसी न किसी बहाने 90 प्रश समय पर सत्र पूरा वहीं चलने देते। ताकि उनके कुकर्मों पर आंच न आए और जनता में ज्यादा बदनामी और हो हल्ला न मचे जबकि सदन को न्यूनतम हर वर्ष 100 से 120 दिन चलाया जाना चाहिए ताकि सरकार जागरूक रह सके।

साप्ताहिक समय माया

होम्योपैथी से 1 प्रतिशत खर्च में ही स्वास्थ्य रखा जा सकता है, देश की जनता को

सबसे सस्ती, सटीक, जड़ से समाप्त करती है रोगों को होम्योपैथिक और बायोकेमिकल

भारत में केन्द्र व राज्य सरकारें स्वास्थ्य पर लगभग वर्तमान में रुपए 40 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करती है। जिसमें से रुपए 20 लाख करोड़ वहां बैठे, प्रधान सचिव, सचिव मंत्री, आयुक्तों से लेकर अंतिम बिंदू पर बैठा डॉक्टर, बाबू, कक्षकर्मी, तक डकार जाते हैं। जबकि इसके खर्च से दुगुना स्वयं जनता इन एलोपैथिक डॉक्टरों के चंगुल में फंसकर जेब से खर्च कर देती है। जबकि वास्तविक रोगों की चिकित्सा पर यथार्थ में 1 प्रश ही खर्च होता है। परंतु 95 प्रश जांचे, सीटी स्केन, इसीनी, मलमूत्र, रक्त, आदि की जांचें निरर्थक और लूट के लिए की जाती है। जिसमें जांच करवाने वाले डॉक्टर का 50 से 70 प्रश कमीशन होता है।

दूसरी ओर 90 प्रश बीमारियां वर्तमान में जो न केवल भारत में वरन विश्व के सामने आ रही है। इसके लिए स्वयं मनुष्य का बहुराष्ट्रीय कं. के लालच के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो रही है। जिसके मूल में है, कृषि में अंधाधुंध बढ़ते कीटनाशकों, खाद व अन्य रसायनों का बढ़ता प्रयोग है, जिसने हमारे न केवल 90 प्रश खाद्य पदार्थों, यथा दाल, सब्जियों, अन्न, दलहन और तिलहनों के साथ सभी फूलों चाहे व लघु, मध्यम व दीर्घायु वृक्षों या फसलों से प्राप्त होते हैं। उन्हें हायब्रिड, बायोटेकनीकली मोडीफाइड अर्थात बीटी, जेनेटकली मोडीफाइड अर्थात जीएम फसलें, जिसमें बहुराष्ट्रीय कं. का अपना घोर लूट, और वसूली का लालच था ने वास्तविकता में एक तरफ उनकी अनुवांशिक पौष्टिकता, औषधीय गुणों और मानव व अन्य प्राणियों के जैविक साम्य को बिगाड़ा और प्राकृतिक साम्य को बाधित कर दैहिक, दैविक संतुलन को नष्ट करके केवल भौतिक उपलब्धि और प्रचुरता को ध्यान में रखने से प्राकृतिक जीवों को नष्ट करने के साथ मनुष्यों में अल्पायु में ही घोर व घातक बीमारियों का कारण बनी जिससे बहुराष्ट्रीय कं. का औषधियों, उपकरणों आदि के उत्पादन बिक्री से लाभांश अवश्य बढ़ा। इसके विपरीत उनका ये तात्कालिक लाभ प्राकृतिक वनस्पतियों और जैविक चक्र को नष्ट करने में सफल रहा, इससे सहस्त्रों सूक्ष्म से लेकर दृष्य कीट, पतंगों, पक्षियों, कई प्रजातियों के सांपों, पक्षियों से बड़े पशुओं तक को नष्ट करने का कारण बना, पर इन सब स्वार्थ और मोटे लाभ के अंधों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो तो एक तरफ विषैले खाद्य पदार्थ बेंच तो दूसरी तरफ उस विष से उत्पन्न बीमारियों को दवाएं बेंचकर लाभ कमाने को ही अपना जीवन लक्ष्य मान बैठे हैं। बीमारियों की दवाएं बेंचकर लाभ कमाने को ही अपना जीवन लक्ष्य मान बैठे है। ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति यथार्थ में किसी ठोस सिद्धांत पर कार्य नहीं करती जैसा कि भारत की प्राचीन आयुर्वेद पद्धति जिसमें कि मनुष्य बीमार होता है। उसकी पुष्टि और संतुलन से मनुष्य स्वास्थ्य और निरोगी हो प्रफुल्लित हो अपने कार्यों को संपन्नन कर सकता है। शरीर का निर्माण पंचमहाभूतों यथा अग्नि, जल, वायु, आकाश और भूमि तल से निर्मित है। भारत की सनातन धर्म परम्परा के चार वेदों यथा ऋग्वेद, सामवेद, अर्थव वे और यर्जुवेद में वैसे तो चारों की वेद मनुष्य को निरोगी रखने और दीर्घायु स्वस्थ्य जीवन जीने की कला की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षता और निर्देशित करते हैं। पूरे इस वृहद ज्ञान व इसकी परम्परा को नष्ट करने, गुरूकुल पद्धति, संस्कृत अध्ययन, वेदों का अध्ययन और ज्ञानार्जन को नष्ट करने में सबसे बड़ी चाल अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कं. व अन्य तात्कालिक कं. की थी, जिसमें वो न केवल पूर्णतः सफल रही, वरन आजादी के बाद सत्ता में पाले देशी गुलामों को जो भद्र पुरुषों की श्रेणी में भ्रष्ट बनाकर उपयोग करती रही। पट्टे की स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण के समय देश में 127 अंग्रेज कं. देश में कार्यरत थी। जिसमें से अय्याश नेहा, न केवल सबसे कुख्यात कं. ईस्ट इंडिया को ही भगाया था, जो भारत की स्वतंत्रता के 67 वर्ष बाद भी देश को नोंच और बर्बाद कर रही है। जिसमें अनेकों एलोपैथिक औषधियां भी बनाती हैं। साथ हीं अंग्रेजों द्वारा स्थापित ईसाई मशिनिरियों के धर्मादा चिकित्सालयों ने भी देश की पारंपरिक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को नष्ट करने और

रोगी स्वयं बेहतर चिकित्सक बन सकते हैं, स्वयं अध्ययन करें, समझें और एलोपैथिक के डकैतों के चंगुल से बचे, कोई जांचों की जरूरत नहीं, गंभीर रोगों की चिकित्सा भी आसान

एलोपैथिक व्यवस्था को स्थाई रूप से स्थापित करने में 19वीं, 20वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान की 21वीं शताब्दी में भी भारी भूमिका अदा कर रहे हैं। इस आयुर्वेद की प्राचीन औषधिय और चिकित्सीय पद्धति से ज्यादा सटीक ज्यादा सस्ती और रोगों को जड़ मूल से साफ करने वाली होम्योपैथिक पद्धति का विकास जर्मनी के चिकित्सक हानेमन ने 17वीं शताब्दी में किया, जिसके मूल में लोहा लोहे को काटता है या विषं विषे समयंति'' अर्थात विष विष को समन करता है, इस सिद्धांत पर उन्होंने बीमारियों की चिकित्सा में सूक्ष्म मात्रा में विषों औषधियों के अर्क तैयार कर दुग्ध, शर्करा की मीठी गोलियों, में मनुष्य के मुंह से शरीर में पहुंचाकर गंभीर रोगों की चिकित्सा का मार्ग प्रशस्त कर मानव कर्कट, अर्बुद, सुजाक, उपदेश जैसे रोगों की चिकिस्ता का मार्ग प्रशस्त कर मानव मात्र के लिए अत्याधिक सस्ती और सरल चिकित्सा पद्धति विश्व को प्रदान की, इस विष विषे समयंति के सिद्धांत के विपरीत मानव के सिर बाल से लेकर पैरों के तल के तक में पाए जाने स्थूल और सूक्ष्म रूप में मात्र 12 लवणों की खोज भी जिसे 12 तक चिकित्सा या टवेल्व टिशु रेनेडीज को भी विकसित किया जिसके अनुसार पूरा शरीर केवल 12 लवणों से बनी है, जिसकी कमी से रोग उत्पन्न होते है। जिन्हें औषधि रूप में मुख से मीठी दुग्ध शर्करा के साथ आपूर्ति कर मनुष्य को निरोगी बनाया जा सकता है अर्थात वर्तमान में लाखों करोड़ का जो बजट एलोपैथिक औषधियों पर कर रही है उसका मात्र 1 प्रश बजट भी होम्योपैथिक चिकित्सा के विकास और जनता के स्वास्थ्य पर खर्च किया जाए तो पूरे भारत को निरोगी बनाया जा सकता है। परंतु एलोपैथिक चिकित्सा का शासन और निजी लूट और भ्रष्टाचार की दुकानदारी जहां लाखों करोड़ सरकार भी खर्च करती है और जनता से भी लूटे जाते हैं। सब चौपट हो जाएगी इसीलिए एलोपैथिक औषधियों पर कर रही है। उसका मात्र 1 प्रश बजट भी होम्योपैथिक चिकित्सा के विकास और जनता के स्वास्थ्य पर खर्च किया जाए तो पूरे भारत को निरोगी बनाया जा सकता है। परंतु एलोपैथिक चिकित्सा का शास. और निजी लूट और भ्रष्टाचार की दुकानदारी जहां लाखों करोड़ सरकार भी खर्च करती है और जनता से भी लूटे जाते हैं। सब चौपट हो जाएगी इसीलिए ये एलोपैथिक चिकित्सक और बहुराष्ट्रीय औषधियां और चिकित्सीय उपकरण बनाने वाली कं. इस होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को बदनाम करते है। उसमें स्टेरायड होता है, और नशे की लत लग जाती है। बेशक होम्योपैथिक सारी औषधियों को अर्को अल्कोहल में घोलकर औषधियां तैयार की जाती है। उन्हीं औषधियों की कुछ बूंदे दुग्ध, शर्करा की मीठी गोलियों पर टपका कर औषधि चिकित्सा के लिए मुंह से दी जाती है। यह पूर्णतया बकवास की है, उसमें नशा दिया जाता है। फिर एलोपैथि के सारे तरल मुंह से पीने के लिए चिकित्सा के रूप में दिए जाते हैं। सर्दी, खांसी बुखार से लेकर लीवर आदि अनेकों औषधियों स्थूल एल्कोहल में मिलाकर तैयार कर सर्दी, खांसी, अस्थमा आदि के रोगियों के दवा में विशुद्ध 3 प्रश से 6प्रश तक विशुद्ध अल्कोहल पिलाकर नशा ही पिलाया जाता है, जिसकी कफ सिरप की बोतलें शराबियों को पर्याप्त शराब का ही आनंद देती थी जिन्हें भारी मात्रा में नशीली औषधियों के विक्रय के रूप में पकड़ा भी गया था।

वर्तमान में अधिकांश होम्योपैथिक चिकित्सक इस पद्धति को बदनाम करने में न केवल लगे हुए है, वरन अपनी कमाई के लिए रोगियों से पहले सारी बीमारियों के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। फिर पूछतें हैं कि किस बीमारी को पहले ठीक करें। फिर रोगी की इच्छानुसार केवल उस बीमारी की चिकित्सा में भी ढेर सारी दवाइयों की पुड़ियां पकड़ाकर मरीजों से मोटी धन राशि ऐंठते हैं। जबकि सच तो ये है कि गंभीरतम बीमारियों में भी आधे लक्षण मरीज से जानने के बाद आधे लक्षणों को मरीज की बीमारी, चेहरे के भावों और रंगत से चिकित्सक को स्वयं सत्यापित कर सभी बीमारियों की एक ही औषधि उसकी तीव्रता यथा 1,3,30,200,1000 का आंकलन समय शरीर उग्र के हिसाब से निश्चित करना होता है। परंतु वर्तमान में बड़े-बड़े विज्ञापन श्रृंखलायें पूर्णतः प्रतिबंधित है। फिर भी पूरे-पूरे पेज के विज्ञापन देकर निराश रोगियों से केवल जांच और औषधियों के नाम पर चारों तरफ सैकड़ों केवल इंदौर के साथ प्रदेश और देश में लूटमार मचाकर भारी वसूली करने के साथ अनेकों दवायें और अनेकों बार औषधियां देकर अपनी वसूली का औचित्य सिद्धकर यथार्थ में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को न केवल स्वयं बदनाम करते हैं वरन एलोपैथिक चिकित्सों को बेलाग मुंह चलाने का भी अवसर प्रदान करते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि आम साधारण ज्ञान व बुद्धिधारी व्यक्ति इंटरनेट से या होम्योपैथिक के साधारण अध्ययन से भी छोटी-छोटी बीमारियों का अपने और अपने परिवार की चिकित्सा कर स्वस्थ रहने के साथ ही यदि वह छोटी-छोटी बीमारियों को प्रारंभ में ही समाप्त करने में सफल होगा वो बड़ी-बड़ी व गंभीर बीमारियों के खतरों को भी 90 प्रश तक टालने और बाजार में बैठे गिद्धों की फौज के चंगुल में फंसने और अपनी खून पसीने की कमाई को भी बचाने के साथ अनावश्यक आर्थिक मानसिक व सामाजिक घोर पीड़ाओं और प्रताड़नाओं से भी बच सकेगा।

आम साधारण पारिवारिक व्यक्ति यदि होम्योपैथिक की तीन-चार दवायें जैसे नक्सवोमिका जो किसी भी बीमारी के विष को प्रारंभिक अवस्था में ही समाप्त करने में सक्षम है। इससे मौसमी बीमारियों, सर्दी, खांसी, छींक, फोड़े, फुंसियां, दाद, खाज, खुजली, सिरदर्द, बदन दर्द, एलर्जी आदि ऐसे ही अर्निका 3 जो कि सभी चोटों, दर्द, मोच, जोड़ों के दर्द, सूजन आदि में , थूजा- यह औषधि 50 से ज्यादा बीमारियों यथा प्रमेहों, मूत्र रोगों, यौन रोगों से लेकर दांत दर्द, सर्दी खांसी की गंभीर चिकित्सा तक में बहुउपयोगी है। व्यक्ति अपने आंतरिक और ब्राह्य पीड़ाओं को स्वयं बेहतर महसूस कर इंटरनेट से होम्योपैथिक, औषधियों का विश्व की सभी वृहत स्तर पर उपयोग की जाने वाली भाषाओं में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है से अध्ययन कर और होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श कर औषधि सेवन कर सकते हैं। 95 प्रश बीमारियों में किसी भी प्रकार की चाहे वह ह्दय हो, पेट हो जोड़-घुटने आवश्यकता नहीं परंतु एलोपैथिक जिसे आधुनिक लूट चिकित्सा पद्धति कहते हैं। मात्र मोटा बिल बनाने और दहशत देकर लूटने के लिए शल्य क्रिया कर हमेशा के लिए शरीर को रोगी बना देते हैं। जिससे होम्योपैथिक चिकित्सा से बचा जा सकता है। बस आवश्यकता इस बात की है कि किसी सेवा भावी समर्पित, अध्ययनशील, फालतू के बाजार दिखावे से दूर, होम्योपैथिक अनुभवी चिकित्सक के सानिध्य मं या स्वयं हर दिन घंटे-घंटे अध्ययन कर औषधियों के सेवन से निरोगी और स्वास्थ्य रहा जा सके।

बारह जैविक लवण चिकित्सा में फेरमफास 3×, नेटम्यूर 30×, मैगफास 3× जैसे लवणों की 25 ग्राम की शीशी जिसमें 300 गोलियां होती है। घर में रखें जो तात्कालिक औषधि के रूप में बच्चों से बुजुर्गों को दी जा सकती है। पर इन सबके लिए भी या तो स्वयं अध्ययन करें या अनुभवी चिकित्सक का परामर्श ले लेवे, वैसे तो 12वी लवण और उनके संयुक्त लवणों की भी 28 की श्रृंखला है जिसके अध्ययन और सेवन से गंभीर बीमारियों से अपने और अपने परिवार की स्वास्थ्य की देखभाल कर दीर्घायु जीवन जिया जा सकता है। ऐसे सैकड़ों चिकित्सकों जो स्वयं तो एलोपैथी से चिकित्सा करते हैं। परंतु स्वयं के और परिवार की चिकित्सा अनुभवी होम्योपैथ से करवाते हैं। दबी जुबान से होम्योपैथी को श्रेष्ठ, सटीक सस्ती और तत्काल स्वास्थ्य लाभ देने में सक्षम चिकित्सा पद्धति मानते हैं।

बेनामी संपत्ति पर 7 साल की सजा, पहले जेलों और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाओ

पेज 12 का शेष

उनके समकक्ष इंडियन (क्राइम) प्रोटेक्शन सर्विस अधिकारी इंडियन अरेस्ट (इटिंग) सर्विस अधिकारी इंडियन रेवेन्यू (ईटिंग) सर्विसेज अधिकारी अर्थात आयकर कस्टम व एक्साइज, सर्विसेज अधिकारियों से लेकर राज्यों के मंत्रियों नेताओं, पटवारी से लेकर तहसीलदार, निरीक्षक, उप सहायक, जिलाधीशों सभी राज्य सरकारों के विभागों के निरीक्षकों से लेकर उपर सभी अधिकारियों, इंजीनियरों, डॉक्टरों, सहा., उप संचालकों, विक्रयकर आबकारी अधिकारियों जो वर्ष में रुपए 50 लाख से लेकर 5 से 25 करोड़ हजम कर सारा कालाधन अपने भाई-भतीजों से लेकर साले-साली, सास-ससुर के नाम तक से संपत्तियां कालेधन से ही खरीदते, कंपनियों अंशों, ऋणपत्रों से प्रतिमूर्तियों में निवेशित करते हैं। सबको जेल भेजने के लिए साथ ही 90 प्रश व्यापारी, 90 प्रश मध्यम श्रेणी के उद्योगपतियों जो काले धन से से ही बड़ी संपत्तियां खरीदते है जो कि देश में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा होंगे, जेल भेजने के लिए पहले सरकार को देश वर्तमान 1500 के लगभग जेलों को कम से कम 5000 करना चाहिए, और न्यायालय लगभग 8000 की संख्या बढ़ाकर 25000 करना चाहिए ताकि शोषण निर्णय किए जाकर शीघ्र कालेधन पर लगाम लगाई जा सके, दूसरी तरफ सरकार व राज्य सरकारों में बैठे इतने अधिकारियों की जांच के लिए भी पहले हर वर्ष वर्तमान डेढ़ करोड़ कर्मचारियों और अधिकारियों की अपेक्षा कम से कम 3 गुने कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती की व्यवस्था करना चाहिए ताकि हर वर्ष 50 से 70 प्रश स्टॉफ को कालेधन और बेनामी संपत्ति के आरोपों में गिरफ्तारी से शासन तंत्र पर दैनिक कार्यों पर असर न पड़े।

इस सबके पूर्व पहले हम ये देखें कि पहले से भारत की केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों में इस संबंध में लागू कानून, उसकी व्यवस्थाओं, उसके अंगर्तत लंबित पड़ी जांचे, उसमें घिरे और फंसे महाधूर्त इंडियन एब्यूसिंग सर्विस के ही अधिकारियों जैसे सुधी रंजन मोहंती, राजेश राजौरा, थेटे, शशि कर्णावत, आशुतोष अवस्थी जैसे सैकड़ों पर कहीं न्यायालयों में लोकायुक्त आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो में, जांचे वर्षों से लंबित है। क्या हुआ 99 प्रश शान से सत्तासुख भोग रहे हैं। सारे हरामखोर बिकाऊ है। जैसे भ्रष्टाचार से धन कमाया था, धन लुटाकर शान से बैठकर अब दुगनी लूटपाट कर रहे हैं। जबकि 99 प्रश सब ही अरविन्द जोशी और टीनू जोशी है। 90 प्रश हजारों करोड़ के मालिक है।

90 प्रश के पास सैकड़ों करोड़ की देश में और देश के बाहर सैकड़ों देशों में बेनामी संपत्तियां भी है, ये हाल भारतीय शासकीय सेवाओं से लेकर राज्यों की सेवाओं के भी है। इनकी जांच कौन करेगा जो जांच करेगा वो सब भी तो भ्रष्ट हैं। चाहे वो लोकायुक्त हों, आर्थिक अन्वेषण ब्यूरों, केंद्रीय भाजपा जांच ब्यूरो, फिर जो जितना बड़ा भ्रष्ट उतना बड़ा मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री, क्या हुआ मप्र के मु.म. शिवराज मामा का सैकड़ों डंपर होशंगाबाद के गांवों से रेती ढो रहे हैं। व्यापमं घोटाले का सरगना, जिस कांग्रेसी ने सच बोला उल्टे ही उस पर केस थोप दिया, कितनी हत्याएं हुई, प्रोफेसर से लेकर छात्रों, पत्रकारों की कितने पकड़े गए, फिर न केवल केन्द्र में किस मंत्रालय में भ्रष्टाचार रूक गया जो राज्यों में रूक जाएगा, उल्टे ही हर मुख्यमंत्री, मंत्री यह देखता है, कि मलाई वाला विभाग कौन सा है, जहां अधिकतम लूट पाट कर धन एकत्रित कर बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल बनवाए, इंजीनियरिंग कॉलेज स्कूल खोले, खेती की जमीन हड़पे-खरीदे काहे की नामी-बेनामी काहे के कानून सब जेब में सब टुकड़खोर श्वानों के टुकड़े डालो और सब कानूनों का भोंकना रोक दो। फिर कानून बनाए किसने और कानून की परिभाषा क्या है? तो कानून की पारंपरिक परिभाषा से यथार्थ की भाषा में, कानून धूर्तों के बनाए शब्दों के मायाजाल हैं। जो अपनों के पोषण और निरीहों के शोषण के, सत्ताधीशों के हथियार हैं।

मप्र वाणिज्यकर चारों तरफ भ्रष्टाचार और जालसाजियों का तांडव

हजारों करोड़ के कर वसूली की फाइलें गायब, जप्त संपत्ति का जवाब नहीं

सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर साफ इंकार, लेन-देन कर करोड़ों की फाइलें नष्ट कर दी जाती है। पूर्व आयुक्त व्ही.पी. त्रिवेदी ने करोड़ों रुपए की गोदरेज नकली अलमारीयां व फर्नीचर खरीदा। सन् 2003-4, 04-05, 05-06 में रुपए 650 करोड़ के पेट्रोलियम घोटाले की कितनी वसूली हुई

मप्र वाणिज्य कर के इंदौर मुख्यालय की नाक के नीचे भ्रष्टाचार और जालसाजियों के कितने बड़े-बड़े खेल होते हैं। जिसमें नीचे निरीक्षकों, सहा. वा. कर अधिकारी से लेकर ऊपर आयुक्त, मंत्री तक सब शामिल होते हैं। इसलिए कोई किसी की बात नहीं करता उल्टा ही एक-दूसरे को बचाने में लगे रहते हैं। क्योंकि मामले की जड़ तक जाने में बारीकी से छानबीन करने में सैकड़ों नए राज खुलने और सबके लपेटे में आने का डर सताने लगता है। जबकि पुराने अधिकारियों ने जिन्होंने ग्वालियर, इंदौर से नगद कर की वसूलीयां कर लाखों रुपए हजम किए। रसीदें भी जारी की और पैसा भी बैंकों में जमा नहीं किया गया प्रकरणों में जांच भी हुई, परंतु अंत में सभी बचा लिए गए, इसी प्रकार सेवानिवृत्ति उपायुक्त सोनवलकर, टीके व अन्य जो फर्जी तरीके से निरीक्षक से सीधे वा.कर अधिकारी की सूची में नाम जुड़वाकर वा.क.अ. बन गए थे, मामला उठा, निचले न्यायालय ने दोषी माना, तो उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर फैसला अपने पक्ष में ले लिया, उसके विरुद्ध भी शासन ने याचिका सर्वोच्च न्यायालय में अधिकारियों ने पैसे हजम कर, नहीं की, उपायुक्त के पद से निरोधक दस्ते से सेवानिवृत्ति होने के बाद भी बंदा सोनवलकर 4-6 माह तक खुलकर वसूली करता रहा यह जानकर भी विभाग ने भी कोई कार्रवाई नहीं की।

यही हाल संचालक के पद पर पदस्थ एनएस मरावी, जिसके विरुद्ध जालसाजियों और भ्रष्टाचार के प्रकरणों थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल होने के बाद भी यह बंदा भी आरक्षण के दम पर पदोन्नतियां पाता हुआ, संचालक के पद पर विराजमान है, जबकि उन प्रकरणों में कार्रवाई उचित तरीके व सही समय पर की जाती तो शायद घर बैठे होते, परंतु प्रशासनिक ढीलेपन के चलते संचालक का पद संभाल रहे है।

अति. आयुक्त के पद पर बैठे राजेश बहुगुणा को भी वर्षों में इंदौर में हो गए, बंदा सारे नाकों से पदस्थापना स्थानांतरण में जिसका मोटाधन उसके ही नाके पर बैठाया जाता है। फिर एंटी इवेजन ब्यूरों में मप्र की सारी इकाइयों में पदस्थापना स्थानांतरण आदि के काम में भी बंदा दोनो हाथ से वसूली कर रहा है। यही कारण है कि इंदौर की ए इकाई में मोटी वसूली के लिए वा.क.अ. और सहायक आयुक्त की महीनो के बाद भी पदस्थापना नहीं की है। सूत्रों के अनुसार बहुगुणा ने इंदौर में वाणिज्यकर में अति. आयुक्त का पद संभालने के बाद मोटा विनियोजन शॉपिंग काम्पलेक्स भवन बनाने के साथ ही जनवरी में एक बड़ी दुकान का उदघाटन देहरादून में किया है। शासन को यथार्थ का पता लगाकर आय से अधिक संपत्ति के बारे में स्त्रोतों का पता करना चाहिए,

पूर्व में आयुक्त विश्वनाथपति त्रिवेदी ने अपने कार्यकाल में करोड़ों रुपए अलमारियों व अन्य फर्नीचर खरीदा था जो कि पूर्णतः मिस ब्रांडेड था, जिसमें मोटा कमीशन हजम किया गया था। क्यों अलमारियों में न तो गोदरजेज के असली ताले हैं न ही गोदरेज के स्तर की मोटाई की स्ट्रिप जिससे अलमारियां बनी है। वही हाल मेजों की ड्राज में उस स्तर के ताले है न उस स्तर की बनावट, पर सब जानकर भी विभाग के उच्च अधिकारी सब चुप्पीमारे बैठे हैं। अर्थात भ्रष्टाचार हर स्तर पर पल्लवित व पोषित किया जाता है।

सूचना के अधिकार में प्रदेश के अधिकांश संभागों से जानकारी मांगी गई थी। 90 प्रश ने तृतीय पक्ष बताकर एकमुश्त देने से मना कर दिया जबकि प्रवेश कर, वा. कर, वेट आदि में हर दिन औसतन आधिवय के नाम पर करों की वापिसी की जाती है जो 1 से 5 प्र.श. तक हो सकते है। बिना लेन-देन के कराधिवय का भुगतान नहीं किया जाता है। यदि बारीकी से करो की वापिसी का मूल्यांकन किया जाए 70 प्रश कर वापिसी योग्य नहीं होती है। क्योंकि करदाता इतना मूर्ख भी नहीं होता कि साथ ही न ही उसके पास धन जो उसने बिक्री पर करों से वसूला होता है, कि वो उसकी तिजोरी से बहर कूद रहा होता है, जिसे शासन के पास जमा करवाना उसकी मजबूरी बन जाए, चूंकि वहां भारी कर वापिसी में भ्रष्टाचार होता है लेन-देन के बाद ही लौटाया जाता है। यही हाल आईटीआर में भी होता है, जिसमें इससे शासन को करोड़ों की धन हानि होती है। यही कारण है कि ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना में बैठे धूर्त, जालसाज, हरामखोर, शूकरों की फौज हर जानकारी को तृतीय पक्ष की जानकारी कहकर साफ मना कर देती है। अपील करने पर उनके ही वरिष्ठ अधिकारी चूंकि स्वयं न केवल भ्रष्ट और महाजालसाज है। वरन अनेकों जांचों को भी फाइलों में दफन कर व करवा चुके है, से.नि. शिवहरे स्वयं ने 27 हजार का रिफंड रुपए 1 लाख से ज्यादा करवाया था। एलजी इलेक्ट्रानिक्स का तो स्वाभाविक था सारी अपीलें किसी न किसी बहाने रद्द कर दी जाती थी। अब यही हाल संचालक पद पर बैठे मरावी जो स्वयं भ्रष्ट और अनेकों एफआईआर में नामदज आरोपी है। हर अपील में अपने अधीनस्थों को बचाने एक मुस्त रद्द कर दिया, वही अपर आयुक्त राजेश बहुगुणा करेंगे।

सूचना अधिकार के पैमाने पर कम से कम वाणिज्यकर में तो मुख्यालय से लेकर नीचे तक 80 से ज्यादा वृत्तों में कोई ईमानदार और खरा नहीं निकला, इंदौर के 10 नंबर वृत्त में पत्र देने पर रुपए डेढ़ से दो हजार तक मांगे गए, समय बाधित होने से जब जानकारी दी गई तो मात्र 80 से 90 पेज की ही जानकारी निकली। स्पष्टतः यह अपराधिक प्रकरण न्यायालय में भा. दंड संहिता की 6 से ज्यादा धाराओं में प्रकरण लगाए जाने योग्य था। सं. 3 का उपायुक्त जिसने 15 वर्ष से ज्यादा की सेवायें धन, बल के दम पर इंदौर में ही पूरी कर ली, ये और इसके सभी वृत्ताधिकारी, सहा. आयुक्त भी हर जानकारी न तो स्वयं देतेहैं और अपील लगाने पर ये जालसाज हरामखोर भी बड़ी आसानी से हर अपील निरस्त कर देता है। फिर इसी का मोटा कमीशन रुपए 1 लाख प्रति माह का चेतक चेंबर के किराये में, जो अफीम गोदाम में वाणिज्य कर का स्वयं का भवन नहीं बनने दे रहा है क्रमांक 13 की वृत्ताधिकारी पूर्णिमा चौरसिया के भी हर कर पुर्नभुगतान की, पुरानी फाइलों की, वृत्त 9 के, दीपक श्रीवास्तव की पुर्न भुगतान और फाइलों, वृत्त 11, 10 आदि पुराने वृत्तों के पुर्न भुगतान व फाइलें जिनमें भारी केन्द्रीय, प्रवेश वाणिज्यिक व वेट की बकाया थी जांच की जाए तो मालूम पड़ेगा कि सैकड़ों फाइलें या तो रद्दी में बेंच दी गई, या नष्ट कर दी गई लेन-देन करके।

सन् 2000 से 2006 के बीच हुए रुपए 650 करोड़ के घोटालों और कर अपवंचन में कौन-कौन से अधिकारी कर्मचारी शामिल थे, कर अपवंचन के इस मामले में अनेकों अधिकारी तो सेवानिवृत्ति पा चुके है। जबकि कर अपवंचन करने वाली अधिकांश फर्मों के कर्ता-धर्ता नाम बदलकर दूसरा व्यापार कर रहे हैं। इनके पास करोड़ों की संपत्तियां कितनी अधिग्रहित कर नीलाम की गई, ऐसे सैकड़ों कर अपवंचन कर चोरी की फाइलें ही नष्ट कर दी जाती है। या ओने-पोने रद्दी में बेंच दी जाती है। यह हाल इंदौर का है, जबकि ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, सागर, रतलाम, छिंदवाड़ा आदि के उपायुक्तों से लेकर सभी वृत्ताधिकारी भी ऐसे हजारों कारनामों को पिछले 30 वर्षों में अंजाम दे चुके है। वर्तमान आयुक्त अमित राठौर भी महाधूर्त, अय्याश, जालसाज, प्र.स. मनोज श्रीवास्तव की कठपुतली बन येन-केन प्रकरेण इंदौर मुख्यालय में कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। ये भी विभाग के भ्रष्टाचार में अंकुश लगाने की तो दूर अधिकांश अधिकारी, सहा. आयुक्त उपायुक्त तीन वर्ष से ज्यादा समय से एक ही स्थान पर बैठे आंख भींच वसूली में जुटे हैं। उनका स्थानांतरण तक नहीं कर सके है।

मप्र के वाणिज्यकर वृत्तों में वृत्ताधिकारियों द्वारा कर वसूली के विरुद्ध संपत्तियां राजसात कर नीलामी करने का प्रावधान है। परंतु प्रदेश के अधिकांश वृत्तों में संपत्तियां देख करों के विरुद्ध अटैच कर ली गई, संपत्तियों को वृत्ताधिकारी सालों तक मोटा धन वसूल कर, टालते रहते हैं। जिससे शासन को मोटे धन की राजस्व हानि होती है।

इसी प्रकार स्वकर निर्धारण प्रकरणों को 31/10 तक आवंटित हो जाना चाहिए। 30 नवम्बर तक उनका चयन हो जाना चाहिए। लेकिन विभाग में ये प्रक्रिया 31 दिसम्बर तक चलती रहती है व पूरे वृत्त कार्यालयों से लेकर संभागीय आयुक्त कार्यालयों तक जिसमें स.वा.क.अ., वा.क.अ., स. आयुक्त व उपायुक्त तक मिलकर सब गलत जानकारी देते रहते हैं। जो कि मप्र के हर वृत्त में फर्जीवाड़ा चल रहा है।

हर वृत्त कार्यालय में कर वसूली पूरी तरह कर डायरी में नहीं लिखी जाती वसूली पंजी पूर्णतः भ्रमित करने वाली होती है। वृत्त अधिकारियों द्वारा 11.12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16 के वृत्ति कर के प्रकरण संस्थापित नहीं कराए गए न ही निवर्तमान नियमानुसार किया गया है। जिसकी जांच स्वयं आयुक्त बारीकी से कर सकते है। प्रत्येक अधिकारी द्वारा वा.क.अ., सहा. आयुक्त, उपायुक्त कार्यालय का निरीक्षण, प्रतिवेदन, रोस्टर तैयार किया गया है। वह पूर्णतः असत्य है। इसमें वृत्त कार्यालयों का अनियमिततााओं का लेन-देन कर छुपा लिया जाता है। जिन्हें आयुक्त स्वयं जांच करें जिसमें निरीक्षणों की त्रुटियां नहीं दशाई गई हैं। समयमाया ऐसी अनेकों त्रुटियां बता सकता है जो भारी भ्रष्टाचार से संबंधित होने के कारण जानबूझकर छुपाई गई है। इसी प्रकार अनेकों वृत्तों द्वारा विनिष्टीकरण का किए गए दस्तावेजों, फाइलों का रिकार्ड व उचित तरह से नहीं रखा गया, साथ ही दस्तावेजों को पुराना बताकर बैचे गए रिकार्ड की रद्दी को भारी कम कीमतों में बेचना दिखाकर बीच में बंदरबांट की गई, यही कारण है कि हर वृत्त कार्यालय में, सहा. आयुक्त व उपायुक्त कार्यालयों मुख्य रूप से इंदौर संभाग 3, भोपाल 1 व 2, सतना, ग्वालियर सं.क्र. 1,2, जबलपुर सं. 1 व 2 में वर्षों से अजगरों की तरह कुंडली मारे बैठे उपायुक्त जानकारी देने की अपेक्षा ये धूर्त जालसाज सु.अ. के पत्र ही पी जाते हैं या भोपाल में बैठे 1 व 2 के उपायुक्त 5-5 पन्नों के औचित्यहीन दलीलों के जवाब भेजकर अपनी भ्रष्ट, जालसाजी पूर्ण, धूर्त मानसिकता का ही परिचय देते हैं। फिर अपीलीय अधिकारी चूंकि स्वयं भ्रष्ट होने के साथ महीना वसूली करते हैं। इसलिए अपने मातहतों को बचाने, बहाने बनाकर अपीले रद्द कर देते हैं। क्योंकि जितना कर राजस्व मिलता है वह मात्र 30 से 40 प्रश ही होता है। 10 से 20 प्रश राजस्व यहां बैठे अधिकारी हजमकर स्व्यं व्यापारियों और करदाताओं को राह दिखाकर चोरी करवाते हैं। इसलिए स्वाभाविक है ये भ्रष्ट जानकारी न देने के बहाने ढूंढते है और आवेदकों को हतोत्साहित कर उनका आवेदन देने से लेकर अपील लगाने और सुनवाई तक तिरस्कार का पात्र बनाते है। इसीलिए सूचना अधिकार कानून में आवेदक को ससम्मान आवेदन लेने और ससम्मान जानकारी देने की धाराओं में उल्लेख है। जबकि आयुक्त व शासन को अपने स्तर पर चाहिए कि जो अधिकारी जानकारी देने की अपेक्षा उल्टी सीधी दलीलें देकर 4-5 पेजों के जवाब भेजकर जानकारी देने से बचते हैं। स्वयं शासन को ऐसे अधिकारियों के क्रियाकलापों पर नजर रखकर उनके 10 से 25 प्रश कर निर्धारण की जांच वरिष्ठ अधिकारियों से करवाकर अरबों रुपए के राजस्व की हानि के आरोप पत्र दे कर उनकी विभागीय जांच करवाकर, निलंबन से लेकर सेवाओं से मुक्त कर उनके भविष्य और पेंशन भी जप्त कर बिदा कर दे। यह सुझाव शासन भले ही आजमाने पर भविष्य में इस पैमाने पर कार्य करना ही होगा।

तानाशाह रक्त पिपासु मोदी निचोड़ देगा जनता को हर तरह से

पेज 12 का शेष

जहां तक मीडिया का सवाल है, जनता से अंबानी द्वारा पेट्रोल, डीजल, गैस, मोबाइल सेवाओं में तिगुनी लूट के पैसे देश का मुद्रित व दृष्य-श्रव्य श्रृंखलाये सबको अंबानी गिद्धों ने खरीद लिया है तो सत्य दिखाना भूल चुके है वो केवल आकाओं के पूर्णतः भांड बन, उनकी ढपली से उनके राग ही सुना रहा है। नोटबंदी से भीषण बर्बादी का सच जनता के सामने नहीं आने दिया, उल्टे ही पूर्णतः जालसाजी से जीती उप्र, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर को नोटबंदी की सफलता के रूप में भुनाया जा रहा है। प्रसार माध्यम इस झूठ की यज्ञशाला में बढ़ा-चढ़ा भाजपाइयों को बुला, साक्षात्कार दिखा सारी जालसाजियों का सत्य सिद्ध करने पर तुले है। विज्ञापन में पेटीएम का विज्ञापन में अपनी गुलामी और ओछी मानसिकता का परिचय दे ही दिया बाद में दिखावे के लिए उनसे माफी मंगवा दी, यही हाल इसने भाजपाई चुनाव प्रसार में भी किया। गली-गली मोहल्ले में जाकर सभाओं के साथ खुले वाहन में रोड शो भी किया, कल तक झाड़ू लगाने वाला संघ कार्यालय में प्रधानमंत्री बन गया तो मानसिक स्तर थोड़े ही सुधर गया।

रेलवे को अब सरकारी कं. पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति नहीं करती हैं। अब रिलायंस न केवल रेलवे को वरन विमानों में भी आपूर्ति करता है। जिसके स्तरहीन पेट्रोल डीजल के कारण विमानों और डीलज रेल इंजनों का खर्च व रखरखाव भी बढ़ गया है। अब रेलवे गरीबों की यात्रा कर साधन नहीं वरन अमीरों जो विमान यात्राओं की तरह सीटें और आरक्षण बढ़ने के साथ किराएं की दरें भी बढ़ जाती हैं। खाद्य सामग्री में वह तो तब से नहीं चला और समयमाया की लगातार पहल के कारण खाद्य सुरक्षा व मानक अधि. 2006 यदि पूर्णतः लागू हो जाता तो न केवल दालें जो रुपए 50 प्रति किलो दाल की तरह रुपए 250, शक्कर 100 प्रति किलो, खाद्य तेल रुपए 200 प्रति किलो तक बिकवा दिया जाता, बेशक दूसरी तरफ हर वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों ने इसकी मनमानी पर अंकुश लगा रखा है। फिर जनता ने ढाई वर्ष में खूब देखे हैं। दोनों दानवों मोदी और शाह की झूठ, मक्कारी, लफ्फाजी और 125 करोड़ जनता के छल-कपट के किस्से कहानी, बदले में अंबानी, टाटा और बहुराष्ट्रीय कं. की बढ़ती दानवी लूट चारों तरफ बढ़ती बेरोजगारी, बंद होते उद्योग, धंधे, जीएसटी के प्रावधानों से सुरक्षा, लघु मध्यम स्तर के उद्योग धंधे, दुकानें, 60 प्रश तक बंद हो जाएगी। तब मोदी के यथार्थ का पता लगेगा, गुजराती धूर्त जिस तरह से सत्ता हथियाकर हर शासकीय संस्थान का निजीकरण कर अपने गुजराती बाप अंबानी बंधुओं को सौंप मोटा अरबों करोड़ का कमीशन बटोर पूंजीवाद की तरफ धकेलने पर तुला है। जिस तरह जनता के घोर शोषण की दीर्घकालिक व्यवस्था करने में जुटा है। वह शोषण की घुटन से इस देश का हाल भी सोवियत रूस की तरह न हो जाए, इस राष्ट्र के समग्र विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यस्था ही कारगार होगी।

साप्ताहिक समय माया

मप्र लोक भ्रष्टाचार निर्माण विभाग

हर कदम जालसाजियों का अंबार-ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार

भ्रष्टों जालसाजों को बचाना मोटी वसूली करना, अनेकों लोकायुक्तों के छापों में पकड़ें राणे को भी दो माह बाद हटाया

मप्र लोक निर्माण विभाग में भोपाल के मुख्यालय में बैठा प्रमुख अभियंता अखिलेश अग्रवाल ही घोर भ्रष्ट और जालसाज हैं,तो स्वाभाविक है कि अपने विभाग में सभी भ्रष्टों और जालसाजों के जो उसे आवंटन में महीना देते हैं। उनको बचायेगा ही चाहे वो ठेकेदार हो या उसके अधीनस्थ मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन सहायक से लेकर उपयंत्रीयों तक। चाहे वो लोकायुक्त में ही क्यों न पकड़े जा चुके हों, सरेआम रिश्वत लेते या आय से अधिक संपत्ति के मामलों में, पकड़े जाने के तुरंत बाद उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए और स्थानांतरण किया जाना चाहिए। पर निलंबन की तो दूर स्थानांतरित भी नहीं किया जाता।

वरन दंडात्मक कार्रवाई करने के विपरीत उन्हें बचाने का षड़यंत्र शुरू हो जाते हैं। जबकि ऐसे अधिकांश इंजिनियर्स की सैकड़ों शिकायतें जो वर्षों से ठेकेदारों द्वारा जनता द्वारा वरन वरिष्ठों द्वारा किए जाने पर भी ऐसे हरामखोर जालसाजों को महीना और आवंटन व दूसरे कार्यों में हिस्सा मोटा होने और मिलने के कारण हर शिकायत रद्दी की टोकरी में फेंक उल्टे ही उनकी पदोन्नतियों से नवाजा जाता है, जैसे वर्तमान मुख्य अभियंता आरके व्यास की सहायक यंत्री काल से लेकर मुख्य अभियंता रहते तक सैकड़ों जालसाजियों और भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई जांचे हुई, कई बार निलंबन की तैयारी की गई पर हर और भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई, जांचे हुई कई बार निलंबन की तैयारी की गई पर हर लूटने और लुटाने से बचाने वालों ने उसे हर बार बचा लिया, वरना इंदौर के राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभारी रहते हुए लगातार 4-5 माह तक रुपए 80000 से 1 लाख तक की टोल चोरी में ही निलंबन की तैयारी हो चुकी थी। अब जबकि भोपाल परिक्षेत्र मुख्य अभियंता है। बैतूल, होशंगाबाद जिलों की सड़कों में भारी भ्रष्टाचार करवाकर धन हजम किया गया।

जांच में प्रधान सचिव प्रमोद अग्रवाल को भी पाया कि स्तरहीन कार्य में भ्रष्टाचार हुआ, परंतु प्रअ अखिलेश अग्रवाल के व्यास से घरेलु संबंधों के चलते पुनः अग्रवाल ढाल बनकर बचा ले गए। प्र.स. व प्र.अ. अग्रवालों ने मोटे धन के चलते उसे प्रमुख अभियंता बनाने के लिए वरिष्ठता सूची में आगे रहने वाले मुख्य अभियंताओं के झूठे शिकायती जांच के आवेदन लगाकर उनकी पदोन्नति रोक व्यास को ऊपर लाया गया, जबकि व्यास इंदौर में एक मकान को फर्जी तरीके से हथियाने के चक्कर में भी अन्नपूर्णा थाने में हुई एफआईआर में भी आरोपी है। इसके विपरीत भ्रष्ट प्र.स. प्रमोद अग्रवाल सचिव च.प्र. अग्रवाल, प्र.अ. अखिलेश अग्रवाल मंत्री रामपाल सिंग सब जानकर उस भ्रष्ट जालसाज को बचाने वरन प्रमुख अभियंता बनने में लगे है।

दूसरी तरफ इंदौर में 69 वर्ष से ज्यादा समय से जमे ईई. प्रकाश राणे, जिसका जाति प्रमाण पत्र ही फर्जी है। बेकलॉग से नौकरी में आए। आने के 6 माह बाद से ही कारगुजारियां शुरू कर दी थी। बिना विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में मामले की छानबीन किए ही, जो वरिष्ठों की वि.प.स. की बैठक में निर्णय लिये गये। इसमें भी प्र.अ. और मुख्यालयों में बैठा जालसाज, महाभ्रष्ट और हरामखोर स्टॉफ मोटा पैसा हजम कर उसे जामि प्रमाण पत्र और वि.प.स. की बैठक की कार्रवाई की जानकारीनहीं दे रहे हैं, पिछले दस साल से और इसके साथ अप कुकर्मों को भी बचा रहे हैं। हाल में इसके पड़े छापे में इसके निवास स्थान के पड़ोसी सूत्रों के अनुसार इसे तो छापे की कार्रवाई की सूचना लोकायुक्त कार्यालय से मिल चुकी थी, इसीलिए दो दिन तक लगातार सारी नगदी, सोना व ग्वालियर, धार, देवास, भोपाल, इंदौर की संपत्तियों के जो दूसरे रिश्तेदारों के नाम से खरीदी गई थी, सारे दस्तावेज व नगदी दांये-बाये करने में सफल रहा। जबकि इस हरामखोर के पास सूत्रों के अनुसार दो अरब से ज्यादा की संपत्ति है। इसने देवास 03-06 देवास 06-08 इंदौर से क्रमांक 2, 8 से 11, संभाग 1, 11 से 14 तक, 14 से 17 परि. ईकाई में रहते हुए हजारों बड़े कार्यों को रुपए 2 लाख में परिवर्तित कर 20 प्रश अनुपूरक स्वीकृति, 90 प्रश में रायल्टी आयकर, वाणिज्यकर, संनिर्माण कर्मकार, कल्याण शुल्क काटे बिना भुगतान कर 50-50 पैसा ठेकेदार और स्वयं ने हजम किया, फर्जी तरीके वर्कचार्ज कर्मियों का ईपीएफ डकार हजम कर लिए गए। रंगाई, पुताई, सफाई जिसके 4 हजार से ज्यादा सरकारी बंगलों, क्वार्टस का पैसा हजम किया गया। 4 संभागों में सड़क मरम्मत के कार्यो में हरामखोर जालसाज ने 40 से 50 प्रश तक पैसा डकारा गया, सारे अधिकारी अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंता, प्रमुख अभियंता, प्रमुख सचिव, मंत्री व मुख्य मंत्री, संबंधित जिलों के जिलाधीश, संभागायुक्त, विधायकों, पत्रकारों को जो बड़े समाचार पत्रों से थे सबको यथा योग्य बांटा गया। यहां तक कि जीतू पटवारी ने प्रश्न लगाये पैसा मिला, प्रश्न वापिस ले लिया, सूत्रों के अनुसार इसके गिरोह में पूरे मप्र के आरक्षित वर्ग के सारे कर्मचारी अधिकारी तक पैसा देकर जो रुपए 5 करोड़ तक होता था, सर्वोच्च न्यायालय में तारीख बढ़वाने में 1 से 2 घंटे में भेज दिया करता था। ताकि सामान्य वर्ग प्रकरण न जीत सके और न उनकी पदोन्नतियां हो सकें, प्र.अ. अखिलेश अग्रवाल हरामखोर जालसाज, जो पैसा और संबंधों का फायदा उठाकर कैसे का. यं. से सीधा बिना अधीक्षण व मुख्य अभियंता विभाग में बैठे थे, स्वाभाविक था जो करोड़ों रुपए खर्च करके प्रमुख अभियंता का पद हथियाया उसमें घोर जालसाजों से ही धन बटोरा गया था। कम्प्यूटराइजेशन के नाम सारे प्रमुख अभियंताओं और अधीक्षण यंत्रियों के पंजीयन निविदा स्वीकृति के अधिकार छीन, सीधा करोड़ों की वसूली के साथ ही अपने खास ठेकेदारों का ठेके देने के लिए कम्प्यूटराइज्ड और ऑनलाइन व्यवस्थाओं भी कर ली गई है। साथ ही महाभ्रष्ट सहायक यंत्रियों को जैसे दीपेश गुप्ता देवास, भूतड़ा शाजापुर आदि 25 से ज्यादा को मासिक वसूली पर का.यं. का प्रभार सौंप दिया गया है। पूर्व में समयमाया ने प्रकाशित किया था कि कैसे प्र.अ. अखिलेश अग्रवाल ने महाभ्रष्ट जालसाज आरके व्यास को मुख्य अभियंता और वरिष्ठ अभियंता सावला श्रीवास्तव आदि को विभिन्न कारण दिखाकर आरके व्यास को प्रमुख अभियंता बनाने का खेल चल रहा है।

प्रदेश में 16-17 में अनेकों का.यं. सहा. व उपयंत्री रिश्वत लेते पकड़े गए। सबको मोटा धन लेकर बचा रहा, बस स्थानांतरण देकर इतिश्री कर ली जाती है। इस विभाग में पूरे प्रदेश में हजारों, सैकड़ों उपयंत्री, सहा. यंत्री वर्षों से एक ही स्थान पर कुंडली मारे बैठा रखे हैं। सबके अपने निजी आवास हैं। इसके विपरीत अधिकांश सरकारी मकानों में निवास कर अपने मूल वेतन का मात्र किराया वसूलती है। सरकार धारा 45 अ में जबकि स्वयं के निवासधारी से 45 ब में 20 प्रश किराया वसूलना चाहिए सरकार को। इससे अकेले भोपाल शहर में 60 प्रतिशत कर्मचारी अधिकारियों से करोड़ों रुपए की आय शासन को मिल सकती है और प्रदेश में 2 लाख कर्मचारी अधिकारियों से जो स्वयं के निवासधारी होने के बाद भी सरकारी आवासों में निवास कर रहे हैं। प्रतिमाह 200 करोड़ रुपए कानूनन वसूलने की पात्रता है सरकार को। अधिकांश शासकीय भवनों की देखरेख व रखरखाव का जिम्मेदारी लो.नि.वि. का ही होता है। इसके साथ ही स्वयं के निजी आवाजों से प्राप्त आय को भी अधिकांश अधिकारी कर्मचारी अपने आयकर विवरणी में नहीं दिखाते हैं। जबकि वह कर योग्य आय होती है। सूचना के अधिकार में ये जानकारी मांगी गई तो धूर्तों की फौज जो मुख्य अभियंता कार्यालयों में बैठी है मात्र वहां पदस्थ कर्मचारियों अधिकारियों का आवास जो सरकारी था उसके वेतन पत्रक जिसमें किराया कटोत्रा 10 प्रश दिया व दर्शाया गया था। पैसे वसूलकर दे दिया गया, जबकि का.यं. कार्यालय से प्राप्त जानकारी ने आवास आवंटन समिति का अध्यक्ष मुख्य अभियंता, सचिव अधी यंत्री, होकर हर आंवटन पर हस्ताक्षर करता है। वही हाल लो. स्वा.यां., जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालयों का भी था।

प्रधान सचिव प्रमोद अग्रवाल के सहा. यंत्रियों व कार्य. यंत्रियों से सीधे वसूली के बड़वानी व शिवपुरी के कांड समाचार पत्रों में छप चुके हैं। तो उनके कनिष्ठों का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर मंत्री राम पाल सिंग तो पिछले वर्ष ही आया है और अगले साल चुनाव है, कार्य करे या कार्यवाही करे। वैसे इंदौर में परिचय सभा में वादा करके गये थे। सड़क डकैत निगम में से तीन पदों को संभाल रहे बौरासी को हटाने की मोटी वसूली कर चुप।

अंग्रेजों के राजस्व वूसली एजेंट, पट्टे की आजादी में देश के खुदा बन लूट रहे जन-धन

महाभ्रष्ट, तानाशाह सबसे बड़े जालसाज होते हैं, जिलाधीश व जि पं. मु.का.अ.

खनिज, आदिम जाति, कृषि, उद्यानिकी, लोक निर्माण, लो. स्वा.यां., महिला बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खा.व.ना. आपूर्ति, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, पंजीयन, परिवहन, समाज कल्याण आदि में हिस्सा और जमीनों के हेर-फेर में मोटी कमाई के चलते घोर भ्रष्टों को पालना संरक्षण देना, सू. अधिकार में जानकारी मांगने पर हड़काना आवेदकों को ताकि इन हरामखोरों के भ्रष्टाचार जनता न जान सके

भारत को पट्टे की आजादी दिलाने के बाद से सबसे ज्यादा जो उचट के लगी कि अंग्रेजी शासन काल में राजस्व वसूली करने वाले कलेक्टर, कमिश्नर, सचिव, मुख्य सचिव ने अपने आप को इस देश का असली शासक घोषित कर लिया, जो शासन में बैठकर असली सत्ता सुख-सुविधायें भोगने के साथ ही राजस्व के साथ भूमि और उनके कार्यक्षेत्र की भूमि पर रहने वालों के बेताज बादशाह बन प्रजा और प्रजा की संपत्तियों के दोहन के राजकीय प्रतिनिधि बन बैठे और चारों ओर से दोनों हाथों से धन बटोरने में लगे हुए है। कानून इनकी रखैल, सरकारी संपत्तियां, इनकी बपौतियां, क्षेत्र की जनता, जनधन व जनता की संपत्तियां इनकी दासी है। जब चाहे, जहां चाहे, किसी भी बहाने, अपने सरकारी गिरोह के अमले के साथ कभी सड़कों के चौड़ीकरण के बहाने, कभी स्मार्ट सिटी के बहाने बस्तियां उजाड़े, दादागिरी दिखाने, वैद्य मकान, बाड़े बाजार, कालोनियां, ढहा दे, जनता के विरोध पर लाठीचार्ज करवा दे, हाथ-पैर तोड़ने की धमकी दे, भ्रष्ट पटवारी, तहसीलदारों, सहा. उप जिलाधीशों के साथ हर राज्य व केन्द्र शासन के विभागों में आवंटित कार्यों, योजनाओं में शेरू हिस्सा डकार जाए, सरकारी जमीनों को पट्टे पर बांटना दिखा बाले-बाले ही मोटे धनवालों को बेंच खाये। गधों को प्रधानमंत्री बना दे, चुनावों में जनता किसी को भी वोट दे पर ये बिना गणना किए गणना की नौटंकी कर मन से ही, चाहे गए उम्मीदवार को सत्ता सुख भोगने का अवसर प्रदान कर दें, गुस्सा हो जायें, जीतों को हराकर गधों को मुख्यमंत्री भी बना दे, प्रधानमंत्री मोदी को भी दिल्ली में धूल चटा देते हैं। भारतीय प्रताड़ना सेवा की परीक्षा पास कर ये जीवित दानव देवता होने का स्वांग रचते है। इनके सामने देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सब पानी भरते हैं। कठपुतली बनाकर जैसा चाहते हैं, वैसा नाचते हैं। न नुकुर करने पर प्रसार माध्यमों में केवल राष्ट्रपति को छोड़ चंद मिनटों में ही धज्जियां बिखेर देना इनके बायें हाथ का खेल होता है। देश के इन कुख्यात लूटेरों का ही खनिज, राजस्व, भूमि की अफरा-तफरी, कृषि उद्यानिकी, आदिम जाति, लो. निर्माण, लो. स्वा. यां., जल संसाधन, महिला बाल विकास, परिवहन, पंजीयन, आबकारी, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में जनता से नोंचे गए धन के आवंटन आय में से मोटा हिस्सा डकार विदेशी बैंकों में जमा करवाया गया है, इसलिए मोदी वित्त मंत्री अरुण जेटली की औकात नहीं कि उस पैसे को देश में ले आये या उनकी जांच करवाकर इन पर कानूनी कार्रवाई कर अंदर करवा सकें, ये लॉबी भा.प्र.से. की मोदी की 24 घंटे में पूरी दुनिया में धज्जियां बिखेर देगी, इसलिए विदेश धन पर ये भाजपाई धूर्त कितनी भी नौटंकी करे 400 लाख करोड़ का धन व अन्य बेशकीमती हीरे जवाहरात और स्वर्ण भूषण जो स्व. इंदिरा गांधी के आपातकाल में 700 ट्रक भरकर जयपुर के खजाने से सेना के ट्रको में भरकर विदेश भिजवाये थे, 1974-75 में। अभी तो पूरे देश में ईवीएम मशीन की जालसाजियों से भाजपा की ऐतिहासिक उप्र में जीत का जो मुद्दा छाया हुआ है, उसकी भी ये शूकरों की फौज सबसे बड़ी धुरी है। मशीन में कम्प्यूटराइज्ड कम्पाउंड देने से लेकर, जिसमें कोई भी मतदाता कहीं भी वोट डाले, हर वोट, हर दूसरा वोट अपने आकाओं के उम्मीदवार को ही जाएगा, जिसका निर्देश, दिल्ली से मिला है। फिर मशीनें दस तालों में बंद कर दो बाहर से मास्टरमाइंड सेंटर से कमांड देकर 15-20 दिन में कभी भी बदलवा दो, तीसरे क्रम में गिनती के समय भी पूरी जालसाजी, एक मशीन को स्ट्रांग रूम में लाने साफ करके दिखाने फिर परिणाम दिखाने की किस उम्मीदवार को किस केन्द्र से कितने वोट मिले। इसके बाद सारे टेबलों के परिणाम इकट्ठे करने और उन्हें ऑफिस एक्सेल शीट में टेबल और उम्मीदवार के अनुसार कम्प्यूटर में डाटा भरकर विधानसभा के अनुसार शीट हर राउंड की तैयार प्रति राउंड डेढ़ से दो घंटे लगते हैं। 10 राउंड की गिनती में स्वाभाविक है 15से 20 घंटे चाहिए तो फिर ऑफिस एक्सेल शीट बनाने के लिए कर्मचारी बैठाए जाते हैं। पहले दूसरे राउंड की शीट तैयार होते-होते ही 2 से ढाई घंटे निकल जाते हैं। तब तक ये मन से ही अलग कमरे में बैठकर हाथ से ही इनके चेले उप व सहा. जिलाधीश, शीट में इच्छानुसार वोट दिखाकर घोषित करना शुरू कर देते हैं। फिर चुनावी महोत्सव में एक-एक कलेक्टर से रुपए 5 से 10 करोड़ विभिन्न कार्यों के नाम से हजम कर लेता हैं। इसलिए ये हरामखोरों की फौज सूचना के अधिकार में जानकारी देकर अपनी धज्जियां उड़वाने की अपेक्षा आवेदकों के जवाब देने और अपीलों में हड़का और डांट-डपट कर भगा देती है। न केवल इंदौर, देवास वरन पूरे प्रदेश में और देश में कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मु.का.अ. के तानाशाहीपूर्ण, भ्रष्ट व जालसाजीपूर्ण कार्यशैली से सत्ता के दलाल और चापलूस, भ्रष्ट अधिकारी खुश और ईमानदार अधिकारी कर्मचारी नाराज रहते हैं। बेशक इन बेचारें को भी सत्ता में बैठे मंत्रियों, संत्रियों, अपने वरिष्ठों की न चाहते हुए भी मन और धन से सेवा करनी पड़ती है। तब मनचाही पदस्थापना, सकून और चैन मिलता है। बिना महिना और रायल्टी चुकाये इन्हें भी जन-धन और मक्खन मलाई के ढेर पर मुफ्त में नहीं बैठाया जाता।

प्रधानमंत्री मोदी, मु.मं. शिवराज सत्ता बाप की जागीर नहीं, जो जनता को लूटो-खाओ

सूचना अधिकार में जानकारी देने में घबराहट, बहाने और बत्तमीजियां क्यों?

भारत के लोकतंत्र बनाम लूटतंत्र में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा बनाये गए सारे कानून, यथार्थ में कानून धूर्तों के बनाए शब्दों के मायाजाल है, जो निरीहो के शोषण और अपनों के पोषण के काम आते हैं।यथा सारे सत्ताधीशों ने पट्टे की मिली आजादी में अंग्रेज आकाओं के द्वारा बनाए गए भारतीय गुलामों को हांकने के सारे महत्वपूर्ण कानून यथा भातरीय दंड संहिता 1860, भा. दंड प्रक्रिया संहिता 1890, भूमि सुधार, प्रबंधन आदि यथा स्थिति स्वीकार कर वैसे ही लागू कर चलाये जा रहे हैं। ताकि आकाओं रूपी सत्ताधीश जनता रूपी गुलामों का अपनी मनमर्जी से हांक सके। सत्ताधीश जनता से वसूले गए विश्व में सबसे ज्यादा करों को अपने रिश्तेदारों और मातहतों के हितों में अपनी मनमर्जी से उड़ा खा सकें, जब आधी शताब्दी तक जनता खूब उबलने और सत्ताधीशों को धिक्कारने लगी और विदेशी कं. सत्ताधीशों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध पारदर्शिता के लिए कानून लाने की मांग करने लगी तब यहां के सत्ताधीशों ने पहली बार जनता का आभासी विश्वास जीतने के लिए बड़ी मुश्किल से सूचना अधिकार अधि. 05 बनाकर 12.10.2005 से लागू करने की व्यवस्था की जिसका पिछले 12 वर्षों में गांव की पंचायतों से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय से निम्न जिला व सत्र न्यायालयों तक खूब धज्जियां बिखेरी जाती रही साथ ही सबने इस मात्र 30 धाराओं वाले कानून की व्याख्या करने, अपने आपको बचाने उल्टे-सीधे फैसले देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार रोकने, जालसाजियां, कारगुजारियां पकड़ने से बचने के लिये इन धूर्त हरामखोर जालसाजों ने सरकारी दस्तावेजों को भी व्यक्तिगत जानकारी व तृतीय पक्ष की जानकारी बताकर अपने भ्रष्टाचार लूट और जालसाजी के रास्ते पक्के कर बचने की जुगत जमा ली। सरकार, न्यायालय आदि सभी जानते हैं कि वर्तमान में आरक्षित श्रेणी में कार्यरत 50 प्रश कर्मचारी अधिकारी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। जैसे मप्र के हर विभाग में कार्यरत सारे मीणा फर्जी जाति और मूलनिवासी प्रमाण पत्रों के दम पर नौकरी कर रहे हैं। वर्तमान में इंदौर के खाद्य, नियंत्रक आरसी मीना पूर्व के उपसंचालक कृषि आलोक मीना जो वर्तमान में देवास में है। दोनों के जाति व मूल निवासी प्रमाण पत्र उनके विभागों से मांग गए,वही हाल लो.नि.वि. इंदौर में 8 वर्षों से पदस्थ महाभ्रष्टाचारी हाल ही में लोकायुक्त छापे में पकड़ा गया, सं. परि. यंत्री एपी रामे का भी जाति व मूल निवासी प्रमाण पत्र मांगा गया उनके वरिष्ठ अधिकारियों से तीनों विभागों में वरिष्ठों ने मोटा धन हजम कर जानकारी देने के नाम पर तृतीय पक्ष की वृत्ताकार जानकारी देने से साफ मना कर देते हैं। वाणिज्य कर में भोपाल के दोनों जबलपुर, ग्वालियर, सतना, इंदौर-3 संभाग में बैठे शूकरों को अपनी जालसाजियों और मोटी वसूली के चलते आखिर जानकारी कैसे दें।

मप्र का मुख्यमंत्री शिवराज महाजालसाज सूचना के अधिकार अधि. में बार-बार जानकारी मांगने वालों को धमकाता है। अंधों में काने राजा को तीसरी बार सत्ता क्या मिल गयी सत्ता को बाप की जागीर मान बैठा। हरामखोर चारों तरफ जालसाजियां, भ्रष्टाचार करें और जानकारी मांगों तो कहता है कि सरकार को ब्लैकमेल कर उपयोग करते हैं।

तुम जनता से हर वस्तुओं पर पेट्रोल-

12 वर्ष में हजारों करोड़ हजम कर गए, साधनों की आड़ में पर धारा 4 के अंतर्गत किसी भी प्र.मं., मु.मं. से लेकर नीचे तक किसी ने भी पूरी जानकारी क्यों नहीं डाली? मु.मं. शिवराज कहा है कि सू.अ. के आधार पर पत्रकार ब्लैकमेल करते हैं तो चौहान ये भी बतायें कि स्वयं और अन्य ब्लेक कुकर्म करते क्यों हैं। ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात करने वाली देश, देश की जनता, देश के साधनों का भयंकर शोषण कर अपना धन कहां निवेशित किया?

डीजल में 3 प्रश वेट वसूलने के बाद भी रुपए 5 प्रति लीटर की अतिरिक्त वसूली कर अरबों रुपए प्रतिदिन बटोरो अपनी मौज-मस्ती लूट में कमी आए तो शूकरों, दानवों, बाजार से ऋण लेकर घी पियो और कुछ बिरले अपनी जान जोखिम में डालकर खर्च किए पैसे की जानकारी मांगे तो सार्वजनिक मंच से चिल्ला कर स्वयं सिद्ध करो कि हम भ्रष्टाचारी जालसाज, अपराधी हैं, इसलिए सूचना के अधिकार में जानकारी देना हमारे लिए ब्लेकमेलिंग की श्रेणी में आता है और हमें लोग ब्लेकमेल करते हैं। इस शब्द के कई सारांश निकलते हैं। पहला कि हम जनधन से भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी और जालसाजी करते हैं। इससे सूचना के अधिकारर में जानकारी देना हमारे लिए ब्लेकमेलिंग बन जाता है। दूसरा सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने वाले से हमें भारी डर लगता है। हम वो नामर्द हैं। शादी दिखाने के लिए तो कर लेते हैं। ताकि नामर्दों की श्रेणी में न गिनती हो, तीसरा सत्ता और कानून इनके बाप की जागीर है, ये जनता से मनचाही वसूली और लूटपाट करें, करों से, शुल्कों से, पर जनता इनसे ये भी न पूछे कि उस धन को कहां और कैसे खर्च किया। चौथा सरकार कमाई की व्यवस्था करे न करे जनता की, पर उसके खून पसीना बहाकर की गई कमाई को जरूर लूटने के लिए नगदी हीन व्यवस्था पर केन्द्र व राज्यों का 80 प्रश पेट्रोल-डीजल व अन्य अनेकों माध्यमों से लूटकर हरामखोर जालसाज, डकैतों की फौज विदेशों में रंगरैलियां मनाए, लाखों-करोड़ के अपने फोटो के साथ अपने विज्ञापन छपवायें, पर इनसे सूचना के अधिकार में ये भी न पूछा कि कितना कहां खर्च किया। पांचवा- नोटबंदी से 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, नोटबंदी क्यों की गई तो मात्र 5 राज्यों के चुनाव जीतने विरोधी पार्टियों के पास जो धन है उसे मिट्टी का ढेर कर उनके खर्च करने की शक्तियां समाप्त करने के लिए। सैकड़ों लोग लाइन में खड़े-खड़े मर गए, लाखों बीमार हो गए, पर इनसे नोटबंदी से हुए फायदे नुकसान की जानकारी मत मांगों अन्यथा देशद्रोही की श्रेणी में रखेंगे ये। छठवां- हमारे प्रदेश का धूर्त मुख्यमंत्री शिवराज नर्मदा यात्रा के बहाने जनता का हजारों करोड़ खर्च कर दे, जबकि ये नर्मदा यात्रा नहीं यथार्थ नर्मदा को खोखली करो यात्रा है। क्योंकि इस बहाने वो अपने और अपने रिश्तेदारों के छह सौ डंपरों के लिए किस-किस जगह से रेत निकाली जा सकती है इसका मंथन कर रहा है। बाद में नर्मदा के किनारे के उन घाटों के जिलों से छोटे-छोटे खनिज और वन विभाग से पट्टे लेकर रेत निकाल कर बैचे। यदि यह जानने के लिए कि नर्मदा यात्रा पर कितना जन-धन बर्बाद किया तो ब्लेकमेलिंग की श्रेणी में या दुरुपयोग की श्रेणी में आ जाएगा, है दानव शिवराज चौहान तुम कर्ज लेकर घी पियो चुकाने के लिए जनता के सिर कर्ज थोपो, जानकारी मांगो तो कानून का दुरुपयोग करते हैं यह लोकतंत्र नहीं लूटतंत्र है जनता से लूटो और अरबों रुपए बिजली से, खनन से, लो.निव्र., लो.स्वा. जल संसाधन, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य, अंत्यावसायी, शिक्षा वनों आदि के नामों से हजम कर जाओ, पर सूचना के अधिकार का भी उपयोग न करो हैजन ऐसे अनेकों बिंदू हैं। जो इन सत्ताधीश दानवों की नोंच-खंसोट, भ्रष्टाचार और जालसाजियों के यथार्थ का कच्चा चिट्ठा हैं।

फिर है सत्ताधीश दानवों, यदि आप ईमानदार तो नहीं, पर यदि स्तरीय बेईमान भी हैं तो भी जब इस कानून की धारा 4 में 17 बिंदुओं की हर विभाग की जानकारी इंटरनेट साइटों पर 12.10.05 को डाली जानी चाहिए थी जो 10 वर्ष बाद भी क्यों नहीं डाली गई क्योंकि भ्रष्टों को जनता से या सूचना के अधिकार से नहीं वरन अपने किए हुए कुकर्मों से ज्यादा भय लगता है। आप तो सत्ताधीश है। जब आप अपने लूट और भ्रष्टाचार के कुकर्मों से इतने भयभीत हैं,जो मंच से चिल्ला-चिल्ला कर अपने भय को प्रदर्शित करने के साथ उल्टे ही आम सूचना अधिकार में जानकारी मांगने पर दोषारोपण कर रहा है, तो तुम आमजन भय, भूख से कैसे निजात दिलवाओगे। सोचो स्वयं कि तुम सत्ता पर 11 वर्ष से कुपात्र होने के बाद, भी बैठे हों, क्योंकि जनता अपने ही दो वक्त की रोटी की लड़ाई से मुक्त नहीं हो पा रही है। वह कभी का सत्ताप्च्युत कर चुकी होती।

कृषि अधिकारी कर्मचारी कल्याण व विकास विभाग

धूर्त डकैतों की फौज प्र.स. संचालक सं.सं., उ.सं. से ग्रा.कृ.वि.अ. तक

मप्र कृषक कल्याण व कृषि विकास यथार्थ में मु.मं., मंत्री बिसेन, प्र.स. राजेश राजौरा से मोहन लाल मीना से लेकर प्रदेश के संभागों में बैठे सभी संयुक्त संचालक, जिलों के उपसंचालकों से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक बैठे सभी ग्रा.कृ.वि. अधिकारी तक सबका एक मात्र उद्देश्य अपने स्तर पर केन्द्र व राज्य शासन 30 से ज्यादा योजनाओं में जिसमें हर जिले को 500 से रुपए 1000 करोड़ तक मिलता है। कागजों पर कृषकों के कल्याण के नाम पर, कृषि विभाग के कर्मचारी और अधिकारी स्व विकास और कल्याण करते है। इसके लिए आवश्यक है कि हर पद पर चुन-चुनकर भ्रष्टों को भाटक और महीना वसूली के आधार पर मंत्री और मु.मं. नियुक्त और पदस्थापना करते हैं। जो खूब कमायें, खायें और समय पर महीना पहुंचायें आखिर प्र.स. राजेश राजौरा जिसके भ्रष्टाचार और लोकायुक्त प्रकरणों में छाये रहे आखिर क्यों मु.मं. चौहान 3 वर्ष से ज्यादा समय से एक हीविभाग में बैठा रखा है। मोटा खाओ और खिलाओ सूत्रों से प्राप्त समाचारों के अनुसार हर स्थानांतरण व पदस्थापना में रुपए 10 लाख से लेकर 40 लाख तक पद और आवंटन के अनुसार उपसंचालकों को नियुक्त किया जाता है। विभिन्न जिलों के उपसंचालक पद पर वहीं हाल संयुक्त संचालकों का है। जिन पर उपसंचालक रहते जन-धन के गबन के प्रकरण बनाये थे जांचे बंद कर उन्हें धन लेकर संयुक्त संचालक बना दिया गया उसमें एक सं.सं. सिसौदिया भी थे, इसलिए सूचना के अधिकार में न स्वयं अपने कार्यालय की जानकारी देते है न दूसरे उपसंचालकों और जिलों में जबकि ये 6 आदिवासी जिलों जिनमें न केवल कृषि वरन आदिवासी विकास के नाम पर भी रुपए 1000 से 1500 करोड़ का विकास खंडों के आधार पर आवंटन मिलता है। महीना पाकर धन्य हो, सबकी जानकारी देने में बहुत ज्यादा जानकारी है, स्टॉफ नहीं है क्या करोगे? हमारे रहते तक आप जानकारी मत मांगना, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब तो सारा कार्य कम्प्यूटर से होता है। कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है कि निरर्थक दलीलें देकर अपीलों की सुनवाई में भी चालाकियां भी जालसाजियों को बचाने के लिए

सूचना के अधिकार में जानकारी न देने, अनेकों नौटंकी हर स्तर पर

की जाती है। पर जानकारियां देने से ये हरामखोर, जालसाज बचने और बचाने की तैयारी करते है। जबकि खरगोन में रहकर इस जालसाज ने बीटी कॉटन के 300 रुपए के पैकेट को रुपए 1300 से 1500 तक बिकवाकर एक तरफ किसानों में युद्ध करवाया तो दूसरी तरफ हर पैकेट पर रुपए 1000, 1200 तक की लूट करवाकर विक्रेताओं और डीलरों से प्रति पैकेट रुपए 200 से 300 तक की वसूली स्वयं ने कर ली, फिर केन्द्र से कृषक कल्याण के नाम पर बैलगाड़ियां व बैलों की खरीद से लेकर किसानों की जानकारी देने के लिए मुद्रण तक का पैसा तक आता है। यह खेल हर जिले में होता है। जिसमें न केवल फर्जी यात्रा बिलों से, चिकित्सा देयकों से कर्मचारी तक पैसा डकारा जाता है। जबकि अनेकों कर्मचारियों ने जिले के बाहर कदम तक नहीं रखा होता है। पर उनका मुंह बंद रखने उनको ऐसे उपकृत किया जाता है। फिर भ्रष्टचार और जालसाजियों के विशेषज्ञ कर्मचारियों की भी भारी पूछ-परख होती हैं। वर्तमान में इंदौर के उपसंचालक पटेल बहुत सयाने हैं। अर्थात घोर जालसाज,उज्जैन में उपसंचालक थे तब भी सूचना के अधिकार जानकारी देने में नियमों-कानूनों के अड़ंगे लगाकर जानकारी देने से बचते थे। इंदौर में आकर भी वही रणनीतियां अपनाए हुए हैं। जवाब में पत्र भेजकर हरामखोर लिखता है। जानकारी बहुत ज्यादा है आकर देख लो, तो फिर बहानेबाजी, उस पर भी ईमानदारी से मैं तो देना चाहता हूं पर स्टॉफ नहीं है। पर भ्रष्टाचार जालसाजी करने के लिए सेंगर जिसकी पदस्थापना धरमपुरी में है। दूसरा भटनागर जिसकी देपालपुर में पदस्थापना होने के बाद जालसाजी और भ्रष्टाचार विशेषज्ञों को इंदौर कार्यालय में संलग्न कर रखा है। सेंगर को महीनों से। फिर देपालपुर से सं.सं. से भटनागर के भी आदेश करवा लिए ताकि अपनी गर्दन न फंसे जबकि दोनों का वेतन पदस्थापना वाले स्थानों से ही निकलता है। अभी बीटी कॉटन की बिक्री व वितरण होना है। ऐसे अनेकों कर्मचारी है। जो फर्जीवाड़े और जालसाजी के साथ वसूली की विशेष योग्यता के कारण जिला कार्यालयों में पूरे मप्र में बैठाये जाते हैं। जिनकी पुख्ता जानकारी सं.सं. संचालक और प्र.स. को भी रहती है। पर जब भगवान को भी खाने और खिलाने वाले भक्त ही पसंद आते हो तो ये तो बेचार मु.मं., मंत्री, प्र.सं., संचालक उपसंचालक है तो साधारण मनुष्य ही न फिर जब सब खाने वाले बैठे हो तो कैसी जालसाजियां, भ्रष्टाचार कैसा कृषक कल्याण।

दंत चिकित्सा महाविद्यालय

इंदौर के प्राचार्य देश राज जैन जिन्होंने जालसाजी से पद हथिया लिया तो फिर हर कदम पर जालसाजियां और भ्रष्टाचार करना, पैसे के लिए विद्यार्थियों को फेल करना, बाहर के चिकित्सा निजीकरण महाविद्यालयों के विद्यार्थियों से मोटा धन लेकर अपने शास. विद्यालयों में इंटर्नशिप करवाना, मोटी खरीदी में मोटा कमीशन खाना, नए कॉलेज भवन के लिए पुराने 6 करोड़ के प्राक्कलन को रद्द कर नया 25 करोड़ की डीपीआर बनवाना, मन से ही बिना विज्ञापन बिना उचित चयन प्रक्रिया के मर्जी से 8-10 कर्मचारियों की भर्ती कर नियमित वेतन निकालन, वही हाल लेक्चरर की भर्ती में भी किया गया और 8-10 लेक्चरर भर्ती कर लिए गए। इसलिए में इसकी चापलूसी न करने वालों को दूसरों से शिकायत लेकर उनको कारण बताओ नोटिस जारी करना, जांचे बैठाना, अपना सिक्का चलता रहे, इसलिए एक-दूसरे को लड़वाना , इनकी फितरत है। सूचना अधिकार में अपील के बाद आदेश जाने के बाद भी महीने तक पत्र ही नहीं मिला कि दलीलें देता रहा, विद्यार्थियों से प्रायोगिक परीक्षा में वसूली करना अन्यथा परिणाम बिगाड़ने से अनेकों विद्यार्थी वर्षों से अटके पड़े है।

साप्ताहिक समय माया

नीले वीडियों की अपलोडिंग, हम नहीं रोक सकते- न्यायालय

अवयस्क विवाह अवैध, अवयस्क यौनाचार वैध

स्वास्थ्य विभाग स्कूलों में कंडोम बांट बाल यौनाचार को तो प्रोत्साहित करता है, टीवी, इंटरनेट, मोबाइलों पर नीले यौनाचार दृष्यावली पर आंखें मूंद लेता है, अवयस्क विवाह के लिए पुलिस, महिला बाल विकास, प्रशासन सब ही रूकवाकर बहादुरी दिखाते है

वर्तमान का प्रचार, संचार माध्यमों में अपने व्यवसाय बढ़ाने, विज्ञापनों के प्रदर्शनों में खुलकर नग्नता, यौनाचार परोस 10 से 15 वर्ष की युवा पीढ़ि को भारी 24 घंटों 7 दिन उत्तेजित कर यौनाचार की तरफ धकेलना, यौनाचार कर कामाग्नि शांत करने, विवश होते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय व विभाग सब समझते है। सहशिक्षा स्कूलों में पढ़ने वाले 95 प्रश छात्राएं की 90 प्रश आपसी गप्पों, यौनाचार के अतिरिक्त कोई मुद्दा नहीं होता है।चले जाइए स्कूलों में और विद्यार्थियों से एंड्रायड मोबाइल को जांचिए 95 प्रश मोबाइलों में नीली फिल्में मिलेगी, स्वाभाविक है बढ़ती उम्र में यौन उत्तेजतना को बढ़ाने वाले सारे साधन मौजूद होते होने के साथ फिर टीवी पर चलने वाले विज्ञापनों में चलने वाले धारावाहिक कार्यक्रमों में यौनाचार ही बिक रहा है। जो युवा पीढ़ी को यौनाचार की तरफ धकेल 12-15 वर्ष की छात्रायें अपनी उत्कंठाएं पूरी कर रही है। जिनके लाखों वीडियो यूट्यूब पर, मोबाइलों पर चल रहे हैं। सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय भी स्कूलों में निरोध के फुग्गे बांट रहे हैं, परंतु बाल विवाह का नाम सुनते ही भुखेरे श्वानों की भांति महिला बाल विकास, पुलिस और प्रशासन दौड़ पड़ता है। रोकने के लिए और स्पष्ट संदेश देता है कि बाल नहीं वरन अवयस्क विवाह कानूनी अपराध हैं और शादियां तुड़वा देता है। परंतु 12, 15, 17 की उम्र में स्वच्छंद यौनाचार अवश्य चलेगा, शिक्षक सहपाठियों से लेकर किसी से भी निरोध लगाकर संबंध बनाना चलेगा, पर ये भी क्या बात हुई कि छोटी उम्र में भी तुम शादी करके केवल एक की होकर रह जाओ। नहीं इस उम्र में जो अच्छा लगे या जिसको तुम अच्छी लगो उससे सहमति से संबंध बनाओ कोई तकलीफ किसी को नहीं पर अवयस्क उम्र में एक से शादी कर, एक के ही घर में चली जाओ, नहीं यह तो अवैध है, वह भी मात्र हिन्दुओं के लिए, हिन्दू फिर निहायती डरपोक कौम न केवल कानून से डरे, समाज से डरे, इसलिए आप की लड़की अव्यस्क यौनाचार तो चोरी छीपे कर सकती है बस समाज में अव्यस्क उम्र में शादी नहीं कर सकती अन्यथा मां-बाप से लेकर पंडित, केटरिंग वाला, बारातियों,

घरातियों के साथ सब अवैध विवाह के चक्कर में हवालात पहुंचा दिए जाएंगे, भाग जाए, साथी के साथ बिना विवाह के सारे भोग करना चल सकता है। जबकि यही मीडिया, महिला बाल विकास, पुलिस और प्रशासन मुस्लिमों में होते अव्यस्क विवाहों को न तो पकड़ने दौड़ता है न विवाह रोकता है। क्योंकि वहां जाने की हिम्मत ही नहीं, अगर वहां जाएंगे तो वहां पर रिश्ते-नातेदार घेरकर उनकी पिटाई कर देंगे। वहां ये सब बहादुर सिंग इन सबको गीदड सिंग बना देंगे।

इसके दूसरी ओर बढ़ती उम्र में विगत जो 30-35 वर्ष की उम्र में विवाह होने का एक फैशन सा चल पड़ा है। जिसके मूल में देखा जाए तो तो जो स्त्री-पुरुष 12-15 वर्ष की उम्र में अपने शालेय शिक्षा में सारे यौनाचार कर चुका हो, वह उसे 30-35 की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते शादी करने पर क्या देगा? न वो भावनायें न वो गर्मजोशी न एक-दूसरे के प्रति लगाव केवल एक छत के नीचे रहने वाले एक-दूसरे की आवश्यकताओं का समझौता, बात-बात में विचारों का टकराव, विवाद और तलाक। जबकि अव्यस्क उम्र में 70-80 के दशक तक हुई शादियां में अधिकतम 2-5 प्रश अलगाव और विवाह विच्छेद के बिरले मामले आते थे, परंतु 25 से 30 उम्र में हुए विवाहों में ये 20 प्रश तक आने लगे और 30-35 की उम्र में हुए मामलों में ये विवाह विच्छेद 25 से 35 प्रश तक आने लगे और होने लगे तो आखिर क्यों। सीधा सा गणित 15 वर्ष की उम्र से 30 की उम्र तक अनेकों से शारीरिक और मानसिक संबंध बने और बिगड़े, अब स्थाई संबंधों की जंजीरों में घुटन होने लगी, और विवाह विच्छेद होना एक आम और सामान्य समस्या बनकर रह गया, इसके विपरीत जिस अव्यस्क उम्र में शादी से ज्यादा एक हम उम्र साथी और दोस्त मिलना जिससे मानसिक और शारीरिक संतुष्टि मिलने का अहसास जीवन पर्यन्त रिश्तों को हर ऊंच-नीच के साथ दुख-सुख में साथ निभाने का दायित्व बोध स्त्री-पुरुष को बांधे रखता था, इसी बीच बच्चों को जन्म जहां पुरुष को पिता होने और समाज में एक जिम्मेदारी का बोध कराता था, वहीं स्त्री को उसकी मां होने की अनुभूति और कुटुम्ब में, समाज में मां होने के साथ उसकी गरिमामयी स्थिति का आभास कराती हैं। पर जब विवाह ही 30-35 वर्ष में हुआ तो उसकी समाज और कुटुम्ब में वह गरिमामयी स्थिति तो दूर यथार्थ में न केवल माता-पिता के दिलों-दिमाग में, उच्च श्रृंखलता का अहसास समाज और कुटुम्ब में भी करवाते है। ज्यादा पढ़-लिख जाने, ज्यादा पैसा कमाने, अच्छा पद प्राप्त कर लेने से ह्दय से कोई भी सम्मान नहीं देता, जो स्त्री-पुरुष के माता-पिता बनने के बाद मिलता है। पद और पैसे की प्रतिष्ठा में आप जी लीजिए जिस अहं और मौज मस्ती में आप जीना चाहे, पर पीठ पीछे आपके बारे में होती चर्चा में संबंधों को लेकर आपको संत्रास तो देती रहेगी।

वर्तमान में चल रहे टीवी, इंटरनेट, मोबाइलों पर नीली फिल्मों के यौनाचार यदि सरकार नहीं रोक सकती, बेशक यह एक दुष्कर कार्य है। स्कूलों में सह शिक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच इस यौन उत्तेजनापूर्ण माहौल में यौनाचार अव्यस्कों के बीच नहीं रोका जा सकता है, बेशक वातावरण यौनाचार की उत्कंठा को पूर्ण करता है, परंतु स्कूलों में कंडोम बंटे न बंटे, सभी शहरीय विद्यालयों से लेकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्यार्थी यौनाचार में निरोध आदि प्रयोग करते है। पर इस बाल वैश्यावृत्ति को प्रोत्साहित करने की अपेक्षा बेहतर होगा कि बाल विवाह तो नहीं कहा जा सकता। अव्यस्क उम्र में विवाह की खुली छूट होती समाज की बर्बादी रोकी जाए, वैसे भी शिक्षित वर्ग में तो बाल विवाह की तो दूर विवाह की उम्र बढ़कर 30 के आसपास पहुंच चुकी है। 50 प्रश बच्चो 30 की उम्र के बाद महिलाएं अपने या पति के निचुड़ जाने या वीर्य में शुक्राणु के अभाव में या 15-30 की उम्र तक महिलाएं इनते गर्भनिरोधकों, गोलियों, गर्भपातों के कारण प्राकृतिक जनन खो चुकी होती है। गर्भाशय में विकारों के कारण या बांझ रह जाती है। या चिकित्सीय माध्यमों से मां बनने के लिए विवश होना पड़ता है। जिस पर अब परखनली, शिशु चिकित्सा से बच्चे पैदा करने की व्यवस्था सरकारी चिकित्सालयों में जन-धन का उपयोग करने की घोषणा कर चुकी है।

विवाह की उम्र में विवाह न करने दो सरकारी जन-धन की होली जलाकर बहादुरी दिखाते हुए अव्यस्क विवाह रोको। जब आधी उम्र निकल जाए तो बच्चे पैदा करने जैसी नेसर्गिक आवश्यकता को पूरा करने के गैर पति के बीजाणु पत्नी कोख सिंचित कर पालो, वहा री सरकारों और नीति नियंताओं कानून बनाने वालों।

इलेक्ट्रानिक वोट मशीन की जालसाजियों से हथियाई उप्र, उत्तराखंड, बदले में पंजाब

तानाशाह रक्त पिपासु मोदी निचोड़ देगा जनता को हर तरह से

उप्र जीतते ही रेल किराया, पेट्रोल, डीजल, गैस, विद्युत व अन्य सब की कीमतें बढ़ायेगा, मीडिया पर, अंबानी का कब्जा, पहले नोटबंदी से, अब जीएसटी, आधार कार्ड, केशलेस से तबाह करेगा 40 करोड़ से ज्यादा को

भारत का लोकतंत्र यथार्थ में लूट व जालसाज तंत्र बन चुका है, लोकतंत्र को भले ही चुने हुए नेता चलाते हुए दिखते हैं पर ये अकल के पैदलों को यथार्थ में चलाने वाले होते है, सत्ता के असली शासक भारतीय प्रशानिक बनाम प्रताड़ना सेवा के अधिकारी जो कि परिक्षायें उत्तीर्ण कर 35-40, 45 वर्ष तक सत्ता में बैठे चुनकर आए पैदलों को प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर पंचायतों तक इन्हीं का साम्राज्य होता है। वो खुश तो काहे की चुनावी नौटंकी, जिसे मन चाहेगा हरा देंगे, जितायें इलेक्ट्रानिक वोटिंग, पूरी जालसाजी है। पूरा खेल वोटिंग मशीन में दी गई कमांड का है, जैसे 7 बजे परीक्षण के समय परिणाम बराबर जो डाले वो दिखाये 8 से 11 के बीच बटन कोई सा भी दबे हर दूसरा वोट मनचाहे याह जिसे जिताना है उसके ही जाएगा। अंत में भी कम्प्यूटर से मशीन में जितने वोट डले वो संख्या स्थिर रहेगी पर सारी मशीनों के वोटों लेपटॉप या कम्प्युटर से यहा-वहां शिफ्ट कर सकते हैं। फिर इतनी बड़ी मशीन में रिमोट से ब्लूटुथ, जीपीआरएस,वाई-फाई, डब्ल्यूएलएल से भी कोड एक्टीवेट करके कुछ भी किया जा रहा है। साथ ही अंतिम वोटो की गिनती के समय ऑफिस एक्सेल सीट नहीं बनाई जाती है। एडीएम, एसडीएम, कलेक्टर घोषणाये करते रहते हैं। जिसे मैंने अपनी आंखों से लोकसभा चुनावों में देखा है। मोदी ने षड़यंत्रों की रचना नोटबंदी से शुरू कर दी थी। जिसमें यूपी के बदले पंजाब देना था, फिर आईएएस लॉबी दिल्ली से चलती है न कि राज्य सरकारें चलाती हैं। भा. प्रताड़ना सेवा का अधिकारी खुश तो देशभर में भाजपा की सरकार बनवा देता है। वरना दिल्ली में धूल चटा देता है। यह बात सर्वोच्च न्यायालय के समझ में भी आ चुकी है। इसलिए उसने सरकार को मजबूर किया कि यूपी में जहां ईवीएम के साथ में वीवीपीएटी (वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) की तकनीकी व्यवस्था मतदान में करें, यूपी में जहां ईवीएम के साथ में वीवीपीएटी की व्यवस्था की गई थी उसमें भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मोदी की सुनामी में हार गए। अब भविष्य में उप्र की सत्ता हाथ आते ही रेलवे की निजीकरण की योजनाएं विद्युत कं., सड़क परि., डिपो, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़कें, पानी सेवा, अपने पूंजीपतियों को सौंपने की तैयारी के साथ ही सभी शासकीय सेवाओं दरों यथा पेट्रोल, डीजल, गैस, बैंक सेवायें आदि सबकी कीमतों बढ़ाकर लूटमार में बढ़ोत्री कर दी जाएगी, **(शेष पेज 9 पर)**

सबसे ज्यादा बेनामी संपत्ति नेताओं, मंत्रियों, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, उद्योगपतियों, दलालों और बड़े समाचार पत्र मालिकों के पास

बेनामी संपत्ति पर 7 साल की सजा, पहले जेलों और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाओ

यथार्थ में सजा मिलने लगी तो कम से कम 10 करोड़ लोगों को जेल भेजा जा सकता है, पर निर्णेयों में विलंब और भ्रष्ट आयकर अधिकारियों से 90प्रश कालेधन वालों का कुछ नहीं बिगड़ेगा

भारत में दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक, सामुदायिक तंत्र या कम्युनिस्ट राष्ट्रों की अपेक्षा सबसे ज्यादा कानून, सबसे बड़ा लिखित संविधान होने के उपरांत भी यथार्थ में जनता को कोई सीधे अधिकार नहीं है कि वो भ्रष्ट जालसाज सत्ताधीशों जिसमें जनता द्वारा चुने हुए या जालसाजी से हथियाई सत्ता के सत्ताधीश मंत्रियों और उसमें बैठे महाधूर्त आईएएस अर्थात इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के अधिकारियों की जालसाजियों, चालबाजियों और भ्रष्टाचारों के विरुद्ध कुछ कर सके, करने की तो दूर उल्टे ही ये सत्ताधीश डकैत शूकरों का गिरोह, जनता को निचोड़ने उसका हर तरह से दोहन करने के लिए कानूनों पर कानून बनाकर लादते रहते हैं। जबकि 99 प्रश कानून जनता के मध्यमवर्गीय लोगों को लूटने के काम आते हैं। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को क्योंकि बड़ा मानता नहीं और छोटा जानता नहीं, जबकि पुलिस और सरकारी अधिकारी कर्मचारी वास्तविक अपराधियों को स्वयं संरक्षण देकर कमाई का साधन बना, पालते, पोसते है। दूसरी ओर दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां सत्ता में बैठे नेता मंत्री स्वयं ही अपराधी होने के उपरांत भी किसी भी कानून को बनाने से पहले जनता से बुद्धिजीवियों से सलाह और वास्तविकता जानने की कोशिश नहीं करते। भले ही वो स्वयं अंगूठा टेक, अनपढ़ या विषय विशेषज्ञ हों न हों परंतु कानून बनाकर थोप देते हैं। जिस पर सत्र न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मानने और पालन करवाने के लिए न केवल बाध्य हैं। वरन् सत्ताधीशों के पूंजीपतियों के इशारे पर नाचने के लिए बाध्य है। हाल ही में राष्ट्रपति से हस्ताक्षरित नया बेनामी संपत्ति पर 7 वर्ष की सजा का नया कानून देश की जनता पर थोपा गया है। बेशक इस कानून में भी कानून बनाने वालों ने अपने आपके कुकर्मों को छुपाने बेनामी काले धन से चुनाव लड़ने की नौटंकी करने वाले धूर्त सत्ताधीश मंत्रियों नेताओं और सत्ताधीशों ने अपने आपको बचाने के लिए ढेर सारे रास्ते छोड़े ही होंगे। क्योंकि इस कानून को बनाने वाले सत्ताधीश मंत्री, नेता, सांसद और उनके मुख्य सलाहकार, सरकार को हांकने चलाने वाले महाधूर्त महाडकैत, महाभ्रष्टाचारी देश के असली खुदा सत्ता में 30 से 40-45 वर्षों तक कुंडली मारकर अजगर की तरह लिपटे रहने वाले इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी, **(शेष पेज 8 पर)**

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958, इंदौर कार्यालय- मोबा. 9425125569